R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 10
16 से 28 फरवरी 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

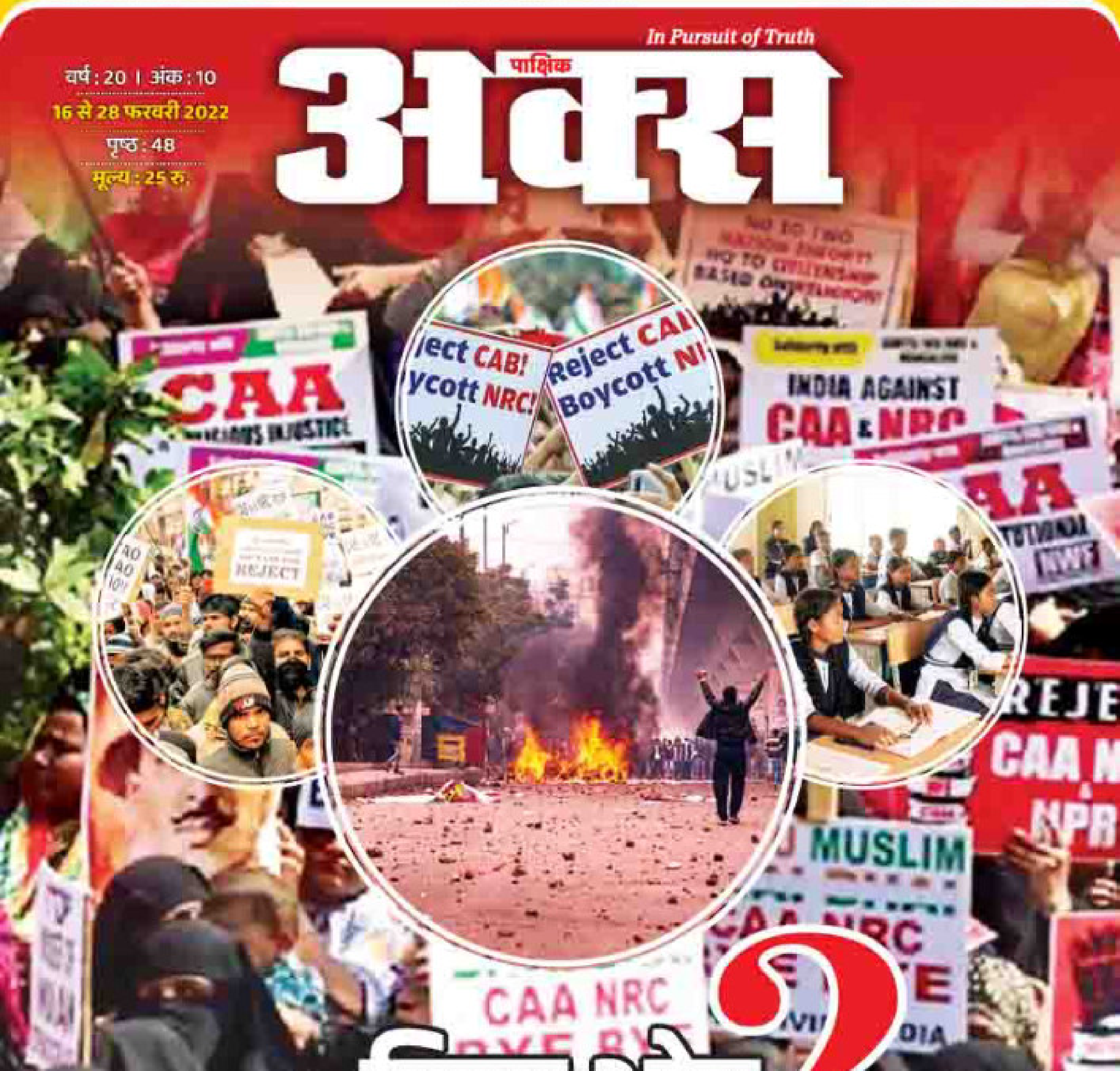

किस ओर जा रहा देश...?

हिजाब हो या न हो... शिक्षा हमारा अधिकार है!

7 साल की शांति में... अशांति का किसका प्रयास?

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

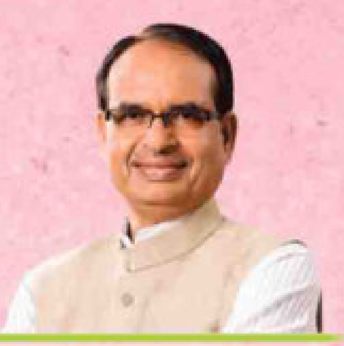

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश प्रथम

लगातार तीसरे वर्ष मिली उपलब्धि

जितनी स्वस्थ होगी माता, उतना ही बेहतर होगा नौनिहाल का भविष्य। माताओं और बहनों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए हमने कई योजनायें प्रारंभ की हैं। आप सभी उनका अधिक से अधिक लाभ लेकर स्वयं को स्वस्थ रखें और परिवार को भी खुशहाल रखें।

-शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

अब तक कुल 23, 58,731 गर्भवती महिलाओं को 995.08 करोड़ रुपए का भुगतान

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

उद्देश्य: गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद सहायता प्रदान करना ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात् उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सकारात्मक सुधार लाना।

पात्र हितग्राही

प्रथम प्रसव वाली गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं

प्रथम किश्त : गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन : रुपए 1000/-

द्वितीय किश्त : गर्भावस्था के 06 माह के अंदर कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जाँच होने पर : रुपए 2000/-

तृतीय किश्त : बच्चे के जन्म का पंजीकरण तथा बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर : रुपए 2000/-

कुल देय राशि : रुपए 5,000/-

योजना का लाभ लेने हेतु-

अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र/ बाल विकास परियोजना अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास से संपर्क करें।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना

उद्देश्य : उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान, सुरक्षित प्रसव, शिशु जन्म पश्चात जच्चा एवं बच्चा के टीकाकरण व स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना ताकि माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा सके।

पात्र हितग्राही

गर्भवती माता 18 वर्ष से अधिक आयु की हो, संबंधित महिला असंगठित कर्मकार में पंजीकृत हो अथवा पंजीकृत असंगठित मजदूर की पत्नी हो, शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में एवं प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जावेगा।

प्रथम किश्त : गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक / एएनएम. द्वारा 4 प्रसव पूर्व जांच कराने पर : रुपए 4000/-

द्वितीय किश्त : शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने, नवजात शिशु को संस्थागत जन्म उपरांत शीघ्र स्तनपान व पंजीयन कराने पर तथा शिशु को 0 डोज बीसीजी, ओपीवी व हेपेटाइटस बी टीकाकरण कराने पर देय होगी : रुपए 12000/-

कुल देय राशि : रुपए 16,000/-

योजना का लाभ लेने एवं आवेदन हेतु-

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय को आवेदन किया जा सकता है।

D-19507/21

कोरोना पर विजय पाना है, टीका जरूर लगवाना है।

इस अंक में

मास्टर प्लान

9 | विवादों का मास्टर प्लान

राजधानी का मास्टर प्लान एक बार फिर विवादों में फंसता जा रहा है। गौरतलब है कि विवादों के कारण राजधानी में मास्टर प्लान केवल कागजों में ही बनता रहा है। अब मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप में बड़े तालाब के कैचमेंट में बसे...

राजपथ

10-11 | 20 लाख घंटे का समयदान

2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अधिक वोट प्रतिशत पाने के बाद हार का सामना करने वाली भाजपा सत्ता में आते ही मिशन 2023 के लिए जुट गई थी। मिशन 2023 में कांग्रेस का सूपड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री...

मप्र कांग्रेस

14 | अकेले पड़े कमलनाथ!

महज 15 महीनों में अपनी सरकार से हाथ धो बैठी मप्र कांग्रेस में अभी गुटबाजी कम होते नहीं दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मिशन-2023 को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। इसके लिए 1 फरवरी से घर चलो, घर-घर चलो अभियान का आगाज किया गया है।

अवैध खनन

19 | खनन माफिया पर कानूनी नकेल

मप्र में भू माफिया, ड्रग्स माफिया, अपराधियों, तस्करों पर नकेल कसने के बाद अब शिवराज सरकार ने खनन माफिया के साम्राज्य का खात्मा करने के लिए कठोर कानून का पहरा बैठा दिया है। सरकार ने मप्र खनिज अवैध परिवहन, भंडार नियम 2022 को हरी झंडी दी है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

कोई क्या पहनता है? क्या खाता है? इस पर फैसला करने का अधिकार ना समाज को मिला है, ना धर्म को मिला है, ना जाति को मिला है, ना किसी संस्था को मिला है। भारत का संविधान कहता है कि कोई क्या पहनता है और क्या खाता है... जैसे सवालों का जवाब व्यक्ति का निजी अधिकार है। निजता के अधिकार के तहत संविधान के अनुच्छेद-21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के तौर पर शामिल है। फिर हिजाब को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है।

37

40

44

45

राजनीति

30-31 | विपक्ष होने लगा जागरूक

बजट सेशन में विपक्ष की आवाज का असर देखने को मिला है। बड़े दिनों बाद विपक्ष की खामोशी टूटती नजर आई है। सोशल मीडिया पर भी लोगों के रिएक्शन पर गौर करें तो वे भी विपक्षी नेताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देते नजर आए हैं। सत्तापक्ष की तरफ से विपक्ष...

महाराष्ट्र

36 | मौखिक निर्देश पर फंसती नौकरशाही

एक लोकतांत्रिक देश को ठीक से चलाने के लिए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश के भाग्य विधाताओं ने काफी सोच-विचार करके ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका आदि का गठन किया होगा। इनके चयन और चुनाव की प्रक्रिया तय की गई होगी। गलतियां होने पर उन्हें सुधारने...

बिहार

38 | वंश वॉर

वैसे बिहार में राजनीतिक मर्यादाओं को ताख पर रखने का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। लालू परिवार के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं। हालांकि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के बयान सरकस्टिक होते हैं, लेकिन इन दिनों लालू के बोल बेहद निजी...

6-7 अंदर की बात
39 पड़ोस
40 विदेश
42 यादें
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

....नौ दिन में चले अढ़ाई कोस

गत दिनों सोशल मीडिया पर ये पंक्तियां पढ़ने को मिली...

पुलिस आयुक्त प्रणाली में कब दिखेगा जोश
अभी तक नौ दिन में चले अढ़ाई कोस....

अगर राजधानी भोपाल की पुलिस आयुक्त प्रणाली के अब तक के कार्यकाल का आंकलन करें तो उपरोक्त पंक्तियां उस पर सटीक बैठती हैं। गौरतलब है कि 9 दिसंबर 2021 को जब भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई तो पुलिस महकमे के साथ ही दोनों शहरों की जनता में नई उम्मीद का जोश दिखा। लेकिन अब यह जोश ठंडा पड़ा दिख रहा है। राजधानी में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद भी पुलिस की मैदानी सक्रियता जस की तस है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने पुलिस आयुक्त प्रणाली के अनुरूप आला अफसरों की पदस्थापना तो कर दी लेकिन मैदानी अमला अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। यहीं नहीं अभी तक पुराने शहर में एडिशनल डीसीपी की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। इसका असर व्यवस्था पर साफ-साफ दिख रहा है। यह स्थिति तब है जब भोपाल के पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अफसर हैं। आयुक्त प्रणाली में सबसे ज्यादा दिक्कत मैदानी अमले की कमी से हो रही है। वजह साफ है कि आला अफसरों के पद तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन निचला अमला अलग से स्वीकृत नहीं किया गया है। इससे व्यवस्था में तार्किक बदलाव नहीं आया है। इसका भान पुलिस अफसरों को भी है। लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं। न फंड है और न ही अमला। इसका असर यह हो रहा है कि आज तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर नहीं पाई है। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि शहर में सारी व्यवस्था चाक-चौबंद नजर आने लगेगी। लेकिन आज भी शहर के अधिकांश चौराहों की ट्रैफिक लाईट सुधरी नहीं है। इस कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। शहर की सड़कों का आलम यह है कि वीआईपी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गड्ढ़े ही गड्ढ़े नजर आ रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी और मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण उनके आसपास की सड़कें चलने लायक नहीं रह गई हैं। ऐसे में पुलिस आयुक्त प्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है। यही नहीं कानून व्यवस्था की स्थिति भी पहले की तरह है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने आईपीएस अफसरों की तो पदस्थापना कर दी, लेकिन नीचे की इकाई के मुखिया यानी थाना इंचार्ज आज भी पुराने ही हैं। स्थिति यह है कि शहर में इंस्पेक्टरों की भरमार के बाद भी अधिकांश थानों की कमान सब इंस्पेक्टर के हाथों में है। ये थाना इंचार्ज कोई ऐरे-गैरे नहीं हैं, बल्कि माननीयों के नाते-रिश्तेदार हैं। ये काम करें या न करें इनको कोई हटा नहीं सकता। ऐसे में शहर की व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है। आयुक्त प्रणाली लागू होने के साथ ही नई व्यवस्था में सामूहिक नहीं, सबकी अलग-अलग जिम्मेदारी तय करने की नीति बनी थी। इसके तहत सिपाही तक को बीट का प्रभारी बनाया जाना था। ताकि मोबाइल और वायरलेस सेट के जरिए आला अफसर अपने बीट प्रभारी के सीधे संपर्क में रह सकें। व्यवस्था में बदलाव के तहत पहला काम सिपाही तक की जिम्मेदारी तय करने का था। लेकिन सारी व्यवस्था कागजों पर ही सीमित है। भोपाल के पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर निरंतर अफसरों को ताकीद कर रहे हैं, लेकिन मैदानी अमला अभी भी पुलिस आयुक्त प्रणाली के फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा है। इसके लिए जब तक पूरे अमले में आमूलचूल बदलाव नहीं होगा, तब तक स्थिति जस की तस रहेगी।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 10, पृष्ठ-48, 16 से 28 फरवरी, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्कण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

मप्र में अपराध होगा शून्य

मप्र में शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री दिन-रात प्रयास कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों से समाज को दूर रखने के लिए प्रदेश में कई कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम अपराध शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

● **सूरज यादव,** भोपाल (म.प्र.)

मंडी में भी इंदौर नंबर-1

अब मंडी में भी इंदौर प्रदेश या देश में ही नहीं, पूरी एशिया में नंबर-1 बन जाएगा। इंदौर में कैलोद गांव के निकट भूमि पर शिफ्ट की जा रही कृषि उपज मंडी एशिया की सबसे स्मार्ट मंडी बनाई जाएगी। इससे मप्र सहित आसपास के राज्यों को भी फायदा मिलेगा।

● **नितेश तिवारी,** इंदौर (म.प्र.)

मजदूर मजबूर क्यों?

मनरेगा योजना से लाखों मजदूरों को लाभ मिलता है। इस योजना के तहत कई राज्यों में भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसका खामियाजा गरीब मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। सरकार को इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करनी होगी, जिससे मजदूरों को अपना हक मिल सके।

● **रानू शिवहरे,** ग्वालियर (म.प्र.)

आत्मनिर्भर होगा हमारा मप्र

कोरोनाकाल में अनगिनत नौकरियां चली गईं। ऐसे में अब लोगों की निगाहें रोजगार के नए माध्यमों पर हैं। इस साल में मप्र में कई बड़े उद्योग स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र को औद्योगिक हब बनाने का जो प्रयास शुरू किया है उसके सार्थक परिणाम नजर आने लगे हैं। मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जो कार्ययोजना बनाई है, उसमें वर्ष 2022 में गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ाई जाएंगी। सरकार का सबसे अधिक फोकस उद्योग-धंधों पर है। इस साल रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के लिए निवेश बढ़ाने पर सर्वाधिक जोर दिया जाएगा। अगर सबकुछ ऐसे ही चलता रहा तो मप्र आने वाले समय में देश को रोजगार का बूस्टर डोज देगा।

● **कोमल मिश्रा,** सीहोर (म.प्र.)

मप्र होगा कर्ज मुक्त

मप्र की शिवराज सरकार ने जमीन बेचकर कर्ज चुकाने का जो तरीका अपनाया है, वह एक तरह से सही है। शिवराज सरकार ने भोपाल सहित प्रदेशभर में पड़ी सरकारी जमीनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करवाई है, जिसमें तमाम विभागों की जमीनों को शामिल किया गया है और उसके लिए अलग से मप्र लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का भी गठन किया गया है। दरअसल तमाम विभागों के पास अनुपयोगी जमीनें पड़ी हैं, जिन पर अवैध कब्जे भी हो जाते हैं। सरकार इन्हें बेचकर प्रदेश को कर्ज से मुक्ति दिलाएगी।

● **आरती शर्मा,** जबलपुर (म.प्र.)

व्यापक तैयारी जरूरी

किसानों की समस्याओं का समाधान अभी भी प्रतीक्षित है। राष्ट्रीय राजमार्गों और मेट्रो का विस्तार अच्छे संकेत हैं, पर औद्योगिक उत्पादन अभी भी अपेक्षित स्तर से कम है। आर्थिक सुधारों और व्यापार का सुभीता बढ़ाने के लिए नियम-कानून में बदलाव जरूरी है। सामरिक दृष्टि से सीमा पार और आंतरिक चुनौतियों का स्वरूप जटिल हो रहा है। इस मोर्चे पर सजगता जरूरी है। नए वर्ष के आगमन पर कोरोना के तेजी से फैलने वाले संस्करण ओमिक्रोन की दस्तक चिंताजनक है। उससे निपटने के लिए व्यापक तैयारी जरूरी है।

● **मिथलेश सिंह,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

कुनबे की कलह

तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में सबकुछ सहज और सामान्य नहीं दिख रहा है। कोलकाता हवाई अड्डे पर अखिलेश यादव के समर्थन के लिए लखनऊ रवाना होने से पहले ममता बनर्जी पत्रकारों से रूबरू हुई। उनसे गोवा में चुनाव प्रचार की बाबत सवाल हुआ तो बोली कि वे लखनऊ जा रही हैं। गोवा को कोई और देख रहा है। वे गोवा नहीं जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गोवा में पार्टी के विस्तार का अभियान ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी और सांसद महुआ मोइत्रा चला रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने दूसरे दलों से नेता तो जरूर तोड़ लिए पर गोवा के चुनावी मुकाबले में पार्टी अपेक्षित माहौल नहीं बना पाई। जाहिर है कि दीदी ने भतीजे का नाम लेने के बजाय कोई कहकर संबोधित किया तो इससे दोनों के बीच मतभेद के कयास तो लगने ही थे। प्रशांत किशोर से भी ममता अब खुश नहीं लग रहीं। उनकी कंपनी को इस अपेक्षा से ठेका दिया गया था कि तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी। अभी तक के नतीजों से ऐसा होता दिख नहीं रहा। चर्चा है कि पीके ने ममता को संदेश भेजा था कि वे अब पश्चिम बंगाल, मेघालय और ओड़िशा में काम करना नहीं चाहते। दीदी ने भी तत्काल उन्हें धन्यवाद लिख भेजा। वे 2026 तक के अपने अनुबंध को जब चाहें तोड़ सकते हैं।

चुनावी मांग

हिमाचल में चुनावी साल शुरू हो गया है। चुनावी साल की वजह से प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन पर हैं। ऐसा हर चुनावी साल में होता है। लेकिन हाल ही में ठेकेदारों ने 400 करोड़ रुपयों के करीब लंबित भुगतान को लेकर जब हड़ताल की तो पूरे मंत्रिमंडल में ही हलचल मच गई। मचती भी क्यों नहीं। चुनावों के खर्च को चलाने के लिए पिछले दरवाजे से पैसा इन्हीं ठेकेदारों के जरिए मिलता है। ऐसे में राठौर ने झट से ठेकेदारों की मांग का समर्थन कर दिया। वामपंथी विधायक राकेश सिंघा भी समर्थन में उतर गए। क्योंकि ठेकेदारों के पास काम करने वाले श्रमिकों का भुगतान रुक गया था। पहले तो मुख्यमंत्री ने इस मामले पर अदालत के आदेश का हवाला देकर इस भुगतान का मामला अदालत के जरिए सुलटाने का रुख ले लिया। लेकिन जब ठेकेदारों ने अपना संघर्ष बढ़ाया तो मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली। ज्यादातर मंत्री राजधानी से बाहर थे। कई पहुंच भी नहीं सके। बैठक में तुरंत ठेकेदारों के भुगतान को लेकर रास्ता निकालकर एक संबधित अधिनियम में संशोधन करने का फैसला ले लिया गया। अब बाकी कर्मचारी सोच रहे हैं कि उनका संघर्ष तो सालों तक चलता है। लेकिन सरकार कोई परवाह ही नहीं करती। हालांकि अभी यह मामला अदालत में है। अदालत ने अगर सरकार के रुख को नहीं माना तो जयराम सरकार फिर चुनावी साल में मुश्किल में फंस जाएगी। कांग्रेस पार्टी चाहती भी कुछ ऐसा ही है। चाहती है कि ठेकेदार सरकार के खिलाफ रहें।

चर्चा-ए-मुफ्त

दिल्ली और पंजाब में ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन वहां के आर्थिक और राजनीतिक संस्कृति में खासी दूरी है। दिल्ली में बिजली-पानी मुफ्त की बात यहां के मध्यमवर्गीय लोगों के लिए संजीवनी की तरह ही है। दिल्ली वालों की बिजली का बिल पड़ोसी राज्यों के लोगों के लिए ईर्ष्या का सबब बन जाता है। एक तरह से कहें तो आम आदमी का चरित्र ही शहरी मध्य-वर्ग का है। बात एक ब्यूटी पार्लर में चल रही थी। दुल्हन के मेकअप का बिल पचास हजार का था और उसके साथ आई लड़कियों का अलग से। वो बात कर रही थीं कि पंजाब में केजरीवाल आएंगे तो स्त्रियों को एक-एक हजार रुपए देंगे। इसके लिए बस उन्हें मोबाइल से घंटी मारनी पड़ेगी। अब जो लड़की अपने मेकअप के लिए पचास हजार दे सकती है उसकी इस वादे में क्या रुचि रहेगी। लेकिन पंजाब के इलाके इस बात की तस्दीक करते हैं कि चाहे आपके बटुए में कितने भी पैसे हों मुफ्त का आकर्षण कभी खत्म नहीं होता है। चंडीगढ़ जैसे अपेक्षाकृत महंगे इलाकों में भी पार्लर से लेकर मॉल तक मुफ्त-मुफ्त की बातें जरूर होती हैं। पंजाब में भी हाशिए पर पड़ा ऐसा तबका है जिसके लिए ये वादे उनकी जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। विरोधाभासों से भरे इस राज्य में आम आदमी पार्टी चर्चा में तो खूब है और वो भी अपने मुफ्त-मुफ्त के वादों को लेकर।

संकट में सपा

उप्र में भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी की रफ्तार में ओवैसी स्पीड ब्रेकर बनते दिखने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी को पूरी तरह नकारने वाले पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की सोच उप्र के मुसलमानों में नहीं है। ओवैसी को यहां का मुस्लिम वोटर, खासकर युवा वर्ग खासा पसंद करता है। भाजपा इस वर्ग में यह प्रचार कर पाने में सफल होती नजर आ रही है कि भले ही उसे मुसलमान वोट नहीं चाहिए, सपा भी बहुसंख्यक वोटर को लुभाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को तवज्जो देने से बच रही है। यह बात तेजी से फैलने लगी है कि कथित धर्मनिरपेक्ष दल मुसलमान का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुस्लिम लीडरशीप को वे खुले तौर पर अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं। ओवैसी इस बात को मुसलमानों के दिमाग में बैठाने का काम कर रहे हैं जिसका सीधा फायदा भाजपा को होना तय है। पश्चिम उप्र में सपा-रालोद का गठबंधन भाजपा के लिए बड़ा संकट है। इस संकट का निपटारा भाजपा के लिए ओवैसी कर रहे हैं।

भारी टेंशन में धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों खासे परेशान बताए जा रहे हैं। कारण है उनकी विधानसभा सीट खटीमा जहां से वे प्रदेश की पांचवीं विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खटीमा में बतौर मुख्यमंत्री धामी ने करोड़ों की विकास योजनाएं शुरू की हैं। धामी की पत्नी पिछले पांच महीनों से घर-घर जनसंपर्क कर आम जनता की समस्याओं को समझ उन्हें दूर करने का कार्य कर रही हैं। धामी स्वयं भी अत्यंत मिलनसार और मृदभाषी होने के चलते क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। इस सबके बावजूद उनका टेंशन अपने चुनाव को लेकर दिनों दिन बढ़ने के समाचार आ रहे हैं। इसका कारण है प्रदेश के मतदाताओं द्वारा पूर्व में दो सीटिंग मुख्यमंत्रियों को चुनाव हरवा देना। भाजपा के कद्दावर नेता मेजर जनरल (रि.) भुवन चंद्र खंडूड़ी 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को तो एंटी इन्कमबैंसी फैक्टर से बाहर निकाल पाने में सफल रहे थे लेकिन खुद अपनी सीट गवां बैठे थे।

माननीय ने फंसाया पेंच

प्रदेश में मंत्रियों के कामकाज में हो रहे हस्तक्षेप से कई मंत्री आहत हैं। लेकिन कुछ बोलने या करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के एक कद्दावर मंत्री ने अपने विभाग में हो रहे हस्तक्षेप का ऐसा जवाब दिया है कि सरकार भी पसोपेश में पड़ गई है। दरअसल, मंत्रीजी के पास प्रदेश के कई प्रमुख विभाग हैं। उनमें से एक विभाग कानून व्यवस्था को संभालने वाला भी है। मंत्रीजी चाहते हैं कि इस विभाग को वे अपनी मंशानुसार चलाएं, लेकिन विभाग में ऊपरी हस्तक्षेप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मंत्रीजी जैसे-तैसे इस हस्तक्षेप को बर्दाश्त कर रहे थे कि एक ऐसा मामला सामने आया, जिससे मंत्रीजी जल-भुन गए हैं। दरअसल, मंत्रीजी के विभाग में इंस्पेक्टरों का बड़े स्तर पर तबादला हुआ, लेकिन न तो इसके लिए मंत्रीजी से पूछा गया और न ही दस्तखत कराई गई। अब विभाग ने डीएसपी के तबादले की एक सूची तैयार की है। गत दिनों यह सूची मंत्रीजी के पास भेजी गई तो मंत्रीजी ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि मुझसे जब इंस्पेक्टरों के तबादले की सूची पर हस्ताक्षर नहीं कराया गया है, तो मैं इस सूची पर भी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी के इस रुख से डीएसपी के तबादले की सूची अधर में लटकी हुई है। उधर, न तो शासन और न ही प्रशासन हिम्मत जुटा पा रहा है कि इस संबंध में मंत्रीजी से बात कर मामले को सुलझाया जाए।

मंत्राणी का गुस्सा

सोशल मीडिया के इस युग में हर नेता इस कोशिश में लगा हुआ है कि वह अधिक से अधिक मैसेज सोशल मीडिया पर प्रसारित करे। इस मामले में प्रदेश सरकार के मुखिया भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन गत दिनों कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के बीच एक महिला मंत्री ने सरकार के मुखिया को नसीहत दे डाली कि वे अपने ट्विटर हैंडलर को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। कैबिनेट में शामिल कुछ मंत्री मंत्राणी के मंतव्य को समझ नहीं पाए। वहीं जो मंत्री सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, वे मंद-मंद मुस्कुराते रहे। दरअसल, प्रदेश सरकार के मुखिया के ट्विटर एकाउंट से गत दिनों एक ऐसा वीडियो डाल दिया गया, जिसमें अनैतिकता

झलक रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि कई मंत्रियों, विधायकों और अन्य लोगों ने बिना देखे-समझे उस वीडियो को रीट्वीट भी कर दिया। इस बात से प्रदेश सरकार के मुखिया शायद अनभिज्ञ थे। लेकिन जिन लोगों की नजर इस पर पड़ी थी, वे भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे में राजसी ठाठ-बाट वाली मंत्राणी ने हिम्मत जुटाई और भरी कैबिनेट में मुखिया को नसीहत दे डाली कि अपने ट्विटर हैंडलर को ताकीद कर दें, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती न हो पाए।

मंत्री की हरकत से सब हैरान

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक मंत्री की एक ओछी हरकत चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, मंत्रीजी जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग पर मुख्यमंत्री की खूब मेहरबानी है। बताया जाता है कि ऐसे में मंत्रीजी जमकर चांदी काट रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी की चांदी काटने की आदत इस कदर बिगड़ गई है कि वे छोटे-छोटे मामलों में भी लक्ष्मी की आस करने लगते हैं। गत दिनों मंत्रीजी के विभाग से संबंधित एक विभाग में तबादलों के मामले में मंत्रीजी की नीयत खुलकर सबके सामने आई। दरअसल, जिस विभाग की यहां बात हो रही है, उस विभाग में सालभर तबादले होते रहते हैं। ऐसे में मंत्रीजी लगातार उस विभाग को तबादले के प्रस्ताव भेजते रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि विगत दिनों जब कुछ प्रस्ताव विभाग के पास पहुंचे उसमें कुछ दागी लोग भी थे। ऐसे में वहां के बाबुओं ने दाग को साफ करने के लिए कुछ मांग कर डाली। बताते हैं कि तबादला चाहने वालों ने बताया कि भैया हम तो पहले से ही मंत्रीजी के यहां पर्ची कटवा चुके हैं। अब आपको क्या दें। यह बात जब मंत्रीजी के पास पहुंची तो वे आव देखे न ताव और उस विभाग में जांच के लिए पहुंच गए। उन्होंने एमडी से इसकी शिकायत की, तो एमडी ने कहा- नोटशीट तैयार करने के लिए व्यक्ति की जांच-पड़ताल तो करनी ही होगी। ऐसे में मंत्रीजी ने कहा- किसी चीज की जरूरत नहीं है, सबका तबादला कर दो। मंत्रीजी यहीं नहीं रुके, उन्होंने उस विभाग के तमाम बाबुओं को कतार में खड़ा कराकर पूछ डाला, किसने रिश्वत मांगने की कोशिश की है। लेकिन मंत्री के सामने मुंह कौन खोले।

कलेक्टरी की आस

हर आईएएस और आईपीएस का सपना होता है कि वह इंदौर या भोपाल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए। लेकिन राजधानी में पदस्थ एक आईएएस अधिकारी का मन यहां से उचट चुका है। 2011 बैच के यह आईएएस अधिकारी अपनी वर्तमान पदस्थापना से ऊब चुके हैं और कलेक्टर बनने की जुगाड़ में जुट गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये साहब पहले कलेक्टर नहीं रहे हैं। अभी साहब राजधानी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन जिस काम के लिए उनको यह जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें वे पूरी तरह विफल रहे हैं। इसलिए वे अब कलेक्टर बनने की जुगत में हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछली बार साहब का खंडवा कलेक्टर बनना लगभग तय हो गया था, लेकिन अंत में उनका नाम काट दिया गया। वैसे साहब अपनी वर्तमान पदस्थापना से मुक्ति चाहते हैं इसलिए वे कहीं का भी कलेक्टर बनने को तैयार हैं। लेकिन उनकी पसंद राजधानी के आसपास के जिले हैं। साहब रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद का कलेक्टर बनना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है यह तो साहब ही बता सकते हैं।

बदल रही परिपाटी

चाल, चेहरा और चरित्र वाली पार्टी में इस समय बहुत कुछ बदल रहा है। इसमें से एक बदलाव यह दिख रहा है कि दरी और जाजम बिछाकर बैठक करने वाली पार्टी पर होटल संस्कृति हावी हो रही है। भाजपा में पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें व प्रशिक्षण शिविर होटलों में आयोजित होते रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रदेश भर से पदाधिकारी आते थे, लेकिन अब जिला और शहर स्तर पर होने वाली बैठकें और शिविर भी होटलों में करने की नई परंपरा शुरू हो गई है। विगत दिनों राजधानी के पड़ोसी जिले के एक होटल में जिला भाजपा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण चर्चा का विषय बना हुआ है। भोपाल-इंदौर सड़क पर बने इस होटल में तीन दिनों तक पदाधिकारियों की बैठक चली। बताया जाता है कि आगामी दिनों में होने वाली बैठकों के लिए पदाधिकारियों ने अपने नेता को किसी हिलस्टेशन पर जाने की सलाह दी है। इसकी वजह यह है कि पार्टी के काम के साथ-साथ नेताओं को पर्यटन का मौका भी मिल जाता है। अब देखना यह है अगली बैठक कहां होती है।

अक्स का आईना

जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते, उनसे कहूंगा कि योगी ने हजारों जेसीबी और बुल्डोजर मंगवा लिए हैं। ये सभी उप्र की ओर निकल चुके हैं। चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा, जिन लोगों ने योगीजी को सपोर्ट नहीं किया है।

● **टी राजा सिंह**

उप्र में कांग्रेस प्रत्याशी महिलाएं बड़े-बड़े दिग्गजों पर भारी पड़ रही हैं। यही कारण है कि भाजपा निरंतर मुझ पर और मेरे प्रत्याशियों पर जुबानी हमले कर रही है। यहां तक कह दिया गया है कि मेरे और मेरे भाई राहुल गांधी के बीच अनबन चल रही है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकती हूं। अब तो वे लोग मुंह बंद रखें।

● **प्रियंका गांधी**

विराट कोहली को लेकर मीडिया में रोज नई कहानी गढ़ी जा रही है। सब खिलाड़ियों के जीवन में उतार-चढ़ाव आता रहता है। विराट आज भी भारतीय टीम की रीढ़ हैं। एक-दो मैच की परफॉर्मेंस से किसी की उपयोगिता पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। विराट जल्द ही अपनी लय में नजर आएंगे। फिर यही लोग वाहवाही करेंगे।

● **रोहित शर्मा**

रूस-यूक्रेन के बीच तनातनी बड़े खतरे का संकेत है। इसलिए पूरे विश्व को यह कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध की नौबत न आए। मैं लगातार दोनों देशों के प्रमुखों से चर्चा कर रहा हूं। उम्मीद है कि हमारा प्रयास रंग लाएगा और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित होगी।

● **जो बाइडेन**

अभी फिल्मों में मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है। भविष्य में मैं अपने आईडियाज को साकार करना चाहती हूं। इसलिए मैं प्रोडक्शन हाउस बनाने का प्लान कर रही हूं। अगर मैं एक प्रोड्यूसर बनूंगी, तो मुझे प्रोफिट का एक हिस्सा मिलेगा, जो मेरे लिए बड़ी बात होगी। मेरे लिए ये केवल पैसा नहीं है। ये उस बारे में है, जब मैं करीब 10 सालों में एक निश्चित मुकाम पर पहुंच जाऊंगी। जहां मुझे लगता है कि मैं एक टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छी पॉजिशन पर होऊंगी। यह केवल मेरे इंजन को फ्यूल देने के बारे में नहीं है, मैं अब फ्यूल का उपयोग कर सकती हूं और अन्य इंजनों को भी फ्यूज दे सकती हूं।

● **आलिया भट्ट**

वाक्युद्ध

उप्र में कानून का राज है और आगे भी रहेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता भ्रष्टों और बाहुबलियों की पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी और उसके बाद उनकी गर्मी निकाल दी जाएगी। अभी जिसको जितना गर्म होना है हो ले, बाद में सबकी हेकड़ी बंद हो जाएगी। 10 मार्च के बाद सब अपने घर में दुपक जाएंगे।

● **योगी आदित्यनाथ**

ये गर्मी निकालने की बात करते हैं। पहले दो चरणों के मतदान में इनका सफाया हो गया है और जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे, उनकी भाप निकल गई है। अब उसके बाद जो वोट पड़ेंगे उससे वे उस दिन धुआं हो जाएंगे। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि सपा सरकार बनते ही हम युवाओं के लिए नौकरियां निकालेंगे।

● **अखिलेश यादव**

विवादों का मास्टर प्लान

राजधानी का मास्टर प्लान एक बार फिर विवादों में फंसता जा रहा है। गौरतलब है कि विवादों के कारण राजधानी में मास्टर प्लान केवल कागजों में ही बनता रहा है। अब मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप में बड़े तालाब के कैचमेंट में बसे 49 गांवों को भी शामिल कर लिया गया है। शासन के निर्देश पर अहमदाबाद की सेप्ट यूनिवर्सिटी ने बड़े तालाब पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। मास्टर प्लान के जारी ड्राफ्ट में इस रिपोर्ट पर अमल करने का दावा भी किया गया। रिपोर्ट में भोपाल की सीमा में आने वाले 49 गांवों की पूरी जानकारी दी गई। टीएंडसीपी के अधिकारियों ने बेशकीमती जमीन के लिए गड़बड़ी कर सिर्फ 32 गांवों को ही दिखाया था। मतलब 17 गांवों के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया था, लेकिन इस संबंध में सैकड़ों आपत्तियां आई थी। अर्बन एक्सपर्ट कमल राठी ने बताया कि करीब तीन दर्जन से अधिक लोगों ने इस संबंध में आपत्ति लगाई थी। इसके बाद आपत्तियों के निराकरण करने के बाद सभी गांव को शामिल कर लिया गया है।

बता दें कि करीब 9 साल से बन रहा भोपाल का मास्टर प्लान मार्च 2022 से लागू किया जा सकता है। प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के ड्राफ्ट में अब कोई बदलाव नहीं होगा। इनके ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं और प्रारंभिक प्लान का प्रकाशन भी हो चुका है। दावे-आपत्तियों का निराकरण होना बाकी है। भोपाल में पिछले 16 साल से मास्टर प्लान नहीं बना है। साल 2005 में जो मास्टर प्लान बना था, उसके अनुसार ही 2021 तक शहर का विकास हुआ। पिछले साल नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय ने वर्ष 2031 के हिसाब से ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेजा था। इसमें डेढ़ साल में दो बार बदलाव हुए। इस बीच केंद्र ने अमृत योजना में शामिल सभी शहरों के मास्टर प्लान वर्ष 2035 के हिसाब से बनाने की गाइडलाइन दी। इस कारण एक बार फिर भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रस्तावित 2031 के ड्राफ्ट को ही लागू करने का मन बना लिया है।

सेप्ट की रिपोर्ट भी बड़े तालाब के कुल कैचमेंट एरिया पर तैयार की गई थी। भोपाल व सीहोर जिले के कुल 80 गांवों को शामिल किया गया। भोपाल के 49 व सीहोर के 31 गांवों को कैचमेंट एरिया में बताया गया है। रिपोर्ट में इन गांवों में निर्माण की अनुमतियां जारी नहीं करने की भी अनुशंसा की थी। यही नहीं कैचमेंट हथाईखेड़ा, दूबड़ी, ईंटखेड़ी, जमुनिया छीर, जाटखेड़ी, काजलस, कलखेड़ा, कल्याणपुर, खजूरी सड़क, खामलाखेड़ी, खारखेड़ी, खारपा, भीलखेड़ी, बिसनखेड़ी, गोरा गांव, बरखेड़ाकला, सिवनिया गौंड, बहोरी, बकानिया, बरखेड़ा सलाम, बोरवन (बारदा), बरखेड़ानाथू, बोरखेड़ी समेत अन्य गांवों को मास्टर प्लान में दिखाया गया है। वहीं खोकरिया, खुरचानी, मेलखेड़ी, मीरपुर, नरेला गांव, पांडाखेड़ी, पिपलिया धाकड़, रोरूखेड़ी, टीलाखेड़ा आमखेड़ा, बाड़झिरी, बहेटा, खेतलाखेड़ी आदि गांवों के नाम पर गड़बड़ी की गई है।

मास्टर प्लान 2031 की खंड-1 में यह तो बताया गया है कि तालाब के कैचमेंट एरिया में कई प्रवासीय पक्षी विदेशों से हजारों किमी सफर तय करके यहां आते हैं। लिहाजा, इसके संरक्षण को लेकर प्रावधान किए गए हैं। जबकि पक्षियों के उन ग्रामीण क्षेत्रों को मास्टर प्लान से गायब किया गया, यहां इनका प्रजनन क्षेत्र रिपोर्ट में दिखाया है। मास्टर प्लान में कैचमेंट (सीजेड) के तहत बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल को रखा गया है। लिहाजा निर्माण व अन्य प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंधित हैं। इसके बाद कैचमेंट जोन-1 में शहरी सीमा में जलभराव से 50 मीटर के बाद व ग्रामीण क्षेत्र में 300 मीटर के बाद निर्माण (यूटिलिटी) को अनुमतियों का प्रावधान है। जबकि कैचमेंट जोन-3 में ऐसे एरिया को शामिल किया गया है, जो तालाब की वाटर बॉडी से दूर है। यहां से पानी वाटर बॉडी में पहुंचता है। यहां भी निर्माण की अनुमतियां देने का प्रावधान किया गया। अब देखना यह है कि विवादों की वजह से नया मास्टर प्लान भी कागजों में ही दम तोड़ देगा या फिर लागू होगा।

● अरविंद नारद

मास्टर प्लान की मात्र 35 फीसदी सड़कें ही बन पाईं

करीब 9 साल से बन रहा भोपाल का मास्टर प्लान मार्च 2022 से लागू किया जा सकता है। प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के ड्राफ्ट में विकास के बड़े-बड़े प्रस्ताव हैं। लेकिन 1996 की प्रस्तावित सड़कें आज तक आधी-अधूरी हैं। करीब 26 साल पहले राजधानी में सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट शुरू तो हुए, लेकिन जमीनी विवाद व अन्य वजहों से उलझकर रह गए हैं। इस कारण अभी तक मात्र 35 फीसदी सड़कों का ही निर्माण हो पाया है। ऐसे में नए मास्टर प्लान की उपयोगिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। भोपाल में पिछले 16 साल से मास्टर प्लान नहीं बना है। साल 2005 में जो मास्टर प्लान बना था, उसके अनुसार ही 2021 तक शहर का विकास हुआ। पिछले साल नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय ने वर्ष 2031 के हिसाब से ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेजा था। इसमें डेढ़ साल में दो बार बदलाव हुए। इस बीच केंद्र ने अमृत योजना में शामिल सभी शहरों के मास्टर प्लान वर्ष 2035 के हिसाब से बनाने की गाइडलाइन दी। इस कारण एक बार फिर भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन सवाल उठ रहा है कि पुराने मास्टर प्लान की सड़कों का क्या होगा। 26 साल पहले आए मास्टर प्लान में प्रस्तावित की गई ऐसी ही कई सड़कें हैं, जो चंद किलोमीटर बनने के बाद अटक गईं। प्लान की गई सड़कों में से महज 35 फीसदी ही बन पाई हैं। 65 फीसदी सड़कें आज भी बनने का इंतजार कर रही हैं। सालों बाद भी प्रशासन इनकी बाधा दूर नहीं कर सका है। एक बार फिर इन सड़कों को लेकर कवायद तो शुरू की गई हैं, अब देखना यह है कि यह कवायद कागजों में दफन हो जाएगी या जमीनी स्तर पर नजर आएगी ये तो समय ही बताएगा।

भाजपा ने मिशन 2023 के लिए 52 फीसदी वोट का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी ने पूरी जमावट कर दी है। शिव-वीडी की जोड़ी ने राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा अभियान बूथ विस्तारक अभियान चलाकर इस पर फुल प्रूफ मुहर लगा दी है। सत्ता और संगठन को उम्मीद है कि आगामी चुनाव में पार्टी 200 पार का टारगेट भी पूरा कर लेगी।

20 लाख घंटे का समयदान

2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अधिक वोट प्रतिशत पाने के बाद हार का सामना करने वाली भाजपा सत्ता में आते ही मिशन 2023 के लिए जुट गई थी। मिशन 2023 में कांग्रेस का सूपड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 200 से अधिक सीटें जीतने का टारगेट सेट किया और अभियान में जुट गए। इसी के तहत बूथ विस्तारक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 20 हजार विस्तारकों ने 65 हजार बूथों तक पहुंचकर 20 लाख घंटे का समय दान कर पार्टी का वोट बैंक 10 फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य साधा है। गौरतलब है कि भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में 41 फीसदी वोट मिले थे। यानी 2013 के मुकाबले करीब 4 फीसदी वोट का नुकसान हुआ था। ऐसे में शिवराज और वीडी शर्मा ने 2023 के चुनाव में 51 फीसदी वोट का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

दरअसल, वर्तमान समय में भाजपा हार के बाद जीत है के मंत्र पर काम कर रही है। इसके लिए शिवराज और वीडी शर्मा की जोड़ी ने जिद करो और दुनिया बदलो की रणनीति अपनाई है। इसी के तहत बूथ विस्तारक अभियान चलाया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि बूथ विस्तारक योजना के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पार्टी के 20 हजार से अधिक विस्तारकों ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री, संगठन पदाधिकारियों ने 10-10 घंटे काम किया है। उनकी सक्रियता से पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि इस योजना में कई अद्‌भुत काम हुए हैं। कमल पुष्प अभियान में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लिया गया, तो विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के काम भी हुए हैं।

भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान 20 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक चला। इन 17 दिनों में पार्टी के 20 हजार से अधिक विस्तारकों ने 65 हजार बूथों को साधा है। इस अभियान के माध्यम से भाजपा ने बूथ समिति तक पहुंचकर उनसे मजबूत बंध बनाने का काम साध लिया है और उन्हें डिजिटल प्लेटफार्म पर संग्रहित कर पार्टी के राष्ट्रीय हाईकमान से लेकर स्थानीय हाईकमान के एक क्लिक पर लाकर जोड़ दिया है। इस अभियान के तहत विस्तारकों ने 20 लाख घंटे का समयदान कर पार्टी का वोट बैंक 10 फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य साधा है। गौरतलब है कि भाजपा अपने पितृ पुरुष का जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मना रही है। एक वर्ष तक चलने वाले इस पर्व में भाजपा खुद को और सशक्त बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। भाजपा ने संवाद और संपर्क के माध्यम से निचले कार्यकर्ता और सरकार से लाभांवित हितग्राहियों तक पहुंचने का पूरा खाका तैयार किया है। पहले चरण में भाजपा ने बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं की टीम को सशक्त किया है। जल्द ही हितग्राहियों को भी संपर्क के माध्यम से पार्टी से लगातार जोड़े रखने पर फोकस किया जाएगा।

भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को भाजपा ने मप्र में पार्टी में भी आत्मसात किया है। तभी राजनीतिक दल की सबसे निचली इकाई बूथ समिति, जिसको सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है, उस तक सबसे पहले पहुंच रही है। यही नहीं, भाजपा के प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं सहित राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी बूथ तक भेजकर नेता कार्यकर्ता एक समान का संदेश दिया जा रहा है। भाजपा हमेशा नए लक्ष्य लेकर

जनाधार बढ़ाने में सबका योगदान

भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान समाप्त होने के बाद अब यह आंकलन किया जा रहा है कि किस-किस का इस अभियान में कितना योगदान रहा। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार मंत्रियों के अलावा अधिकांश विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रतिदिन पूरे 10-10 घंटे नहीं दिए हैं। संगठन अब ऐसे नेताओं की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मप्र में 11 प्रतिशत वोट बैंक बढ़ाने के लिए भाजपा ने बूथ विस्तारक अभियान चलाया था। यह अभियान 5 फरवरी को संपन्न हुआ। इस अभियान में 20 हजार विस्तारकों ने पार्टी को वोट बैंक बढ़ाने के लिए खूब काम किया है। लेकिन इस अभियान में प्रदेश सरकार के मंत्रियों की भूमिका सबसे कम रही। गौरतलब है कि भाजपा ने इस अभियान में टॉप-टू-बॉटम सभी पदाधिकारियों को इस काम में लगाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर नेता और मंत्रीगण बूथों पर प्रवास के लिए 100 घंटे का समय नहीं निकाल पाए। इस संबंध में संगठन के नेताओं का कहना है कि मंत्रियों के पास सरकार के कामकाज की व्यस्तता भी है इसलिए उनके बूथ प्रवास के घंटों का हिसाब नहीं रखा गया।

काम करती है और जब लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो उसके कारणों की तह तक जाकर उन कमियों को दूर करने में जुट जाती है। भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान भी ऐसा ही है। भाजपा इस अभियान में समयदान के माध्यम से सतत संपर्क, सतत संवाद करने में जुटी रही। इसमें भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का लक्ष्य पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की संगठन क्षमता का मिश्रण है।

भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि 2018 में मिली हार के बाद पार्टी ने सबक लिया है और अबकी बार 200 पार के लक्ष्य को सफल बनाने का अभियान चलाया। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। विधानसभा सीटों का लक्ष्य बहुत पीछे छूट ही गया था। उससे भी ज्यादा चिंताजनक था भाजपा का वोट प्रतिशत करीब 4 प्रतिशत कम हो जाना। कारणों को तलाशने का दौर शुरू हुआ। तब एक बड़ा कारण बूथ पर कमजोर प्रदर्शन भी सामने आया। तभी से भाजपा बूथ को लेकर एक महाअभियान की रणनीति पर काम कर रही थी। कोरोना के दुष्प्रभाव निकल जाने के बाद भाजपा अब इस अभियान में जुट गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने इस अभियान को अपने हाथ में लिया और बूथ तक पहुंचने के संकल्प को साधने में जुट गई। इस अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भाजपा अपने बूथ विस्तारक अभियान में जनसंघ से जुड़े पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का सम्मान भी किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस अभियान में जहां भी गए, वहां बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का सम्मान कर उनका पार्टी में योगदान के लिए आभार जताया। वहीं भाजपा के इस अभियान में **भावविभोर** कर देने वाले नजारे देखने को मिले। खाचरोद के एक बूथ पर जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा 81 वर्षीय बुजुर्ग कार्यकर्ता पूरनदास बैरागी से मिले। बैरागी भावविभोर हो गए और वे अपनी भावना जाहिर करने से नहीं चूके। उन्होंने अपने जीवनकाल में पार्टी को दिए गए समय का जिक्र करते हुए कहा

कि मैं जब पार्टी के काम से जाता था, लोगों से मिलता था, तो वो मुझसे पूछते थे कि तुम्हें तन्ख्वाह मिलती है क्या? मैं कहता था, तन्ख्वाह नहीं मिलती, पर ये सारी मेहनत मेरे खाते में लिखाती जा रही है। इतने सालों में जो मेरे खाते में आया था, आज वो सब कुछ मुझे एक ही बार में मिल गया। भाजपा बूथ समिति को संपदा आई कार्ड भी दिया गया। संपदा कार्ड में सं से सम्मान, प से पहचान और दा से दायित्व जोड़ा गया है। यह भाजपा का डिजिटलाइजेशन की तरफ बड़ा कदम है। भाजपा के इस महाअभियान की माइक्रो लेवल पर मॉनीटरिंग डिजिटल वार रूम में की गई। अभियान में पार्टी के सचिव रजनीश अग्रवाल, रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, आईटी सेल के संयोजक अमन शुक्ला, गौरव विश्वकर्मा और अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में आईटी पेशेवरों की टीम 24 घंटे वार रूम में जुटी रही।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मिशन 2023 के लिए 51 फीसदी वोट का जो टारगेट सेट किया है, उसे हासिल करने के लिए कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी वर्ष समारोह पर 16 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक हुई थी। इसमें संगठन को मजबूती देने के लिए मास्टर प्लान तैयार हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में निर्णय हुआ था कि पार्टी बूथ विस्तारक योजना चलाएगी। ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिले। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष पर भाजपा ने 20 जनवरी से बूथ विस्तारक योजना चालू की गई। इसमें पांच फरवरी तक मप्र के 65 हजार बूथों पर बूथ विस्तारकों को भेजा गया। राजनीतिक इतिहास में भाजपा इसे सबसे बड़ा अभियान बता रही है। अभियान के लिए इंदौर और भोपाल के कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए थे। बूथ विस्तारक ने बूथों पर प्रवास कर केंद्रों की जानकारी एकत्रित की। उनके साथ रहने वाले आईटी संचालकों ने इसे संगठन एप में अपलोड किया। इसकी मॉनीटरिंग के लिए प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां से कार्यकर्ताओं को जरूरी टेक्निकल सपोर्ट दिया गया। बूथ विस्तारक योजना के तहत संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं ने प्रतिदिन 10 घंटे यानी इन 17 दिनों में 100 घंटे का श्रम किया। इस दौरान 9 हजार शक्ति केंद्रों पर 20 हजार से ज्यादा विस्तारक पहुंचे।

● कुमार राजेन्द्र

भाजपा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान

प्रदेशभर में बूथ डिजिटलाइजेशन के उद्देश्य से चल रही बूथ विस्तारक योजना के बाद भाजपा को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। पहले बूथ स्तर पर जाकर दिग्गज नेताओं ने पार्टी को कार्यकर्ताओं के लिहाज से मजबूत किया। अब इन बूथ पर एक बार फिर कई बड़े नेता पहुंचेंगे। यह सभी पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए फंड जुटाने का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण निधि जुटाने का अभियान शुरू किया गया। इस बार भाजपा ने 150 करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य रखा है। कोरोनाकाल में इस बार लक्ष्य पूरा करने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बूथ पर जाकर इस अभियान में हिस्सा लिया। इस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी को भी बूथ केंद्रों पर भेजने की योजना बनाई है। अलग-अलग नेताओं को अलग-अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की ओर से हर बड़े नेता को फंड जुटाने में सहायता के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य में पारदर्शिता को लेकर भी ध्यान रखा गया है।

कांग्रेस से भाजपा में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो त्याग किया था उसका भरपूर ईनाम पार्टी ने उन्हें और उनके समर्थकों को दे दिया है। सिंधिया ने जो चाहा उन्हें वह मिला। लेकिन सिंधिया और उनके समर्थकों की चाह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों ने सिंधिया पर नकेल कसने की तैयारी कर दी है और मप्र में उन्हें ग्वालियर में ही सीमित रखने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है।

सिंधिया की उल्टी गिनती!

मप्र की राजनीति में ग्वालियर के महल का दबदबा हमेशा से रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरा महल इस समय कमलदल के साथ है। इस कारण प्रदेश की राजनीति में महल का दायरा बढ़ने के आसार बढ़ गए थे। लेकिन भाजपा आलाकमान ने महल के सबसे बड़े अलमदार ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने की ठान ली है। इसके तहत पार्टी ने उन्हें ग्वालियर तक ही सीमित रखने की रणनीति बनाई है। इसका संकेत इससे भी मिलता है कि सिंधिया की मांग पर उनके समर्थक आईपीएस अधिकारी अनिल शर्मा को ग्वालियर जोन का आईजी बना दिया गया है। उसके बाद सिंधिया ने अन्य जिलों में अफसरों की पदस्थापना के लिए जो भी कदम उठाए हैं, उसे नामंजूर कर दिया गया है।

राजनीतिक मजबूरी चाहे जो हो, लेकिन एक बात साफ होती जा रही है कि मप्र में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता, मंत्री और विधायकों को पचा नहीं पा रहे। कदम-कदम पर यह बात देखने को मिल रही है। इससे सिंधिया समर्थकों में भी उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार महसूस होने का भाव बढ़ता ही जा रहा है। जानकारों के अनुसार भाजपा प्रदेश में खासकर ग्वालियर-चंबल अंचल में अपने क्षत्रपों को किसी भी दबाव में नहीं रखना चाहती है। इसीलिए सिंधिया को ग्वालियर तक ही सीमित रखा जा रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भिंड, मुरैना और प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया सौंप दिया है। जानकारों के अनुसार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की शिकायत और हस्तक्षेप के बाद सिंधिया की उल्टी गिनती शुरू हुई है।

भाजपा नेता सिंधिया समर्थकों को तरजीह देने को लेकर कितने नाराज हैं, इसका अंदाजा भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की कही एक बात से लगाया जा सकता है। भाजपा की नवगठित कार्यकारिणी में सिंधिया समर्थकों को कम स्थान दिए जाने संबंधी संवाददाताओं के सवाल पर मुरलीधर राव एक तरह से लगभग उखड़ ही पड़े और बोले- यह बात ध्यान में रखिए कि हमने अपने बरसों पुराने और अनुभवी नेताओं को पीछे करते हुए सिंधिया के साथ आए नेताओं को मंत्री बनाया है। इस पर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शिवराज सरकार में संतुलन कम है और सिंधिया के साथ भाजपा में आए लोग मंत्रिमंडल में ज्यादा हैं। क्या हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा के नवगठित प्रदेश संगठन में मौका मिल गया, जिन्होंने जी-तोड़ मेहनत करते हुए राज्य में भाजपा के एक करोड़ सदस्य बनाए हैं। मुरलीधर राव के यह तेवर देख जब मीडिया के लोग थोड़ा चौंके तो राव ने बात को संभालते हुए कहा कि दरअसल यह किसी नेता को भाजपा में कम या ज्यादा तवज्जो दिए जाने का मुद्दा ही नहीं है। जो भाजपा में आ गया, उसे तो हम अपना मान चुके। सिंधिया के साथ आए नेताओं में किसी तरह की असुरक्षा की भावना नहीं है। सिंधिया भाजपा में आ गए, तो हम यह मानते हैं कि पूरी भाजपा के नेता हैं। बता दें कि संगठन की इस महत्वपूर्ण बैठक में सिंधिया को भी नहीं बुलाया गया था।

बता दें कि पिछले साल सिंधिया के दो दर्जन समर्थकों ने दलबदल कर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले साल उपचुनाव के दौरान भी सिंधिया समर्थक नेताओं को टिकट देने पर भाजपा में कई जगह बगावत जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी, तब जैसे-तैसे आरएसएस ने दखल देकर बागी तेवर वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाया था। इसके बाद सिंधिया को अपने समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के भोपाल से दिल्ली तक एड़ी-चोटी का जोर कई बार लगाना पड़ा। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक कथन गौर करने लायक है, जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मप्र में कांग्रेस की सरकार गिराई थी। यानी कांग्रेस की सरकारों को अलग-अलग समय में गिराने वाला पूरा सिंधिया वंश आज भाजपा में है। लोग इसका एक अर्थ यह भी निकालते हैं कि धोखा देने और स्वार्थ के लिए दलबदल करना सिंधिया के डीएनए में है।

सिंधिया कांग्रेस में थे, तो उनका अलग सम्मान था। वो शायद अब भाजपा में नहीं मिल रहा, चाहे मंत्री बनवाना हो या संगठन में अपनों को जगह दिलवाना, बहुत ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि ग्वालियर-चंबल अंचल में जिन 7 नेताओं को निगम-मंडल में अध्यक्ष बनाया गया है, वह सभी सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। लेकिन अब भाजपा उनको और देने को तैयार नहीं है।

● रजनीकांत पारे

केपी यादव ने भी खोला सिंधिया के खिलाफ मोर्चा

लोकसभा चुनाव में सिंधिया को हराने वाले केपी यादव ने ग्वालियर-चंबल संभाग में सिंधिया और उनके समर्थकों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोला है। सांसद केपी यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में अपना दर्द बयां किया है। नड्डा को भेजे पत्र में उन्होंने सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर गुटबाजी और भेदभाव करने का आरोप लगाया। यह पत्र सार्वजनिक होने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यादव ने पत्र में लिखा कि सिंधिया समर्थकों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मेरी और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। उन्हें कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता। प्रोटोकॉल के अनुसार उद्घाटन, लोकार्पण कार्यक्रम की शिलापट्टिका पर भी जगह नहीं दी जा रही है। कई ऐसे काम होते हैं, जिन्हें उनके प्रयासों से मंजूरी मिली है। यादव ने लिखा है कि सिंधिया समर्थक मंत्री उनकी अध्यक्षता में होने वाली बैठकों का लगातार बॉयकॉट कर रहे हैं। पत्र में लिखा गया है कि पार्टी कार्यक्रमों के संदर्भ में पोस्टर, बैनरों को लगाते समय भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता।

कैलारस चीनी मिल का हुआ कबाड़ा

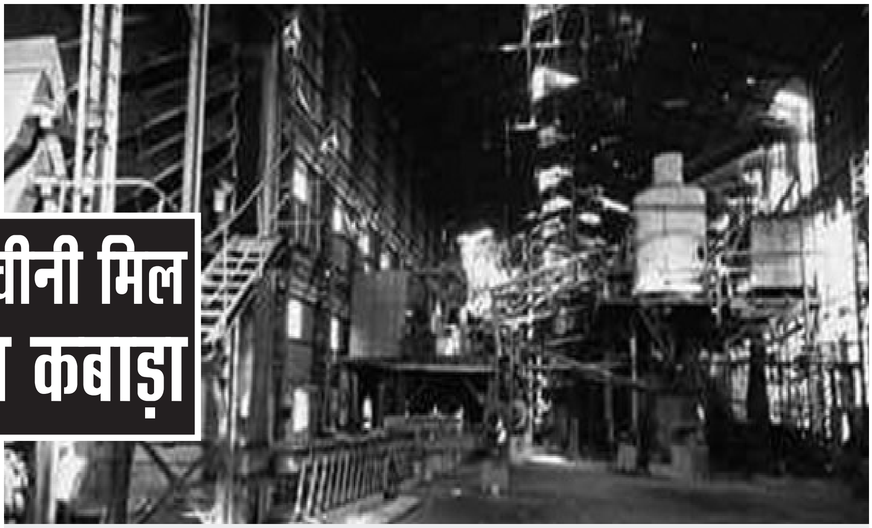

चंबल अंचल की पहली फैक्ट्री कैलारस चीनी मिल अब इतिहास बनकर रह जाएगी। चीनी मिल को बचाने के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शनों से लेकर किसान-व्यापारियों द्वारा अपने खर्च से बंद पड़े मिल को चलाने के सारे प्रयासों पर सरकार ने विराम लगा दिया है। ऑनलाइन हुई नीलामी में 15 साल से बंद पड़े कैलारस चीनी मिल के कबाड़े को 13.04 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। कैलारस चीनी मिल की मशीनरी, शेड आदि को खरीदने वाले व्यापारी जल्द ही इसे यहां से उठा लेंगे, फिर यहां सपाट मैदान रह जाएगा।

कैलारस चीनी मिल की स्थापना का निर्णय 1967 में हुआ और 1970 में यह कारखाना बनकर तैयार हुआ। 1972 से इसमें चीनी उत्पादन शुरू हो गया। मिल से हर रोज 1800 से 2000 बोरी शक्कर उत्पादन होता था। कैलारस मिल की शक्कर का दाना बड़ा व सफेद होता था, जिसकी खासी मांग थी, पर घाटे में बताकर 15 साल पहले इस पर ताला जड़ दिया गया। बीते 6 साल से इसे कंडम घोषित कर कबाड़ में बेचने की तैयारी चल रही थी। चीनी मिल को फिर से शुरू करने के लिए ग्वालियर-चंबल के व्यापारी व किसान आगे आए, जिन्होंने बंद पड़े मिल को अपने खर्च से चलाने के लिए 47 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान करते हुए 46 लाख रुपए के चेक भी एडवांस में दे दिए। किसान नेताओं का एक दल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने गया, उसके बाद एक दल ने गत दिनों भोपाल में जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया व सहकारिता के एससीएस अजीत केसरी से मिलकर ऑनलाइन नीलामी को रुकवाने की गुहार लगाई, पर किसी भी चौखट पर किसान नेताओं की बात पर अमल नहीं हुआ और आनलाइन बोली में कैलारस चीनी मिल 13 करोड़ 4 लाख 1 हजार रुपए में बिक गया।

कैलारस चीनी मिल के कबाड़े के रूप में बिक जाने के खिलाफ आंदोलनों का भी ऐलान होने लगा है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ जल्द ही जेलभरो आंदोलन करने को कहा है, इस विरोध प्रदर्शन के लिए मुरैना के कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से समय मांग रहे हैं। दूसरी तरफ कैलारस-जौरा के किसान नेता जो बीते एक महीने से नीलामी का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने नीलामी के खिलाफ डेरा डालो-घेरा डालो अभियान करने का ऐलान कर दिया है। 28 फरवरी को यह आंदोलन कैलारस चीनी मिल में ही होगा, जिसके तहत शक्कर मिल को बचाने के लिए उसकी घेराबंदी करके सैकड़ों लोग बैठेंगे और नीलामी को निरस्त कराने की मांग करेंगे।

बीते 15 सालों में हुए हर विधानसभा, लोकसभा व उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सरकार बनने के बाद कैलारस चीनी मिल को फिर से शुरू कराने के वादे किए। इन 15 सालों में भाजपा व कांग्रेस दोनों की सरकारें बनीं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी ने सुध नहीं ली। 7 साल पहले सरकार ने शक्कर मिल को पीपीपी मॉडल पर चलाने के प्रयास शुरू किए, इसके बाद डबरा और उप्र के बरेली के एक व्यवसायी ने अपने खर्च पर, मप्र सरकार व सहकारिता की शर्तों के अनुसार शक्कर मिल को चालू कराने की इच्छा जताई थी। दोनों उद्योगपतियों से तत्कालीन संभाग आयुक्त शिवानंद दुबे ने प्रस्ताव भी लिए, लेकिन यह फाइलें इस तरह दबाई गईं, कि दोबारा उन पर चर्चा नहीं हुई।

कैलारस चीनी मिल में 5 करोड़ रुपए की ऐसी खरीदी हुई है, जिसकी कोई सामग्री कारखाने में नहीं आई। कागजों में सामान खरीदना बता दिया। कैलारस चीनी मिल की 120 बीघा जमीन उद्योग विभाग की है। इसमें से आधी जमीन को खेती के लिए किराए पर दे दिया गया है। नियम यह है, कि नीलामी से पहले चीनी मिल प्रबंधन व सहकारिता विभाग को उद्योग विभाग से अनुमति लेनी थी, वह नहीं ली गई और बिना उद्योग विभाग की अनुमति से जमीन को खेती के लिए किराए पर दे दिया गया है। शहर मिल की मशीनरी व शेड को नीलाम करने से पहले मूल्यांकन में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। नीलामी के लिए फैक्ट्री की मशीनों व शेड की कीमत 2 करोड़ 78 लाख रुपए आंकी गई। जब नीलामी हुई तो यही सामान 13 करोड़ से ज्यादा, यानी मूल्यांकन से चार गुना अधिक में बिकी है। इससे मूल्यांकन करने व करवाने वालों की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

घाटे में पहुंचाने 5 करोड़ की हुई फर्जी खरीदी

कैलारस चीनी मिल को 35 करोड़ के घाटे में बताने में भी भारी गफलत हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2008 में सरकार फिर से इसे शुरू करने के लिए अचानक शक्कर मिल संचालक मंडल के चुनाव करा दिए। उस समय बंद पड़े कारखाने को चालू करवाने के लिए मात्र 25 लाख रुपए की जरूरत बताई गई थी, लेकिन सरकार या किसी संस्था ने यह रकम नहीं दी। 2013 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री ने इसे शुरू करने का वादा किया और 2018 में अचानक से आई एक ऑडिट रिपोर्ट में इसे 30 करोड़ के घाटे में दिखाया गया है, जो अब 35 करोड़ तक बताया जा रहा है। मुरैना शक्कर मिल से जुड़े किसान नेता सोहनलाल धाकड़ का कहना है कि 35 करोड़ घाटे की बातें काल्पनिक और षड्यंत्र का हिस्सा हैं। इसमें 5 करोड़ की ऐसी खरीद दर्ज है, जिसका कोई सामान कभी कारखाने में आया ही नहीं है। यह सामान कहां है, किसने खरीदा किसी को नहीं पता। किसान नेता अशोक तिवारी कहते हैं कि कारखाने को चालू हालत में बंद किया गया है। सहकारिता विभाग और सरकार ने ही नहीं चाहा कि यह मिल चालू हो। किसानों से झूठे वादे किए गए और अब इसे नीलाम कर दिया गया है। इसके खिलाफ हम डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन करने वाले हैं। कांग्रेस नेता पंकज उपाध्याय का कहना है कि शक्कर कारखाने को नीलाम करना पूरी जनता के साथ धोखा है। क्षेत्र की जनता 8 फरवरी को धिक्कार दिवस के रूप में याद रखेगी। इस नीलामी के खिलाफ कांग्रेस भी बड़ा आंदोलन करेगी। हम पार्टी के बड़े नेताओं से इसके लिए समय ले रहे हैं।

अकेले पड़े कमलनाथ!

महज 15 महीनों में अपनी सरकार से हाथ धो बैठी मप्र कांग्रेस में अभी गुटबाजी कम होते नहीं दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मिशन-2023 को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। इसके लिए 1 फरवरी से घर चलो, घर-घर चलो अभियान का आगाज किया गया है। लेकिन इस अभियान पर भी कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का असर पड़ता दिख रहा है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अकेले पड़ते दिख रहे हैं। अभी तक कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता इस अभियान के साथ नहीं जुड़े हैं। कांग्रेस अपने घर चलो घर-घर चलो अभियान को सफल बनाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। उधर, भाजपा अपनी रणनीति के अगले चरण में पहुंच गई है। भाजपा ने मिशन 2023 के लिए नए चरण का आगाज कर दिया है। पार्टी को मजबूत करने पहले बूथ विस्तारक योजना शुरू की गई। इसे आगे बढ़ाते हुए अब समर्पण निधि जुटाई जाने लगी है। मप्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का गत दिनों भोपाल में कार्यक्रम हुआ। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मप्र कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी का कांग्रेस के घर चलो, घर-घर चलो अभियान के तहत एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी इस अभियान से नहीं जुड़ सके हैं। कांग्रेस ने यह अभियान अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धि घर-घर तक पहुंचाने और **शिवराज सरकार की कमियां** बताने के उद्देश्य से शुरू किया। लेकिन बड़े नेताओं ने इससे दूरी बना रखी है।

खास बात यह है कि मप्र कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके इस अभियान को सोशल मीडिया पर प्रमोट नहीं कर रहे हैं। पहले सिर्फ अरुण यादव ने एक पोस्ट कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से इस अभियान से जुड़ने की अपील की थी। इसके अलावा अन्य नेता सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखे। हालांकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और सज्जन वर्मा पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि इस अभियान को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लोगों से युद्धस्तर पर जनसंपर्क किया जा रहा है। इसलिए अभियान की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च की गई है। मप्र कांग्रेस के नेता उप्र सहित 5 राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। यह सभी आने वाले दिनो में इस अभियान से जरूर जुड़ेंगे।

प्रदेश में एक तरफ भाजपा ने 17 दिनी बूथ विस्तारक योजना का सफल समापन करने के बाद समर्पण राशि अभियान का आगाज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दिनभर चले अढाई कोस वाली बनी हुई है। गौरतलब है कि भाजपा से पहले कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू किया था, फिर घर-घर चलो अभियान शुरू किया है। लेकिन पार्टी के नेता किसी भी अभियान को गति नहीं दे पा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पदाधिकारियों की सुस्ती देख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी इन दिनों निराश हैं। इसकी एक वजह यह है कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस की राजनीति में सब तरफ उथल-पुथल चल रही है। प्रदेश में एक तरफ संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर में शहर कांग्रेस के इतिहास में पहली बार एक साथ दो-दो महिला शहर अध्यक्ष बना दी गईं। इस पर भाजपाइयों की सोशल मीडिया टीम जब चटखारे ले रही है और कह रही है कि भाजपा की संगठन, बूथ और मतदान केंद्र स्तर की टीम को उसी की तर्ज पर टक्कर देने की कोशिश कांग्रेस नेता खूब करते हैं लेकिन दिनभर चले अढाई कोस पर ही थम जाते हैं।

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रदेश कांग्रेस जुट गई है। घर चलो, घर-घर चलो अभियान चलाने के साथ-साथ उद्योग जगत से लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों तक अपनी पैठ बनाने के लिए पार्टी ने सहयोगी संगठन बनाए हैं। इसमें फुटकर एवं लघु व्यापारी, समाजसेवी कल्याण, वरिष्ठ नागरिक, सांस्कृतिक, त्योहार एवं उत्सव, कृषि, विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति, दिव्यांग, बूथ प्रबंधन, जन समस्या जैसे प्रकोष्ठ शामिल हैं। मकसद यही है कि चुनाव से पहले हर वर्ग को पार्टी से जोड़ लिया जाए। इसके लिए सम्मेलन करने के साथ अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे।

चुनावी तैयारी के मद्देनजर प्रदेशभर में बूथ, मंडलम और सेक्टर का गठन किया जा रहा है। आदिवासी वर्ग में पैठ बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लामबंद करने की कार्ययोजना बनाई गई है। इसके तहत भोपाल में एक सम्मेलन भी हो चुका है। इसके साथ ही नए प्रकोष्ठ गठित करके विभिन्न वर्गों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी पूर्व आईएएस अधिकारी डीएस राय को सौंपी गई है। राय पहले भी संगठन के लिए काम करते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी वीके बाथम और राजेश मिश्रा भी संगठन का काम देख रहे हैं। वहीं, वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी डॉ. एसपी तिवारी को दी गई है। इसी तरह छोटे उद्योग संचालित करने वालों से संपर्क करने और उन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए पहली बार फुटकर एवं लघु व्यावसायिक प्रकोष्ठ गठित किया गया है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

सभी वर्गों तक पार्टी की सीधी पहुंच बनाने के निर्देश

संगठन के महामंत्री और प्रकोष्ठों के प्रभारी जेपी धनोपिया का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी वर्गों तक पार्टी की सीधी पहुंच बनाने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक तौर पर पिछड़े समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए समाज समन्वय प्रकोष्ठ बनाया गया है। ये सामाजिक संगठनों से संपर्क करेगा और उन व्यक्तियों को चिन्हित करेगा जिन्हें आगे लाया जा सकता है। इसी तरह वरिष्ठों को पार्टी से जोड़ने के लिए वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी जहीर अहमद को दी गई है। इसके साथ दिव्यांग, ग्रामोद्योग, डॉक्टर एवं चिकित्सा, महिला उत्पीड़न निवारण सहित अन्य प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। संगठन की गतिविधियों की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में होगी। इसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें संगठन पदाधिकारियों से उनके द्वारा किए गए कामों का लेखा-जोखा लेकर नए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

खंडवा बना अवैध हथियारों की मंडी

निमाड़ अंचल अवैध हथियारों का गढ़ बनते जा रहा है। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का निर्माण हो रहा है और इन अवैध हथियारों की मंडी के रूप में खंडवा सामने आ रहा है। चारों जिलों में पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इन पर रोक लगाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। अवैध हथियारों की तस्करी में अब तक महज कोरियर ही पकड़ में आ रहे हैं। मुख्य सरगना हमेशा ही पुलिस गिरफ्त से बाहर रहता है। खंडवा के रास्ते निमाड़ के अवैध हथियार अन्य प्रदेशों तक भी पहुंच रहे है। पिछले पांच सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो जितने भी मामले अवैध हथियारों के पुलिस ने ट्रेस किए हैं, उसमें से 95 प्रतिशत मामलों में खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर के सिकलीगरों द्वारा हथियारों का निर्माण किया गया था। खरगोन के सिगनुर, सिंगुल, चैनपुरा, बड़वानी के उमर्टी और बुरहानपुर के पाचोरी में बसे सिकलीगरों द्वारा अवैध हथियार निर्माण की फैक्ट्री लगा रखी है। इन गांवों में अवैध हथियार लघु उद्योग की तरह बनाए जाते हैं। हथियारों को बेचने के लिए खंडवा और अन्य जिलों के जिला मुख्यालय का इस्तेमाल किया जाता है। खंडवा तीनों जिलों के बीच में और रेल मार्ग की सुगमता के चलते अवैध हथियारों का पासिंग स्टेशन भी बनता जा रहा है।

सिकलीगरों द्वारा बनाए गए हथियारों की मांग मप्र के चंबल क्षेत्र भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जबलपुर सहित पंजाब, उप्र, हरियाणा, राजस्थान, बिहार तक है। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार इन क्षेत्रों में बिकने पहुंचते हैं या वहां से अपराधिक तत्व खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर पहुंचते हैं। खरगोन में तो हाल ही में पुलिस ने पंजाब, हरियाणा से हथियार खरीदने आए अपराधियों को पकड़ा भी है। वहीं, पिछले साल ग्वालियर, जबलपुर और उप्र में हुई अवैध हथियारों की कार्रवाई में बड़वानी और खरगोन के सिकलीगरों का ही नाम सामने आया था।

निमाड़ में अवैध हथियार निर्माण के बाद मप्र के साथ ही अन्य प्रदेशों के जिलों में भी बेचे जाते हैं। इसके लिए अवैध हथियारों के सौदागर अपने क्षेत्र के बेरोजगार आदिवासी युवाओं का कोरियर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक पिस्टल की डिलेवरी पर कोरियर को 2 हजार रुपए मिलता है। पिछले दो सालों में हुई कार्रवाईयों में अधिकतर पकड़े गए आरोपी कोरियर ही थे। सिकलीगरों द्वारा नल के पाइप व अन्य सामान से देशी पिस्टल तैयार की जाती है। एक देशी पिस्टल की कीमत ढाई से पांच हजार होती है। दलाल के माध्यम से अपराधी तक पहुंचने पर पिस्टल की कीमत 8 से 10 हजार रुपए हो जाती है। अब अवैध हथियारों के सौदागर पिस्टल के साथ कारतूस भी उपलब्ध कराने लगे हैं। जिसके चलते सिकलीगरों के हथियारों की मांग ज्यादा है।

खरगोन के सिगनुर निवासी लखन सिकलीगर बीएसएफ में जवान था और नौकरी छोड़कर वापस खरगोन आ गया था। फौजी के नाम से कुख्यात लखन ने ही सिकलीगरों के हथियारों के बिक्री का जाल पंजाब, हरियाणा तक फैलाया था। जिसके बाद बड़ी संख्या में अपराधिक किस्म के लोगों का खरगोन, बड़वानी में आना-जाना लगा रहता था। फिलहाल लखन फौजी हथियारों की तस्करी में जेल की सलाखों के पीछे है। पिछले साल खरगोन पुलिस ने 31 जनवरी को पंजाब बिकने जा रहे अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी थी। कसरावद-बामंदी के बीच बलकवाड़ा पुलिस ने 27 पिस्टल और दो जिंदा कारतूस के साथ चार आरोपियों को पकड़ा था। इसमें तीन सिकलीगर और एक आदिवासी था। 27 जनवरी 2022 को इंदौर क्राइम ब्रांच ने इंदौर बस स्टैंड से दो सिकलीगरों को पकड़ा था। जिनके पास से 4 देशी कट्टे, 6 देशी पिस्टल और 200 जिंदा कारतूस मिले थे। बड़वानी के अंजड़ निवासी इन सिकलीगरों के घर से भी हथियार, जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया था। खंडवा में मोघट पुलिस ने 26 दिसंबर को सिहाड़ा रोड पर तीन आरोपियों को 6 पिस्टल के साथ पकड़ा था। खालवा निवासी ये तीनों आरोपी सिकलीगरों से पिस्टल खरीदकर खंडवा में बेचने की फिराक में थे। वहीं, 4 फरवरी को भी मोघट पुलिस ने दो पिस्टल के साथ दो आरोपियों को पकड़ा था। डीआईजी निमाड़ रेंज तिलक सिंह का कहना है कि अवैध हथियारों को लेकर निमाड़ के चारों जिलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध हथियारों की खरीदी के लिए आए पंजाब, हरियाणा के आरोपियों को भी पकड़ा है। अवैध हथियार निर्माण पर रोक लगाने के लिए सिकलीगरों के पुर्नवास की योजना भी बनाई जा रही है।

● विकास दुबे

मप्र में ड्रग्स तस्करी चार गुना बढ़ी

मप्र नशीले पदार्थों की तस्करी का गढ़ बन रहा है। साल दर साल नशीले पदार्थों की बरामदगी की मात्रा बढ़ती जा रही है। चिंता की बात यह है कि बीते 13 महीने में नशे की जब्त खेप में चार गुना का उछाल आ चुका है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) की मप्र यूनिट ने 2021 से जनवरी 2022 तक 38 हजार किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ पकड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मात्रा 2018 में पकड़े गए नशीले पदार्थों के मुकाबले करीब 12 गुना है। पहली बार सीबीएन द्वारा पकड़े जा रहे नशीले पदार्थों की सूची में अब सिंथेटिक ड्रग्स भी दिखाई देने लगी है। नशे के खिलाफ काम कर रहे इस केंद्रीय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ड्रग्स तस्करी की खेप भले की छोटे शहरों और गांवों में बरामद हो रही है लेकिन तस्कर इस खेप को बड़े शहरों में खपा रहे हैं। युवा सबसे ज्यादा इनके निशाने पर हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स 2019 तक की कार्रवाईयों के दौरान अफीम, डोडा-चूरा और गांजे जैसे परंपरागत नशीले पदार्थ पकड़े जाते रहे हैं। 2021 की कार्रवाई में पहली बार इस सूची में एमडी जैसी बेहद महंगी और नशीली सिंथेटिक ड्रग्स भी नजर आई। सीबीएन ने नवंबर 2021 में 13 किलो 900 ग्राम एमडी ड्रग्स का पावडर पकड़ा जो अब तक की सबसे बड़ी खेप है। सीबीएन के मप्र यूनिट के अधिकारियों के अनुसार सिर्फ इतना ही नहीं बीते 6 महीनों में ही 17 हजार 535 किलो अफीम, 17950 किलो डोडा-चूरा, 680 किलो गांजा और 650 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। तस्करी कर रहे 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ड्रग्स तस्करी के बढ़ते मामलों के सीबीएन के आंकड़े इंदौर-भोपाल जैसे महानगरीय परिवेश वाले बड़े शहरों को चौकन्ना होने का इशारा भी कर रहे हैं।

15वीं विधानसभा का चौथा बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। 25 मार्च तक चलने वाले सत्र में सरकार बजट पेश करेगी। इस बार के बजट में मिशन 2023 की झलक देखने को मिलेगी। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पौने दो साल बचे हैं। इसलिए सरकार की कोशिश है कि बजट में विकास योजनाओं के साथ ही रोजगार और हर वर्ग को साधने की कवायद की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना के कारण पिछले दो साल से पूरे देश में आर्थिक मंदी का माहौल है। मप्र भी इससे अछूता नहीं है।

बजट में दिखेगा चुनावी झलक

मप्र सरकार का फोकस है कि वर्ष 2022-23 का बजट ऐसा हो जो आत्मनिर्भर मप्र अभियान को पूरा करने में मददगार हो। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे बजट में ऐसी चीजें समाहित करें, जिससे आत्मनिर्भर मप्र को बल मिले। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर वित्त विभाग ने मार्च में प्रस्तुत होने वाले बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह उत्साहित दिख रहे हैं, उससे तो यह साफ हो गया है कि प्रदेश का बजट आत्मनिर्भर मप्र पर आधारित होगा। शिवराज सरकार का आगामी बजट निश्चित रूप से प्रदेश की दिशा तय करने वाला होगा।

मुख्यमंत्री का मानना है कि बजट केवल आय-व्यय का ब्यौरा नहीं है, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। समृद्ध और विकसित मप्र का निर्माण बजट के माध्यम से ही होता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। बजट संचालक आईरीन सिंथिया का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर मप्र के लिए विभाग की योजनाओं, कार्यक्रम एवं उपलब्धि तथा लक्ष्य सहित विभाग से सुझाव मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री की मंशानुसार देश की अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदम की जानकारी बजट सुझाव में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट शिवराज सरकार के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इस मायने में कि राज्य में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके मुकाबले आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। जनता को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य को संकट से उबारने में मदद मिली है। हालांकि वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत अभी भी है। प्रदेश का बजट इस बार ढाई लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। स्वयं का राजस्व बढ़ाने पर सरकार द्वारा जोर दिया जाएगा। साथ ही विभागों को बजट से अतिरिक्त भी वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में तीन प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से प्रविधान रखे जाएंगे तो महंगाई भत्ते के लिए वेतन मद में कुल प्रस्तावित राशि का 32 प्रतिशत हिस्सा रखा जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

अब तक की तैयारियों से माना जा रहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट के जरिए सरकार बड़ा संकल्प जाहिर कर सकती है। सरकार के लिए यह बजट चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी है। माना जा रहा है कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मप्र का खाका खींचने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस बार का बजट अवसर सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि जोखिम लेकर अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं, वे सभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित हुए हैं। कोरोना संकट से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। लगभग सभी क्षेत्रों में **राजस्व संग्रहण** में वृद्धि हो रही है। यह शुभ संकेत हैं, क्योंकि सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, उसके लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक जरूरत होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को अतिरिक्त आय सृजित करने के लक्ष्य भी दिए हैं। जीएसटी के बाद राज्य के पास टैक्स लगाने का दायरा सीमित हो गया है। ऐसे में उन विकल्पों पर विचार करना होगा, जिनके माध्यम से सरकार जनता पर कर का बोझ बढ़ाए बगैर आय बढ़ा सकती है। यही

विभागों के बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार विभागों के बजट में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकती है। प्रदेश में अनुमाति बजट में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का बजट होने की संभावना है। विभाग वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति का बजट 24,911 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2022-23 में 27,920 का बजट अनुमानित है। वहीं इस बार बजट में अनुसूचित जाति का बजट 9,780 करोड़, प्राथमिक स्कूल निर्माण 10,772 करोड़, जल जीवन मिशन 6,338 करोड़, माध्यमिक स्कूल 6,300 करोड़, ऊर्जा विभाग 11,241 करोड़, कृषि कल्याण 15,200 करोड़, स्वास्थ्य व्यवस्था 6,600 करोड़, शहरी विकास 12,100 करोड़, एनवीडीए 3,000 करोड़ अनुमानित है। उधर लोगों की मांग है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा का बजट के बजट को बढ़ाए, पेट्रोल-डीजल पर वेट कम करे, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। महंगाई पर भी अंकुश लगेगा। परीक्षाओं का शुल्क सिर्फ 50 रुपए हो, सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में तार्किक शिक्षा, आधुनिक ट्रेनिंग और भ्रष्टाचार उन्मूलन पर निवेश बढ़ाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में इजाफा किया जाए। सरकार नियमितीकरण में प्राथमिकता दे।

वजह है कि मुख्यमंत्री ने देशभर के नामचीन विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन के बाद आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप तैयार किया है। इसमें सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विषम परिस्थितियों में बेहतर प्रबंधन करते आए हैं, वैसा ही इस दौर में भी वे बजट के माध्यम से करेंगे। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने के साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कदम उठाने से वह नहीं झिझकेंगे।

बजट भाषण के लिए सभी विभागों से आत्मनिर्भर मप्र को लेकर किए गए कामों का ब्यौरा मांगा गया है। दरअसल, बजट के माध्यम से सरकार यह बताएगी कि मप्र ने आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। चाहे निवेश बढ़ाना हो या अधोसंरचना विकास के काम हों, प्रदेश किसी राज्य से पीछे नहीं है। कृषि के क्षेत्र में भी लगातार विस्तार हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, चना, मसूर, सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी गई। इससे किसानों को सुविधा मिली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगने वाली ऑक्सीजन के लिए लगभग 200 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। चार नए मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अटल प्रोग्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी बजट प्रस्तावों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही हैं। सभी विभागों से वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रमों के अंतर्गत आत्मनिर्भर मप्र की योजनाएं और उनकी उपलब्धियां मांगी गई हैं।

मप्र के बजट में इस बार जनता से सुझाव शिवराज सरकार ने मांगे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म कू पर मप्र सरकार ने शिक्षा पर हो बल, सुरक्षित हो कल शीर्षक के साथ जनता से सुझाव मांगने के लिए आग्रह किया है। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य सरकार ने बजट में क्या हो इसके लिए सुझाव मांगे हो। इसके लिए बताया जा रहा है कि प्रयास यही है कि बजट सभी के लिए बेहतर हो, हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। हालांकि सरकार विशेषज्ञों की राय भी ले रही है, विभागीय स्तर पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं है। कॉलेज बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसके लिए सरकार बजट में विशेष प्रावधान करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर मप्र सरकार ने शिक्षा पर हो बल, सुरक्षित हो कल शीर्षक से एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि शिक्षित बच्चे ही भविष्य में देश-प्रदेश की उन्नति का आधार बनेंगे। उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए बजट में योजनाएं बनाना भी जरूरी है। नए वित्त वर्ष के इस बजट की खासियत यह होगी कि उसमें पूरी तरह से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इस बजट में आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप की पूरी झलक दिखेगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने विभाग से जुड़े प्रस्तावों को आत्मनिर्भर मप्र के तहत ही तैयार करने के लिए कहा है।

वर्ष 2023 में मप्र का विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि इस बार के बजट में जनता को अधिक से अधिक सहूलियतें प्रदान की जाएं। इसलिए इस बार के बजट में जनता के लिए कई प्रकार की सौगातें मिलने की संभावना हैं। राज्य की वित्तीय स्थितियों के जानकार मानते हैं कि आगामी बजट का फायदा मुख्यमंत्री एक अवसर की तरह उठाने की कोशिश करेंगे। इसे ध्यान में रखकर ही बजट की तैयारी भी हो रही है। आत्मनिर्भर मप्र के तहत तय किए लक्ष्यों को वर्ष 2023 तक पूरा करने के लिए विभागवार राशि का प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त आय के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा 15 जनवरी के बाद बजट भाषण में शामिल किए जाने वाले विषयों पर चर्चा के लिए बैठक करेंगे। वर्ष 2021-22 में सरकार ने कोरोना संकट के दौरान आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इसके लिए अधोसंरचना विकास के कामों पर सर्वाधिक ध्यान दिया था। इसकी वजह से केंद्र सरकार से प्रदेश को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए अधिक भी मिले हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों को रोजगार फिर से जमाने के लिए बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण दिलाया गया। सरकार का फोकस सबसे अधिक युवा वर्ग पर है।

● राकेश ग्रोवर

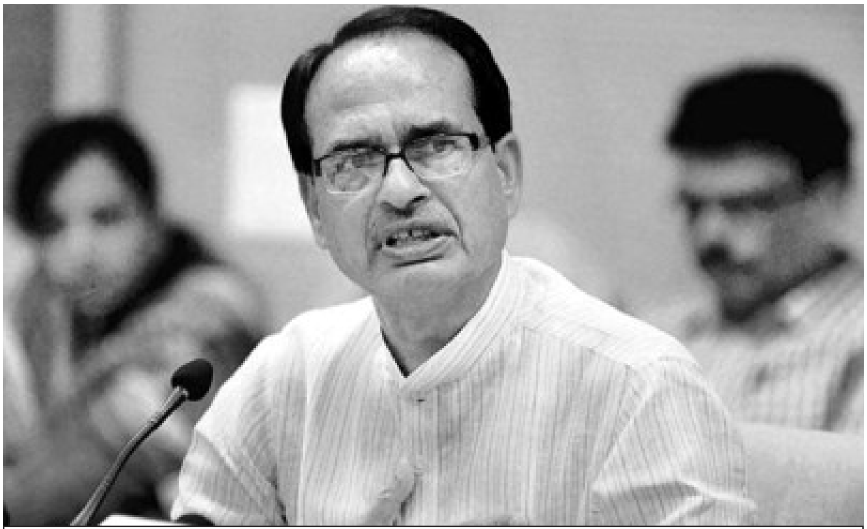

बजट के लिए जनता से सुझाव

मप्र के बजट में इस बार शिक्षा को प्राथमिकता, जनता से सुझाव शिवराज सरकार ने मांगे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म कू पर मप्र सरकार ने शिक्षा पर हो बल, सुरक्षित हो कल शीर्षक के साथ जनता से सुझाव मांगने के लिए आग्रह किया है। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य सरकार ने बजट में क्या हो इसके लिए सुझाव मांगे हो। इसके लिए बताया जा रहा है कि प्रयास यही है कि बजट सभी के लिए बेहतर हो, हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। हालांकि सरकार विशेषज्ञों की राय भी ले रही है, विभागीय स्तर पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं है। कॉलेज बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसके लिए सरकार बजट में विशेष प्रावधान करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म कू पर मप्र सरकार ने शिक्षा पर हो बल, सुरक्षित हो कल शीर्षक से एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि शिक्षित बच्चे ही भविष्य में देश-प्रदेश की उन्नति का आधार बनेंगे। उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए बजट में योजनाएं बनाना भी जरूरी है। कोरोनाकाल के बाद से लोग स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हुए हैं, ऐसी ही गंभीरता वे सरकार से भी चाहते हैं। इसलिए स्वास्थ्य बजट में इजाफा किए जाने का सुझाव दिया गया है। सरकार बजट में ऐसी व्यवस्था करे, जिससे प्रदेश कॉलोनी व मोहल्ले में एक स्वास्थ्य क्लीनिक खोला जाए। जिसमें एक-एक चिकित्सक, नर्सिंग स्टॉफ, टेक्नीशियन पदस्थ किए जाएं। ताकि कोविड जैसे अन्य रोगों के उचित उपचार या परामर्श तत्काल मिल सके।

आउटसोर्सिंग के जाल में बेरोजगार युवा

प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, उसके बाद भी सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े एक लाख से ज्यादा नियमित पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। यही नहीं सरकार ने विभागों का काम करीब 25 एजेंसियों को सौंप दिया है जो आउटसोर्सिंग के जरिए युवाओं को विभाग में पदस्थ करवाते हैं। इस तरह बेरोजगार युवा आउटसोर्सिंग के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में एक तरफ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी, यहां तक तो ठीक था, फिर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन देने के नाम पर संविदा नियुक्ति की परंपरा शुरू हो गई। वहीं प्रदेश में विभिन्न विभागों में एक लाख से ज्यादा नियमित पद खाली हैं, जिन्हें सरकार नहीं भर रही है। सरकार ने पहले नियमित भर्ती के स्थान पर कर्मचारियों की संविदा पोस्टिंग शुरू की और अब संविदा नियुक्ति को समाप्त कर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की जा रही है।

आउटसोर्सिंग के जरिए युवाओं का हर तरह से शोषण किया जा रहा है। न उनके काम के घंटे तय हैं, न वेतन फिक्स है और न ही नौकरी की कोई गारंटी है। सेवा से कब आउट कर दिया जाए, उन्हें खुद नहीं मालूम। प्रदेश में सरकार से जुड़े लोगों की करीब 25 एजेंसियां हैं, जो कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग करती हैं। ये युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें निर्धारित राशि से कम वेतन का भुगतान करती हैं। उन्हें दिए जाने वाले वेतन में से कमीशन काटा जाता है। कई बार काम पर रखने वाले युवाओं से सिक्युरिटी मनी के नाम पर पैसे भी लिए जाते हैं। इन सबके बीच बेरोजगार युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। राजधानी में हाल में बेरोजगारी से तंग आकर युवाओं की जान देने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

दरअसल, युवाओं को परमानेंट सरकारी नौकरी न देनी पड़े, इसके लिए अफसरों ने आउटसोर्सिंग का नया फार्मूला निकाल दिया है। इसमें जिस सरकारी विभाग को जितने कर्मचारियों की जरूरत होती है, उतने वे किसी एजेंसी से ले लेते हैं। ऐसे में युवा को वेतन तो अल्प मिलता ही है, वह कभी भी नियमित होने का हकदार नहीं हो पाता। उसकी नौकरी कंपनी के कर्ताधर्ताओं की जुबान पर तय रहती है। वे जब चाहते हैं, उसे बाहर कर देते हैं। दिलचस्प यह भी है कि विभागों को कर्मचारी-अधिकारी देने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियां भी विभाग के अफसरों से मिलकर काम कर रही हैं। ये विभाग के अफसरों को ही रिटायर होने के बाद आउटसोर्सिंग पर रख देती हैं।

प्रदेश मे पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 35 लाख है, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। दो साल से कोई सरकारी भर्ती नहीं हुई है। इस दरमियान प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तीन परीक्षाएं निरस्त कर चुका है। बेरोजगारी का आलम यह है कि भृत्य और ड्राइवर की भर्ती के लिए हजारों आवेदन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही है। इस दिशा में कार्य अभी शुरू हुआ है। सरकारी नौकरियों में पद सीमित हैं और सरकार लाखों बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे नहीं सकती। इसलिए वह उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की बात कह रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हर माह एक लाख बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए मेले लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति सहित कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक बड़ी बाधा है। सरकार की ओर से गारंटी लिए जाने के बाद भी बैंक लोन मंजूर नहीं करते। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी अधिकारी यह बात ला चुके हैं। प्रदेश में 1.20 लाख संविदाकर्मी पदस्थ हैं। ये लगभग सभी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। कुल संविदाकर्मियों में से 75 फीसदी को सेवा देते हुए 15 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इन्हें नियमित करने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, इससे इनका भविष्य अधर में लटका है। शिवराज कैबिनेट ने जून, 2018 में संविदाकर्मियों के लिए पॉलिसी मंजूर की थी। इसमें कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य सुविधाओं के संबंध में प्रावधान किए गए थे, लेकिन संविदाकर्मियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

राज्य में रोजगार मांगने वालों की संख्या पर नजर डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि यह संख्या बढ़ी है। पांच माह पूर्व शुरू हुए ई-श्रम पोर्टल के मुताबिक मप्र से करीब 1 करोड़ लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि राज्य में हर माह एक लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए सस्ता कर्ज से लेकर तकनीकी सहयोग सहित अन्य सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। वहीं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। एक साल में 44 हजार की भर्ती हो चुकी है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

मप्र में मनरेगा बना बेरोजगारों का संबल

मप्र में मनरेगा बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा संबल बना हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लोकसभा में दी गई जानकारी में यह तथ्य सामने आया है। जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने मप्र को खुले दिल से राशि दी, मप्र भी खर्च करने में पीछे नहीं है। खर्च की स्थिति यह है कि मप्र टॉप फाइव राज्यों में शामिल है। यह इस बात का संकेत है कि प्रदेश में मनरेगा के तहत खूब काम हो रहा है और ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के प्रयास हो रहे हैं। राज्य में जिस गति से रोजगार पाने वालों की संख्या में दिनोंदिन इजाफा हो रहा है, उस तुलना में रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है। प्रदेश में काम मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। वहीं सरकार का प्रयास भी है अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। यही कारण है कि मनरेगा के तहत मप्र ने वितीय वर्ष 2019-20 में 4949.34 करोड़ रुपए राशि खर्च की थी। इसके अगले वितीय वर्ष यानी 2020-21 में इससे दोगुना यानी 9142.26 करोड़ रुपए खर्च किए। चालू वितीय वर्ष में इस राशि में और इजाफा होने की संभावना है।

खनन माफिया पर कानूनी नकेल

मप्र में भू माफिया, ड्रग्स माफिया, अपराधियों, तस्करों पर नकेल कसने के बाद अब शिवराज सरकार ने खनन माफिया के साम्राज्य का खात्मा करने के लिए कठोर कानून का पहरा बैठा दिया है। सरकार ने मप्र खनिज अवैध परिवहन, भंडार नियम 2022 को हरी झंडी दी है। इससे सरकार सालाना हजारों करोड़ रुपए से अधिक की खनिज संपदा बचाएगी। साथ ही सरकार की खनिज संपदा से होने वाली आय में बढ़ोतरी भी होगी।

मप्र में खनिज संपदा के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने पूर्व में कई कदम उठाए हैं, लेकिन वे असरकारी साबित हुए हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा-निर्देश पर सरकार ने खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए कठोर कानून बनाया है। गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर 15 गुना रायल्टी वसूली जाएगी। साथ ही इतनी ही राशि पर्यावरण क्षति के रूप में ली जाएगी। यानी अवैध परिवहन, खनन और परिवहन करने वाले से 30 गुना दंड वसूला जाएगा। यही नहीं लगाया गया अर्थदंड जमा नहीं करने पर जप्त वाहन एवं मशीनरी आदि को राजसात किया जाएगा। जुर्माने की राशि जमा करने पर वाहन की सुपुर्दगी मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट ने मप्र खनिज अवैध परिवहन, भंडार नियम 2022 को हरी झंडी दी है।

अवैध खनन, परिवहन, भंडार के कारण अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा न होने पर मप्र भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के तहत राशि वसूली तथा कुर्की किए जाने का प्रावधान किया गया है। परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक परिवहन के मामलों में खनिज रायल्टी की 15 गुना वसूली होगी। नियमों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध संभागायुक्त को अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान पूर्व की तरह ही रहेगा। संभागायुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका राजस्व मंडल को प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया गया है। इन सुधारों से प्रदेश में अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा तथा उपरोक्त नियमों में एकजाई प्रावधान होने से प्रकरणों के निराकरण में पारदर्शिता एवं सुगमता हो सकेगी। नए कानून के तहत जब्त वाहन छुड़ाने के लिए संबंधित को 50 हजार से 4 लाख रुपए तक जुर्माना भरना होगा। यह राशि वाहन के हिसाब से निर्धारित की गई है। दो एक्सल वाहन पर 50 हजार रुपए, डंपर पर एक लाख रुपए, 10 पहिया वाहन पर 2 लाख रुपए, 10 पहिया से अधिक वाहन पर 4 लाख रुपए की पर्यावरण क्षति की राशि वसूली जाएगी।

गौरतलब है कि मप्र में खनिज संपदा के अवैध खनन पर अभी तक किसी का जोर नहीं चल रहा है। खनन माफिया मनी और मसल के जोर पर नर्मदा सहित प्रदेशभर की नदियों को खोखला कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार माफिया खनिज संपदा के अवैध खनन और नदियों से अवैध रेत निकालकर सरकार को सालाना 55 हजार करोड़ रुपए की चपत लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद प्रशासन ने जहां-जहां सख्ती की है माफिया ने पुलिस, वन और खनिज विभाग पर हमला बोला है। लेकिन सरकार के नए कानून से अब माफिया की मनी और मसल का जोर खत्म हो जाएगा। साथ ही सरकार की आय में इजाफा भी होगा।

एक अनुमान के अनुसार मप्र की नदियों के पेट से सालाना वैध तरीके से 2.25 लाख करोड़ रुपए की रेत निकाली जाती है। जबकि अवैध तरीके से 30 हजार करोड़ रुपए की। वहीं करीब 25 हजार करोड़ रुपए की अन्य खनिज संपदा का अवैध खनन होता है। हद तो यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नेताओं, अफसरों और माफिया की मिलीभगत से हो रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोनाकाल में जब पूरा देश घरों में कैद था, तब भी नर्मदा में रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से होता रहा। शासन और प्रशासन कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने में लगा रहा और माफिया नदियों को खोदने में जुटे रहे। अब एनजीटी ने अवैध खनन पर चिंता जाहिर की तो सरकार ने भी सख्त कदम उठाया है। नर्मदा सहित प्रदेश की नदियों में रेत का अवैध खनन किस कदर हुआ है, इसका अंदाजा इस साल की पहली कमिश्नर-कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर देखकर लगाया जा सकता है।

● राजेश बोरकर

नर्मदा की सहायक नदियों को मिलेगा नया जीवन

शिवराज सरकार द्वारा मप्र खनिज अवैध परिवहन, भंडार नियम 2022 कानून लागू होने के बाद नर्मदा सहित उसकी सहायक नदियों को जीवनदान मिलेगा। गौरतलब है कि मप्र की जीवनरेखा नर्मदा और उसकी लगभग एक दर्जन सहायक नदियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। नरसिंहपुर जिले की प्रमुख नदियों शक्कर, शेढ़, सीतारेवा, दूधी, ऊमर, बारूरेवा, पांडाझिर, माछा, हिरन आदि नदियों में से कई नदियों को रेत माफिया लगभग मौत के घाट उतार चुका है। बारूरेवा, माछा, पांडाझिर, सीतारेवा, ऊमर नदी तो ऐसी नदियां हैं कि जहां माफिया ने रेत का अंधाधुंध खनन नदी के अंदर से किया, जिससे नदी की सतह पर पानी थामने वाली कपायुक्त त्रि-स्तरीय तलहटी (लेयर) पूरी तरह उजड़ गई है। नर्मदा का हाल यह है कि उसका सीना लगातार छलनी किया जा रहा है। इससे नर्मदा के दोनों तटों पर रेत की बजाय अब कीचड़ है, नदी के अंदर से पोकलेंड मशीन के जरिए रेत निकालकर वही कार्य किया जा रहा है। शक्कर और शेढ़ नदी के हाल बुरे हैं। कभी इन नदियों के किनारे खरबूज-तरबूज की खेती लहलहाती थी, आज वहां उजड़ा चमन है। शक्कर अस्तित्व से जूझ रही है, वहीं शेढ़ को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। मप्र में खनन कारोबार का इस कदर विस्तार हुआ है कि राज्य के हर हिस्से में खदानों का खनन हो रहा था जिसके चलते अवैध उत्खनन का ग्राफ बढ़ गया है। प्रदेश में करीब 28 जिलों में तो खनन माफिया का एकछत्र राज है।

उद्योगों को सस्ती बिजली

महंगी बिजली की शिकायत कर रहे उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद जागी है। प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली की दरें घटाए बगैर मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीआईडीसी) के जरिए उद्योगों को सस्ती बिजली प्रदाय का रास्ता निकलता दिख रहा है। प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेज भी दिया गया है। सबकुछ ठीक रहा तो महंगी बिजली से उत्पादन लागत बढ़ने की उद्योगों की अरसे से चली आ रही शिकायत दूर हो जाएगी। प्रस्ताव का लाभ फिलहाल पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का नया हिस्सा यानी सेक्टर-7 और प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के उद्योगों को मिलेगा। इस प्रस्ताव को प्रदेश के औद्योगिक निवेश के लिए भी गेमचेंजर माना जा रहा है।

प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों को बिजली की आपूर्ति मप्र की विद्युत वितरण कंपनियां ही करती है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के स्पेशल इकोनामिक जोन (सेज) की व्यवस्था अलग है। सेज में बिजली आपूर्ति का जिम्मा एमपीआईडीसी संभाल रहा है। सेज में संचालित औद्यौगिक इकाइयों को एमपीआईडीसी 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति करता है। सेज के बाहर चल रहे उद्योगों को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली आपूर्ति करती है। इससे बिजली लेने वाले सभी उद्योगों को 7 रुपए यूनिट की दर से बिजली मिलती है। सेज के बाहर बसे उद्योग अरसे से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी एमपीआईडीसी बिजली वितरण करे ताकि सस्ती बिजली सुलभ हो सके।

उद्योगों की शिकायत है कि बिजली कंपनियों का क्षेत्र बढ़ा है। ऐसे में लाइन लास और बैलेंस शीट के घाटे से लेकर सब्सिडी के हिस्से सभी उपभोक्ताओं में बांट देती है। अन्य क्षेत्रों की आपूर्ति का घाटा भी उद्योगों के जिम्मे आ जाता है, इससे उद्योगों को महंगी बिजली मिल रही है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अनुसार सेज में संचालित बड़ी कंपनियां जो पूरी तरह निर्यातक इकाइयां हैं ऐसी करीब 48 इकाइयों को 50 मेगावाट बिजली आपूर्ति एमपीआईडीसी कर रहा है। सस्ती बिजली देकर भी एमपीआईडीसी सालाना करीब 10 करोड़ रुपए का लाभ भी कमा रहा है। यदि अन्य उद्योगों को भी एमपीआईडीसी बिजली दे तो उसका लाभ भी बढ़ेगा और उद्योगों को राहत भी मिल सकेगी।

एमपीआईडीसी ने बेटमा के पास पीथमपुर का नया सेक्टर 7 विकसित कर रहा है। दो हजार एकड़ के इस नए औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही सुपर कोरिडोर से राऊ बायपास तक विकसित होने वाले इकोनामिक कोरिडोर के उद्योगों को बिजली आपूर्ति के लिए एमपीआईडीसी ने प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सेज से बाहर होने पर भी इन क्षेत्रों के तमाम उद्योगों को पांच रुपए यूनिट तक की दर पर बिजली आपूर्ति करना संभव होगा। अब सचिव और सरकार स्तर से प्रस्ताव की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। तकनीकी बाधा इसलिए नहीं है क्योंकि एमपीआईडीसी के पास पहले से बिजली वितरण का लायसेंस है ही। दरअसल बिजली कंपनी की तरह एमपीआईडीसी सीधे पावर ट्रांसमिशन कंपनी से बिजली खरीदकर वितरण करता है। इसलिए सस्ती बिजली प्रदाय करना संभव है।

एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय निदेशक रोहन सक्सेना का कहना है कि सेक्टर-7 और इकोनामिक कोरिडोर के लिए हमने बिजली आपूर्ति का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उद्योगों की लंबे समय से मांग हमारे पास आ रही थी। सस्ती बिजली से औद्योगिक निवेश भी तेजी से आएगा क्योंकि उत्पादन लागत घटेगी। वहीं पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष डॉ. गौतम कोठारी का कहना है कि पीथमपुर के उद्योग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सेज के बाहर भी एमपीआईडीसी बिजली दे। उद्योगों को तो दो रुपए यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी ही एमपीआईडीसी का सालान मुनाफा भी 50 करोड़ तक पहुंचने का आंकलन है।

उधर बिजली की दरों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8.71 प्रतिशत बढ़ाने की नई याचिका पेश की गई है। मप्र नियामक आयोग द्वारा पुरानी याचिका लौटाने के बाद मप्र विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने पुरानी याचिका को नया बताकर पेश किया है। इस याचिका में भी 3915 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत की पूर्ति के लिए बिजली दरों में 8.71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पेश किया है। बिजली कंपिनयों की ओर से दिसंबर में 2022-23 के लिए याचिका लगाई गई थी। पर मप्र विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में त्रुटि का हवाला देते हुए याचिका वापस करते हुए नए सिरे से लगाने का निर्देश दिया था। दरअसल याचिका में विद्युत अधिनियम 2021 के ड्राफ्ट के अधीन तैयार किया गया था। जबकि याचिका दायर करने के बाद अधिनियम लागू हो चुका था। याचिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कुछ लोगों ने कर ली थी। इसे देखते हुए नियामक आयोग को कदम खींचने पड़े थे।

● सुनील सिंह

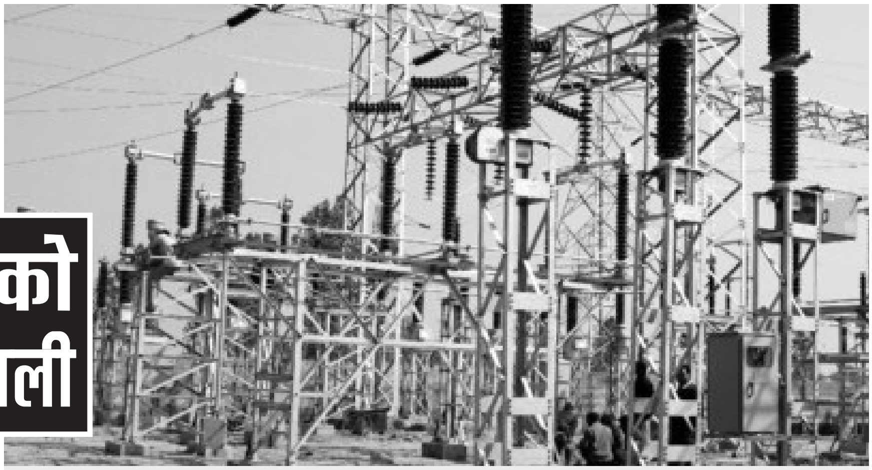

सारणी ताप गृह की चार इकाईयों को बंद करने की तैयारी

बैतूल के सारणी के ताप गृह की चार इकाईयों को बंद करने की तैयारी हो रही है। ये इकाईयां 40 साल या इसके आसपास पुरानी हो गई है। कुछ इससे भी ज्यादा वक्त की है। ऐसे में इन इकाईयों में बिजली पैदा करना महंगा पड़ रहा है। यही नहीं प्रदूषण और अन्य सुरक्षा मानकों में भी ये इकाईयां फिट नहीं बैठ रही हैं। ऐसे में मप्र पावर जनरेशन कंपनी के इस प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। सिर्फ शासन के पास से अनुमति मिलना बाकी है। यदि मंजूरी मिली तो करीब 830 मेगावाट की क्षमता कम हो जाएगी। सारणी ताप गृह की मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता 1330 मेगावाट है। मप्र पावर जनरेशन कंपनी ने सारणी की इकाई क्रमांक छह, सात, आठ और नौ नंबर की इकाई को बंद करने का प्रस्ताव दिया था। जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी प्रबंधन का तर्क है कि इसका रखरखाव महंगा पड़ रहा है। बिजली उत्पादन में कोयले की खपत के मुताबिक नहीं है। इसके अलावा प्रदूषण से जुड़े मानकों पर भी ये सभी इकाईयां खरी नहीं उतर रही हैं। ऐसे में इनसे बिजली का उत्पादन बंद किया जाए। बोर्ड से मंजूरी के बाद ऊर्जा विभाग के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव गया हुआ है जहां से इसे लंबित रखा गया है।

600 साल की गुलामी से मुक्ति

नर्मदापुरम करने की 30 साल पुरानी मांग हुई पूरी

होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की मांग 1991 में सबसे पहले अभाविप ने उठाई थी। 30 साल पहले अभाविप के तत्कालीन जिला संगठन मंत्री किशोर पोनीकर ने 'होशंगाबाद नहीं नर्मदापुरम कहो' अभियान चलाया था। 2006 में मुख्यमंत्री ने नर्मदापुर नाम करने की घोषणा की थी। प्रस्ताव भी भेजा गया लेकिन लेकिन राज्य व केंद्र में अलग-अलग पार्टी की सरकार होने के कारण इसे नामंजूर कर दिया गया था। प्रोटेम स्पीकर के मुद्दा उठाने के बाद लोग फिर नाम बदलने के लिए एकजुट हुए। 7 दिसंबर 2020 को होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने के लिए नर्मदापुरम युवा मंडल व लोगों ने अभियान भी चलाया था।

म प्र के इतिहास में 8 फरवरी का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है, क्योंकि इस दिन नर्मदापुरम को 600 साल की गुलामी से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने पर मुहर लगाई। गौरतलब है कि नर्मदापुरम का नाम मुगल लुटेरे अल्प खां होशंगशाह के नाम पर अभी तक था जो अब फिर से नर्मदापुरम हो गया है। नर्मदापुरम जिले के प्राचीन इतिहास का कोई उचित दस्तावेज प्राप्त नहीं है। 1405 ई. में होशंगशाह गौरी के शासनकाल के दौरान ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका नाम पहली बार सामने आया था। जिसने नर्मदापुरम में दो अन्य लोगों के साथ हंडिया और जोगा में एक छोटा किला बनाया था। बैतूल के पास खेरला के गोंड राजा पर भी होशंगशाह ने हमला किया एवं लूटपाट की। नर्मदा नदी के पार होशंगाबाद के उत्तर-पश्चिम में गिन्नूरगढ़ का किला गढ़ा-मंडला के गोंड साम्राज्य के अधीन रहा।

18वीं शताब्दी की शुरुआत में जिले को सात राजनीतिक प्रभागों में विभाजित किया गया था। यहां तक कि होशंगाबाद उस समय के गिन्नौर शासक के नियंत्रण में था। बाबई सहित बागरा हवेली सोहागपुर तहसील के बागरा किले के राजा से संबंधित थी और देवगढ़ (अब छिंदवाड़ा जिले) के राजा के अधीन था, जिसके अधीनस्थ अधिकारी तरन में तैनात थे। सओलीगढ़ (अब बैतूल जिले में) के राजा ने सिवनी और हरदा तहसील के कुछ हिस्से पर शासन किया। राजा के अधीनस्थ अधिकारी रहटगांव में तैनात थे। कालीभीत के राजा (जो पहले से ही मकरई में स्थानांतरित हो गए थे) ने पूर्वी निमाड़ की कालीभीत पहाड़ियों का आयोजन किया, जो हरदा तहसील के चारवा परगना का सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे पहले मकरई राज्य था।

पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1742 एडी में गंजल नदी के पश्चिम में हंडिया की राजधानी सिरकर पर कब्जा कर लिया और मोहम्मद गवर्नर को अपने हाथों से विस्थापित कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह मार्ग सिंधिया को सौंप दिया गया। गंजल के पूर्व में सिवनी मालवा, होशंगाबाद और सोहागपुर तहसील में पड़ने वाली शेष रियासतें, धीरे-धीरे 1740 ई. और 1775 के बीच नागपुर के भोंसला राजा के कब्जे में आ गईं। बेनीसिंह, भंवरगढ़ में उनके सूबेदार ने 1796 में होशंगाबाद किले पर कब्जा कर लिया। 1802 से 1808 होशंगाबाद और सिवनी भोपाल नवाब द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन अंततः 1808 में नागपुर के भोंसला राजा द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1817 के अंतिम एंग्लो-मराठा युद्ध में, होशंगाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा था और अप्पा साहिब भोंसला द्वारा किए गए अनंतिम समझौते के तहत आयोजित किया गया था। 1818 में इसके आधिपत्य के लिए। 1820 में भोंसला और पेशवा द्वारा उद्धृत जिलों को सौगोर और नेरबुड्डा क्षेत्र के शीर्षक के तहत समेकित किया गया और जबलपुर के रहने वाले 10 गवर्नर जनरल के एजेंट के तहत रखा गया। इस समय होशंगाबाद जिले में सोहागपुर से लेकर गंजल नदी तक का क्षेत्र शामिल था, जबकि हरदा और हंडिया सिंधिया के साथ बने हुए थे।

1835 से 1842 तक होशंगाबाद, बैतूल और नरसिंहपुर जिलों को होशंगाबाद में मुख्यालय के साथ में रखा गया था। 1842 में बुंदेला के परिणामस्वरूप, वे पहले की तरह फिर से तीन जिलों में अलग हो गए और सामान्य प्रभार रखने वाले अधिकारियों के पदनाम को उपायुक्त से सहायक के रूप में बदल दिया गया। 1844 में हरदा-हंडिया पथ भी सिंधिया द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, क्योंकि ग्वालियर की टुकड़ी के समर्थन के लिए सौंपा गया क्षेत्र और होशंगाबाद जिले से जुड़ा हुआ था, जिसे अंतिम रूप से 1860 में बनाया गया था। नर्मदा परगना, नर्मदा के उत्तर में 1844 में सिंधिया लौट आया। हरदा तहसील का कालीभीत मार्ग 1905 में पूर्वी निमाड़ के हरसूद तहसील में स्थानांतरित कर दिया गया। 1865 से पहले, जिले को प्रशासनिक उद्देश्य के लिए 42 तालुकों में विभाजित किया गया था। ऐसे मिनटों के अधीनस्थ उप-विभाजनों से बचने के लिए, तालुकों को छह परगना में वितरित किया गया था, जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तारित थे, उन्हें रजवाड़ा, सोहागपुर, होशंगाबाद, सिवनी, हरदा और चारवा नाम दिया गया था। यह, हालांकि, जल्द ही चार तहसीलों के वर्तमान विभाजन से अलग हो गया था। सोहागपुर, होशंगाबाद, सिवनी मालवा और हरदा। लगभग 1951 में, पचमढ़ी का गठन एक तहसील के रूप में किया गया था। लेकिन पहले की तरह एक अतिरिक्त तहसीलदार के साथ उप-तहसील में घटा दिया गया था। नरसिंहपुर जिले को वर्ष 1932 में होशंगाबाद में एक सब-डिवीजन के रूप में समाहित किया गया था। 1 अक्टूबर, 1956 को इसे फिर से अलग कर दिया गया। मकरानी राज्य को 1948 में हरसूद तहसील के एक हिस्से के रूप में होशंगाबाद में मिला दिया गया। इसके बाद 1948 में, भारतीय संघ में राज्यों का विलय हुआ और होशंगाबाद जिले को भी भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस प्रकार यह नर्मदापुरम से होशंगाबाद बना। इसकी भौगोलिक सीमा में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा हैं।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

मप्र में सरकार ने अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसने के लिए नया कानून तो ला दिया है, लेकिन लकड़ी माफिया अभी भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। माफिया के आगे वन विभाग पस्त नजर आ रहा है।

लकड़ी माफिया के आगे वन विभाग पस्त

नियमों में बंधे होने के कारण कार्रवाई नहीं

वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि नियमों में बंधे होने के कारण अमला माफिया के खिलाफ हथियारों का उपयोग नहीं कर पाता है। यदि बीट गार्ड अपनी बीट में घूम रहा है और उसके पास हथियार भी हैं तो उसे चलाने उसे अपने एसडीओ से परमिशन लेना होता है। जिन कर्मचारियों ने सर्चिंग के समय हथियार का इस्तेमाल बिना परमिशन किया, उन पर कार्रवाई हुई। प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसे हटाने में प्रतिवर्ष करीब 50 वन सुरक्षाकर्मी घायल होते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं जिनमें सुरक्षाकर्मियों को अतिक्रमण मुहिम में जान से हाथ धोना पड़ा है।

वन विभाग की सतर्कता और सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद मप्र के जंगलों में लकड़ी माफिया का आतंक मचा हुआ है। आलम यह है कि माफिया के डर से वन विभाग के अधिकारी संवेदनशील क्षेत्र में गश्त नहीं करते और इसका फायदा उठाकर माफिया सागौन के पेड़ों को कटवाकर उसकी पड़ोसी राज्यों तक तस्करी करा रहे हैं। ऐसे ही तस्करों की चपेट में आष्टा और इछावर की सीमा से लगे खिवनी अभयारण्य भी है। खिवनी अभयारण्य से छापर, अरनिया जोहरी से आष्टा कन्नौद हाईवे से आष्टा शहर में आ जाते हैं। यहां से शुजालपुर, खुजनेर होते हुए राजस्थान पहुंचते हैं।

खिवनी अभयारण्य में लगातार सागौन की कटाई जारी है। यह काम रात के समय किया जाता है। 500 से 2100 हेक्टेयर रकबे की एक बीट की सुरक्षा के लिए केवल एक गार्ड ही रहता है। उसे अपनी बीट में घूमना हो तो उसे 3 किमी से 21 किमी तक का सफर करना पड़ता है। कोई वनकर्मी लकड़ी कटाई को रोकने की हिम्मत दिखाता भी है तो मारपीट की जाती है।

खिवनी अभयारण्य में वन माफिया की पैठ का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि गत दिनों लाड़कुई वन परिक्षेत्र की महिला वन रक्षक जब लकड़ी कटाई रोकने पहुंची तो आरोपियों ने मारपीट की। पिछले 6 माह में कार्रवाई की बात करें तो आष्टा और इछावर ब्लॉक में 165 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 45.70 लाख की **सागौन जब्त** की गई। हालांकि 35 आरोपी ही पकड़े जा सके हैं। वन परिक्षेत्र में कटाई के बाद तस्करी का खेल शुरू होता है। तस्करी के लिए कंडम और चोरी के वाहनों का उपयोग किया जाता है। रात के अंधेरे में गांवों के रास्ते, शहर और फिर फोरलेन से होते हुए यह लकड़ी बड़े शहरों में पहुंचती है। लकड़ी चोर सागौन की एक सिल्ली 600 से 800 रुपए में बेचते हैं, इसके बाद यह 2000 या 2200 रुपए में बिकती है। फर्नीचर की दुकान पर इसकी कीमत तीन गुना हो जाती है। जिले से सागौन की तस्करी, भोपाल, होशंगाबाद और राजस्थान तक होती है।

देश में वन भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण मप्र में हो रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार अब तक मप्र में करीब 5,347 वर्ग किमी से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। जबकि दूसरे नंबर पर असम और तीसरे नंबर पर उड़ीसा का नाम है। मप्र में वन विभाग के संरक्षण शाखा की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्रति वर्ष 750 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर खेती और आवास बनाने के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है। रिपोर्ट में ये बात भी स्वीकार की गई है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने में मात्र 20 फीसदी ही सफलता मिल पाती है। इसकी मुख्य वजह वोट बैंक की राजनीति मानी जा रही है। रिपोर्ट में पिछले तीन साल के अतिक्रमण आंकड़ों का हवाला देकर कहा गया है कि 13209 हेक्टेयर में अतिक्रमण हुआ। जबकि मात्र 1039 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने में वन महकमा सफल हो पाया।

दमोह जिले के तारादेही वन परिक्षेत्र में वनों की कटाई थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां सबसे ज्यादा सागौन की तस्करी हो रही है। लगातार वनों से सागौन के काटे जाने वाले ठूंठ की ग्रामीणों द्वारा फोटो खींची जा रही है, लेकिन वन अमला अब तक नुकसानी का आंकलन भी नहीं कर पा रहा है। तारादेही वन परिक्षेत्र की बरटा बीट और आमाखोई बीट व हाथीडोल बीटों में लगातार बड़े-बड़े पेड़ों की रात दिन अवैध रूप से कटाई की जा रही है। लकड़ी काटने वाले लोग जंगल का सफाया करने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कागजों में केवल अपनी गश्त व उपस्थिति दर्शाई जा रही है। अधिकारी जानकर भी अनजान बने बैठ जाते हैं। तारादेही वन परिक्षेत्र में चारों तरफ घना जंगल होने के कारण माफियाओं द्वारा लकड़ी काटकर आसानी से उपयोग कर ली जाती है। जबकि तारादेही वन परिक्षेत्र ही हर बीटों में वन चौकी बनी हुई है। लेकिन उनमें कोई भी वनकर्मी वहां मौजूद नहीं रहता है। जिसके कारण यह कटाई होना सामने आ रहा है। वन चौकी में रहने वाले परिक्षेत्र अधिकारी बीटगार्ड को इन लकड़ियों के ठूंठ की भनक भी नहीं लगती है। जंगल साफ होता जा रहा है। जिसका परिणाम साफ नजर आता है कि वन अधिकारी रात्रि गश्त का दावा तो करते हैं, तो फिर पेड़ों को काटने वाले क्यों इनकी पकड़ से दूर रह जाते हैं। क्योंकि पूरा वन विभाग अंजान बनकर अपने दफ्तर में बैठा आराम फरमा रहा है। वनकर्मी अपनी सुरक्षा की खैर मनाते हुए शहरों में ही रात बिताते हैं और अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं।

● **बृजेश साहू**

वादों के भरोसे बुंदेलखंड

उप्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है और प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड में इस बार भी चुनावी मुद्दे वही हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। लेकिन मुद्दों के समाधान को लेकर लोगों की मांगों ने जोर पकड़ा है। इनमें बुंदेलखंड राज्य की मांग तो है ही, मगर दूसरी ओर रोजगार के न होने से पलायन जैसे मुद्दे भी इस बार हावी हैं। बताते चलें कि बुंदेलखंड के हिस्से में कुल सात जिले आते हैं, जिनमें 4 लोकसभा सीटें और 19 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड निवासियों का कहना है कि चुनाव तो आते-जाते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान सियासी दलों द्वारा किए वादे पूरे न होने से वे खुद को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं।

दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र की पूरी-की-पूरी 19 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। तब लोगों ने उम्मीद की थी कि भाजपा को सभी 19 सीटों पर जीत दिलाई है और केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का विकास होगा और साथ ही अलग से राज्य भी बनेगा। लेकिन सारी-की-सारी उम्मीदें धरी-की-धरी रह गईं। अब इस बार के विधानसभा चुनाव आते ही लोग नेताओं को पुराने वादे याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि चुनावी वादे को सिर्फ वादा समझने वालों को जनता इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। समाजवादी नेता पूरन सिंह ने बताया कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था। तब झांसी, ललितपुर लोकसभा सीट से भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बुंदेलखंड के विकास को लेकर तमाम वादे किए थे। साथ ही बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा किया था। लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि इतना जरूर हुआ है कि 28 फरवरी, 2019 को सियासत दबाव और लोगों को दिखाने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन हुआ है। बोर्ड में बैठे पदाधिकारी भी अपनी सियासी पकड़ के चलते बुंदेलखंड के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

जहां तक 2022 के विधानसभा चुनाव की बात है, तो बुंदेलखंड में तीसरे चरण में 19 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। इस बार भाजपा और सपा के बीच चुनावी जंग आर-पार की है। बसपा और कांग्रेस चुनावी माहौल बनाने में लगे हैं। लोगों का कहना है कि यह तो बात पक्की है कि सियासत में जुमलों और वादों का दौर चलता है, लेकिन इतना भी नहीं चलता है कि चुनाव जीतने के बाद भुला दिया जाए और जनता फिर भी खामोश बैठी रहे।

बुंदेलखंड के विकास और यहां सूखा पड़ने से बेहाल किसानों की सहायता के लिए काम करने वाले विनीत कुमार ने बताया कि 2007 से पहले लोगों ने यह सोचा था कि मायावती सदैव दलितों के हित की बात करती हैं। लेकिन जब 2007 में बसपा ने जो दलित-ब्राह्मण कार्ड खेला था, जिसमें वे सफल भी हुईं; तब लोगों को लगा था कि दलितों के साथ सामान्य वर्ग का भी विकास होगा। उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस एक सामान्य सरकार की तरह बसपा सरकार भी आरोपों-प्रत्योरोपों से घिरी रहने वाली साबित हुई। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, तो लोगों ने यह आशा की थी कि अखिलेश यादव एक युवा नेता हैं और विदेश से पढ़कर आए हैं। अखिलेश जरूर प्रदेश के विकास के साथ बुंदेलखंड का विकास करेंगे, जिससे इस छिटके क्षेत्र में पानी की किल्लत दूर होगी। किसानों को राहत मिलेगी और गरीबों व बेरोजगारों का पलायन रुकेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में तालाबों के जीर्णोद्धार करने के साथ नए तालाब भी बनवाए हैं। लेकिन तालाबों की खुदाई से लेकर और उसकी मिट्टी का ठेका खासकर एक-दो विशेष जाति के लोगों को दिए जाने से बाकी लोगों में नाराजगी देखी गई। साथ ही लोगों को एम-वाई फैक्टर (मुस्लिम-यादव) के बढ़ते दबदबे से लोगों के साथ खासकर महिलाओं और स्कूलों में नाराजगी बढ़ी थी। क्योंकि थानों में और सरकारी दफ्तरों में एम-वाई फैक्टर की ही सुनी जा रही थी। इन्हीं सब घटनाओं से क्षुब्ध होकर लोगों ने 2017 के विधानसभा के चुनाव में एक तरफा सभी 19 विधानसभा सीटों पर भाजपा को ऐसिहासिक जीत दिलाई। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो फिर लोगों ने यह उम्मीद की थी कि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के लोगों की परेशानियों से वाकिफ हैं और प्रदेश के विकास के साथ-साथ बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहाएंगे और पलायन को रोकेंगे। लेकिन उन्होंने भी इस महती क्षेत्र के साथ वही सब किया, जो दूसरे सियासतदान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वादे, और कुछ नहीं।

● सिद्धार्थ पांडे

समस्याओं की भरमार

बुंदेलखंड निवासी राजेश शुक्ला ने बताया कि बुंदेलखंड की कई बुनियादी समस्याओं के अलावा इसके हिस्से वाले सातों जिलों- बांदा, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा और चित्रकूट की अपनी-अपनी बुनियादी समस्याएं हैं। किसी जिले में कुछ विकास हुआ है, तो किसी जिले में विकास न के बराबर ही हुआ है। ऐसे में सरकार का दायित्व तो यह बनता था कि प्रत्येक जिले की समस्याओं और पूरे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विधिवत योजनाओं को साकार करना किया जाए। लेकिन किसी भी सियासी दल ने यह कभी सोचा तक नहीं है। राजेश शुक्ला का मानना है कि बुंदेलखंड में झांसी जिले का विकास जिस तरह हुआ है, उस तरह अन्य 6 जिलों में नहीं हैं। ऐसे में बाकी 6 जिले काफी पिछड़े हुए हैं। 2020 में कोरोना महामारी ने तो बुंदेलखंड को और भी पिछड़ा कर दिया है। किसानों की हालत खराब है। पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब फिर से बुंदेलखंड में अपराध बढ़ने लगा है। उनका कहना है कि बुंदेलखंड की जनता चाहती है कि सरकार किसी भी पार्टी की बने, पर युवाओं को रोजगार मिले और किसानों को दिए जाने वाले बजट को और बढ़ाया जाए, तब जाकर कुछ होगा, अन्यथा बुंदेलखंड पिछड़ता ही जाएगा।

किस ओर जा रहा देश...?

हिजाब हो या न हो... शिक्षा हमारा अधिकार है!

7 साल की शांति में... अशांति का किसका प्रयास?

कोई क्या पहनता है? क्या खाता है? इस पर फैसला करने का अधिकार ना समाज को मिला है, ना धर्म को मिला है, ना जाति को मिला है, ना किसी संस्था को मिला है। भारत का संविधान कहता है कि कोई क्या पहनता है और क्या खाता है... जैसे सवालों का जवाब व्यक्ति का निजी अधिकार है। निजता के अधिकार के तहत संविधान के अनुच्छेद-21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के तौर पर शामिल है। फिर हिजाब को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है।

● राजेंद्र आगाल

देश में कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को दरकिनार कर देश में इन दिनों हिजाब का विवाद गर्माया हुआ है। आखिर इस विवाद की जड़ में कौन है? देश में 7 साल की शांति को अशांत करने का कौन प्रयास कर रहा है? कर्नाटक सहित पूरे देश में हिजाब को लेकर जो बहस छिड़ी है, उस बहस में हिजाब पहनने और ना पहनने का फैसला करने का अधिकार ना हमें मिला है, ना आपको मिला है, ना ही हिंदू धर्म को मिला है और ना ही मुस्लिम धर्म को मिला है। यह अधिकार लड़की और औरत का है कि वे अपने पहनावे को लेकर क्या फैसला करती हैं? फिर हिजाब को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? कैंपस में हिजाब हो या न हो, शिक्षा हमारा अधिकार है। युवाओं को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि देश का माहौल बिगड़े।

हिजाब हो या न हो, शिक्षा हमारा अधिकार है!

हिजाब विवाद की गूंज अब कर्नाटक के साथ उप्र और राजस्थान में भी सुनाई देने लगी है। दिल्ली में भी इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उचित समय पर विचार करेगा, जिसमें विद्यार्थियों से शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार के धार्मिक कपड़े नहीं पहनने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं फैलने पर भी जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ को छात्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश ने संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया है। उन्होंने याचिका की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध भी किया। कामत ने इसके बाद कहा, मैं उच्च न्यायालय द्वारा हिजाब के मुद्दे पर दिए अंतरिम आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि उच्च न्यायालय का यह कहना अजीब है कि किसी भी छात्र को स्कूल और कॉलेज जाने पर अपनी धार्मिक पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए। न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। उन्होंने सिखों के पगड़ी पहनने का जिक्र किया और कहा कि उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में सभी छात्रों को निर्देश दिया है कि वे अपनी धार्मिक पहचान बताए बिना शिक्षण संस्थानों में जाएं। कामत ने कहा, हमारा सम्मानजनक निवेदन यह है कि जहां तक हमारे मुवक्किल की बात है, यह अनुच्छेद-25 (धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता) के पूर्ण निलंबन के बराबर है। इसलिए कृपया अंतरिम व्यवस्था के तौर पर इस पर सुनवाई करें।

यह देखना दयनीय है कि जब ईरान में महिलाएं बुर्के के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं और अफगानिस्तान में तालिबान बुर्का न पहनने वाली स्त्रियों पर कोड़े बरसा रहे हैं, तब कर्नाटक में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पढ़ाई करने पर आमादा हैं। राज्य के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में इस विवाद ने तब तूल पकड़ा, जब इसी माह की शुरुआत में छह छात्राएं हिजाब पहनकर कक्षा में पहुंच गईं। इसके पहले वे कॉलेज परिसर में तो हिजाब पहनती थीं, लेकिन कक्षाओं में नहीं। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वे अध्ययन कक्ष में हिजाब पहनकर जाने लगीं? इस सवाल की तह तक जाने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि एक तो यह विवाद देश के दूसरे हिस्सों को भी अपनी चपेट में लेता दिख रहा और दूसरे, इसके पीछे संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ दिख रहा है। यह पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र शाखा है। माना जाता है कि यह प्रतिबंधित किए जा चुके कुख्यात संगठन सिमी का नया अवतार है। निसंदेह हर किसी को अपनी पसंद के परिधान पहनने की आजादी है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। स्कूल-कॉलेज में विद्यार्थी मनचाहे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। इसी मनमानी को रोकने के लिए शिक्षा संस्थान ड्रेस कोड लागू करते हैं। इसका एक बड़ा कारण छात्र-छात्राओं में समानता का बोध कराना होता है। दुर्भाग्यपूर्ण केवल यह नहीं कि जब दुनियाभर में लड़कियों-महिलाओं को पर्दे में रखने वाले परिधानों का करीब-करीब परित्याग किया जा चुका है और इसी क्रम में अपने देश में घूंघट का चलन खत्म होने को है, तब कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद कर रही हैं। यह न केवल कूप-मंडूकता और एक किस्म की धर्मांधता है, बल्कि स्त्री स्वतंत्रता में बाधक उन कुरीतियों से खुद को जकड़े रखने की सनक भी, जिनका मकसद ही महिलाओं को दोयम दर्जे का साबित करना है। यह हैरानी की बात है कि कांग्रेस समेत कई दल स्कूलों में छात्राओं के हिजाब पहनने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। इस क्रम में प्रियंका गांधी यहां तक कह गईं कि यह महिला का अधिकार है कि वह चाहे हिजाब पहने, चाहे बिकिनी, चाहे घूंघट...। क्या वह स्कूलों में भी बिकिनी, घूंघट की वकालत कर रही हैं? इस पाखंड और शरारत पर भी गौर करें कि कई कथित प्रगतिशील मुस्लिम महिलाएं, जो खुद हिजाब नहीं पहनतीं, वे उसके पक्ष में अभियान छेड़े हुए हैं।

कॉमन सिविल कोड के लिए माहौल

कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने हिजाब विवाद पर कहा है कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। इन सबके बीच कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब दिल्ली, महाराष्ट्र, उप्र तक फैलता जा रहा है। सीएए विरोधी प्रदर्शन के लिए चर्चा के केंद्र में रहे शाहीन बाग में भी हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं, इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक ट्वीट ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये बहस छेड़ दी है कि देश संविधान से चलेगा या धर्म से? वैसे, चर्चा छिड़ना लाजिमी भी है। क्योंकि, हम भारत के लोग संविधान के खिलाफ नहीं हैं। और, संविधान के ही अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो ताजा हिजाब विवाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू करने का माहौल बना रहा है। क्योंकि, भारत में **मजहब या धर्म के आधार पर** अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्रता का पैमाना तय नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, अगर ऐसा होता है, तो यह सीधे तौर पर भारत के संविधान पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है।

भविष्य में भयावह नजर आते हैं हालात

आज स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने को संवैधानिक अधिकार बताया जा रहा है। इसे देखकर निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि भविष्य में इस्लाम और शरीयत के हिसाब से अन्य चीजों की भी मांग उठेगी ही। क्योंकि, बीते साल ही तमिलनाडु के पेरंबलूर जिले के कड़तूर गांव में निकलने वाली रथयात्रा को मुस्लिम जमात ने अपनी आबादी के लिहाज से शिर्क यानी पाप बताया था। और, इस मामले सत्र न्यायालय द्वारा रथयात्रा पर रोक लगाने के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर जमात का यह तर्क मान लिया गया, तो हिंदू बहुल भारत में कोई मुस्लिम आयोजन नहीं हो सकेगा। वैसे,

शिक्षण संस्थानों के लिए सवैधानिक प्रविधान

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133 (2) को लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को कॉलेज कमेटी या विश्वविद्यालय प्रशासनिक बोर्ड के द्वारा चुनी गई ड्रेस पहननी होगी। सरकार का मत है कि ऐसी ड्रेस को वर्जित किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था भंग होती हो और समानता और सत्यनिष्ठा को भी चोट पहुंचती हो। वैसे अब यह मसला कोर्ट के विचाराधीन है। रेशम और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2022) के नाम पर यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है। दोनों पक्ष अपनी दलील दे रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि हिजाब पहनने का अधिकार इस्लाम में एक धार्मिक प्रथा है, और राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जबकि राज्य के महाधिवक्ता सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए संविधान के अनुच्छेद-19 (2) के तहत राज्यों को उचित प्रतिबंध लगाने के अधिकार का हवाला देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-25 में धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसके आरंभ में ही लिखा हुआ है कि लोक-व्यवस्था तथा संविधान के भाग तीन के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए ही आपको ये अधिकार मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह विवादित आदेश अनुच्छेद-25 के अंतर्गत माना जाएगा? क्या यह सरकारी आदेश लोक व्यवस्था के अंतर्गत भी माना जाएगा? अगर हां, तो संविधान के अनुच्छेद-19 (2) के तहत किस हद तक औचित्यपूर्ण माना जाएगा और सरकार के लोक व्यवस्था कायम रखने के अधिकार को न्याय संगत बनाएगा। इस बारे में फातिमा तसनीम बनाम केरल राज्य (2018) केस महत्वपूर्ण है। दरअसल जस्टिस मुश्ताक ने एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता संस्था के व्यापक अधिकार के खिलाफ अपने व्यक्तिगत अधिकारों को लागू करने की मांग नहीं कर सकते, जिसमें हेडस्कार्फ और साथ ही पूरी बाजू की शर्ट पहनने की इजाजत मांगी गई थी जो स्कूल के ड्रेस कोड के विरुद्ध था। कोर्ट ने सामूहिक हित को प्राथमिकता दी, न कि व्यक्तिगत हित को। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आशा रंजन और अन्य बनाम बिहार सरकार (2017) के फैसले में संतुलन की बात को स्वीकार किया और कहा कि प्रतिस्पर्धी अधिकार की बात जब आती है तो सदैव व्यक्तिगत हित व्यापक जनहित के अनुरूप होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है या नहीं?

हिजाब विवाद को सियासत का औजार न बनाएं

माई चॉइस का मसला एक आधुनिक स्त्री का मसला है, जहां वह अपने निर्णय खुद ले सकती है। लेकिन आज भी हमारे देश में किसी भी जाति-धर्म की लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, जो अपने निर्णय खुद ले पाती हैं। अक्सर वे अपने परिवार और समाज की सत्ता के बनाए कानूनों का ही पालन करती नजर आती हैं। कर्नाटक में जबसे बुर्का और हिजाब की बहस चली है, समाज में विभाजन दिख रहा है। हिजाब को औरतों की आजादी से जोड़ा जा रहा है। लोकतंत्र में अपने-अपने धार्मिक अधिकारों की बात की जा रही है। बहुत से स्त्री-पुरुष, बुद्धिजीवी, हिजाब की वकालत कर रहे हैं। दुनियाभर में बहुत-सी मुसलमान औरतें हिजाब और बुर्कों से मुक्ति के रास्ते तलाश रही हैं। मगर अपने यहां अनेक वे औरतें, जिन्होंने हर तरह की स्वतंत्रता को खूब भोगा है, वे इसके पक्ष में लट्ठ लेकर खड़ी हैं। अरसे से तो बताया गया कि हिजाब, बुर्का, घूंघट, चादर आदि स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले दोयम दर्जे की नागरिकता देते हैं। पुरुषों के बनाए ये नियम औरतों को अपने से नीचे मानने के कारण ही उसे तरह-तरह के बंधनों में कैद करते हैं। मगर अब जैसे इन विचारों को सिर के बल खड़ा कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह उस स्त्री का अपना मामला है कि वह हिजाब, बुर्का पहनती है या नहीं। उस पर अपना विचार दूसरे कैसे लाद सकते हैं। इसी के जवाब में दूसरे कह रहे हैं कि इस तरह तो घूंघट भी औरत की अपनी चॉइस का मामला ही हुआ।

हिजाब विवाद के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन, मुस्लिम समाज में बढ़ रही कट्टरता पर शायद ही किसी के विचार सामने आते होंगे। यहां ये भी बताना जरूरी है कि कड़तूर जिले में जमात का विरोध 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ था। बल्कि, यह वैमनस्य 2011 से ही जारी था। आसान शब्दों में कहा जाए, तो अगर इस तरह के विवादों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके खत्म नहीं किया गया, तो भविष्य में यह एक भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि, भारत कई धर्मों और संप्रदायों का देश हैं, तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं, जिसमें हर समुदाय अपने धर्म और संप्रदाय के हिसाब से कई चीजों को अपना संवैधानिक अधिकार बता सकते हैं।

संविधान में ही हैं कई विरोधाभास

वैसे, भारत में पर्सनल लॉ बनने के साथ ही इस विघटनकारी सोच की नींव रख दी गई थी। क्योंकि, भारत के संविधान में भी कई विरोधाभास हैं। संविधान के अनुच्छेद-15 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य-संप्रदाय, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा। लोगों के पास इन मामलों पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। ठीक वैसे ही जैसे सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल के उम्र की महिलाओं को प्रवेश का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और, मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक की परंपरा को असंवैधानिक बताया था। लेकिन, संविधान के ही अनुच्छेद-37 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जैसे अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं हैं। इतना ही नहीं, संविधान के तहत बनाए गए पर्सनल लॉ को संघ सूची के बजाय समवर्ती सूची में रखना भी एक बड़ा सवाल है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो अगर सरकार **यूनिफॉर्म सिविल कोड** लागू करने का मन नहीं बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास केवल इसके बारे में अपनी राय रखने का ही अधिकार है। इस कारण समय-समय पर यूनिफार्म सिविल कोड का मुद्दा गर्माता रहता है और राजनीतिक रोटी सेंकी जाती है।

लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में

1985 का शाह बानो मामला इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लेकर संसद को निर्देशित किया था। लेकिन, संसद में अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया था। उसके बाद से देश में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का जो उदय हुआ है, आज का हिजाब विवाद उसी का नतीजा कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद तीन दशक से ज्यादा समय गुजर चुका है। अब तक कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकारों को दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं। लेकिन, कोई भी सरकार इस पर कदम बढ़ाने का विचार नहीं बना सकी है। हालांकि, भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का भी वादा किया गया है। लेकिन, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र सरकार की ओर से इस पर अभी तक उदासीनता ही नजर आती है। जबकि, जनवरी 2022 के सर्वे में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के पक्ष में 72.7 फीसदी लोगों ने अपनी राय जाहिर की थी।

मुस्लिम तुष्टिकरण को तिलांजलि

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि धारा-370 जैसे कानून की वजह से ही लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में रिफ्यूजी बनने पर मजबूर होना पड़ा था। और, इसी आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले अधिकांश राजनीतिक दल इसका विरोध करेंगे। क्योंकि, वोट बैंक की राजनीति करने वाली ये सियासी पार्टियां देश को ऐसे ही मामलों में उलझाए रखकर अपना हित साधने में लगी रहती हैं। क्योंकि, जैसे ही केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से इसे लेकर कदम उठाए जाएंगे। ये सभी राजनीतिक दल एक सुर में इसे मुस्लिम विरोधी साबित करने में जुट जाएंगे। जबकि, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सभी समुदाय आएंगे। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड न होने का खामियाजा अब तक कई लोग भुगत चुके हैं। लेकिन, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भारत में राजनीतिक हितों को साधने का एक हथियार बन चुका है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो हालिया हिजाब विवाद केंद्र की भाजपा सरकार के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का माहौल तैयार कर रहा है। लेकिन, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन, देश की एकता और अखंडता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अब कहीं ज्यादा जरूरी नजर आता है।

इस्लामिक संस्थाएं करवा रहीं प्रदर्शन

हैरानी की बात ये है कि इन विरोध प्रदर्शनों का स्कूल में पढ़ने वाले **छात्रों से कोई लेना-देना** नहीं है। बल्कि इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम नेताओं की ओर से अलग-अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर बड़े प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रदर्शन महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ, जिसमें पुलिस की अनुमति के बिना हजारों की संख्या में बुर्का पहनी महिलाएं शामिल हुईं। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लेकिन हमारा सवाल यहां विरोध प्रदर्शनों को लेकर नहीं है। हमारा सवाल उन 15 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 25 करोड़ बच्चों के भविष्य को लेकर है, जिन्हें धर्म की आग में धकेला जा रहा है।

धर्म की असली शिक्षा वो नहीं है, जो आपकी सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति को समाप्त कर दे, बल्कि धर्म की असली शिक्षा वो है जो आपको सवाल उठाने का सामर्थ्य दे ताकि आप गलत को गलत कह सकें और अपना मार्ग खुद चुन सकें। धर्म का बचपन पर क्या प्रभाव पढ़ता है, इसे समझने के लिए वर्ष 2015 में एक रिसर्च की गई थी। ये शोध 1200 बच्चों पर किया गया था, जिनमें से 24 प्रतिशत ईसाई, 43 प्रतिशत मुस्लिम और 27 प्रतिशत धर्म को ना मानने वाले थे। इस शोध में पाया गया कि जिन बच्चों के परिवार वाले बहुत धार्मिक थे, वो बच्चे अपनी चीजों को दूसरों के साथ आसानी से बांटने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों का आंकलन उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कर रहे थे। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था। जिसमें ये बताया गया था कि जब तक अदालत हिजाब मामले में अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती, तब तक राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छात्र और छात्राएं

भारत को बदनाम करने की साजिश

हिजाब विवाद के लिए विधायक और भाजपा नेताओं को दोषी ठहराते हुए पुंजालकट्टे ने कहा, यह रघुपति भट की राजनीति है। भाजपा नेता यशपाल सुवर्णा राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। भाजपा और संघ परिवार विभाजनकारी राजनीति कर रहा है। भगवा शॉल पहनना, भगवा झंडा फहराना, मुस्लिम लड़कियों पर हमले करना, ये सब हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए भाजपा का एजेंडा है। भाजपा के पास दिखाने के लिए कोई विकास का काम नहीं है इसलिए वे समाज का ध्रुवीकरण कर रहे हैं जिससे उन्हें चुनाव में मदद मिले। वहीं भट ने सीएफआई के आरोपों को हंसते हुए खारिज कर दिया और बताया कि उन्होंने मामले को चुपचाप सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया में लीक कर दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि इस खबर को हमारे कॉलेज से बाहर न जाने दिया जाए। मैंने छात्रों और उनके माता-पिता के साथ दो दौर की बैठकें कीं। इस विवाद के अचानक गहराने के कारण के बारे में पूछे जाने पर भट ने आरोप लगाया कि यह भारत को बदनाम करने की अंतरराष्ट्रीय समूहों की साजिश है। इस मुद्दे पर शुरू में खामोश रहने वाले कांग्रेसी नेताओं ने तभी चुप्पी तोड़ी जब यह मामला और कॉलेजों में फैल गया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हिजाब एक मौलिक अधिकार है। वहीं दक्षिण कन्नड़ के विशेषज्ञ ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अगले साल विधानसभा चुनाव तक इसी तरह चलता रहेगा। पिछले चुनाव में भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया था। उडुपी के कार्यकर्ता नागेश कुमार ने इस विवाद के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पूरा मामला एक राजनीतिक नौटंकी के सिवा और कुछ नहीं है।

हिजाब और भगवा गमछा नहीं पहन सकते। हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश के आठवें और नौवें पाइंट में लिखा कि उसे इस बात का बेहद दुख है कि जब इस मामले की सुनवाई लंबित है, उसके बाद भी कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्राएं अपने धार्मिक परिधान में क्लास अटेंड करने की जिद पर अड़ी हुई हैं।

मजहबी शिक्षा लेने वाले ज्यादा कट्टरपंथी

धार्मिक परिवारों से आने वाले बच्चे शरारत करने वाले दूसरे बच्चों को सख्त सजा देने के पक्ष में थे। जबकि जिन बच्चों के परिवार वाले किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो ज्यादा मिलनसार, अपनी चीजों को बांटने वाले और दूसरे छात्रों को सजा ना देने के पक्ष में थे। ये सर्वे सिर्फ 1200 बच्चों पर किया गया था इसलिए कोई चाहे तो इसे आसानी से खारिज भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें किए गए सारे दावे वाकई सच हों। इस समय दुनिया की आबादी करीब 750 करोड़ है। इनमें से 84 प्रतिशत यानी 630 करोड़ लोग खुद को धार्मिक कहते हैं। फिर भी दुनिया के लगभग हर कोने में इस समय कोई ना कोई हिंसा, कोई ना कोई युद्ध और कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ज्यादातर जगहों पर ये सब धर्म के नाम पर ही हो रहा है। इसलिए ये फैसला आपको करना है कि आपको अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के नाम पर उन्हें कट्टर बनाना है या फिर उन्हें धर्म के असली मायने समझाते हुए एक बेहतर इंसान बनाना है।

हिजाब विवाद कई देशों में

कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमा नहीं है। मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक धार्मिक पोशाकों पर रोक रहेगी, फिर वह हिजाब हो या भगवा कपड़ा। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिसे तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। किसी की नजर में ये संवैधानिक अधिकार है तो किसी का मानना है कि शिक्षण संस्थानों में **धार्मिक प्रतीकों** को पहनना सही नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां बरसों पहले ही सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने या इस्लामिक नकाबों पर रोक लगा दी गई। कुछ देशों में तो नियमों के उल्लंघन पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान है। 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नकाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। फ्रांस में करीब 50 लाख मुस्लिम महिलाएं रहती हैं। पश्चिमी यूरोप में ये संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन महज 2 हजार महिलाएं ही बुर्का पहनती हैं। वहीं बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। नवंबर 2016 में नीदरलैंड्स के सांसदों ने स्कूल-अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में सफर के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर रोक का समर्थन किया। इटली के कुछ शहरों में चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध है। इसमें नोवारा शहर भी शामिल है। अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नॉर्वे में जून 2018 में पारित एक कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक है। डेनमार्क की संसद ने 2018 में पूरा चेहरा ढकने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान करने के बिल को मंजूरी दी थी। रूस के स्वातरोपोल क्षेत्र में हिजाब पहनने पर रोक है।

पहले भी उठा है हिजाब पहनने का मुद्दा

यह मुद्दा पहले भी उठ चुका है। मुस्लिमों में ही महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जो हिजाब और बुर्का नहीं पहनता है। सामाजिक कार्यकर्ता फराह फैज ने बताया कि केरल हाईकोर्ट में 2018 में इस तरह का मामला आ चुका है। तब दो मुस्लिम लड़कियां हेड स्कार्फ और फुल स्लीव्स का मसला लेकर पहुंची थीं। ए मोहम्मद मुस्ताक वाली पीठ ने तब कहा था कि स्कूल का डेकोरम होता है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। बेशक, यह उनका अधिकार है। लेकिन, एक तरफ इंडिविजुअल है और दूसरी तरफ लार्जर इंटरेस्ट की बात है। तो प्रॉयरिटी उसे दी जाएगी। स्कूल के पास अधिकार है कि वो अपने यहां डेकोरम मेनटेन करें। यह पूरा मामला प्रोपगेंडा का है। यह विवाद हिजाबी और गैर-हिजाबी महिलाओं पर भी आगे चलकर असर डाल सकता है।

लोगों को मिले मौलिक अधिकार असीमित नहीं

अदालत ने कहा है कि भारत में अलग-अलग धर्म के लोग और भाषाएं मौजूद हैं। इन विविधताओं के साथ भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो अपने नागरिकों को समान रूप से अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। हालांकि ये संवैधानिक अधिकार असीमित नहीं है और इन पर जरूरत के मुताबिक कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी संविधान ने देश के नागरिकों को समान मौलिक अधिकार तो दिए हैं लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं है। देश की न्यायपालिका और सरकारें चाहें तो इस पर जरूरत के हिसाब से आंशिक प्रतिबंध लगाकर संविधान को व्यवहारिक बनाए रखने का काम कर सकती हैं। हिजाब पहनने की जिद को संवैधानिक अधिकारों से जोड़ना पूर्ण रूप से सही नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि क्लासरूम में मुस्लिम छात्राओं की ओर से हिजाब पहनना, इस्लाम धर्म में अनिवार्य है कि नहीं, इसका गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है। इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा है कि भारत एक सभ्य समाज है। यहां किसी भी व्यक्ति को ये आजादी नहीं है कि वो समाज में मौजूद शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करे। मुस्लिम छात्राओं की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और इसकी वजह से स्कूलों को बंद करना खुशी की बात नहीं है। इस पर सभी को सोचने की जरूरत है। आदर्श स्थिति में भारत के स्कूलों में एक कक्षा में 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन पढ़ाया जाता है औसतन 60 बच्चों को। यानी कक्षा में एक शिक्षक एक समय में 60 बच्चों को किसी एक विषय की पढ़ाई कराता है। सितंबर 2020 में लोकसभा में ये जानकारी दी गई थी कि भारत के सरकारी स्कूलों में इस समय 17 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।

सुधर नहीं रही किसानों की दशा

महाराष्ट्र सरकार ने बीते तीन वर्षों के दौरान किसानों के 39 हजार करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए, बावजूद इसके वहां बीते साल लगभग ढाई हजार किसानों ने आत्महत्या की। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 2547 था।

यह सरकारी आंकड़ा है कि औसतन हर दिन दो हजार किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। देश के आधे से अधिक किसान परिवार कर्जे में दबे हैं और औसतन 74,121 रुपए प्रति परिवार कर्जा है। इसमें से 69.9 प्रतिशत कर्ज बैंक या सहकारी समितियों से है, जबकि 20.5 प्रतिशत साहूकारों से लिया गया है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में खेती क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत है, लेकिन इससे कुल रोजगार का 42 प्रतिशत सृजित होता है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित और चरम मौसम ने देश में दस्तक दे दी है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। जब देश में खेती का 55 फीसदी बरसात पर निर्भर हो तो जाहिर है कि खेती-किसानी के प्रति कोताही देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकती है।

एक साल तक चले कृषि कानून विरोधी आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले पंजाब में दिसंबर 2021 में 1200 करोड़ के किसानी कर्जे माफ किए गए, लेकिन देखते ही देखते 14 हजार हैक्टेयर अर्थात् कुल जमीन के 0.33 प्रतिशत पर खेती बंद हो गई। राजस्थान में 61.8 फीसदी किसान-परिवार कर्जदार हैं तो उप्र में आधे (50.8 प्रतिशत) किसान-परिवारों पर कर्जा है। मप्र के 45.7 फीसदी किसान-परिवारों पर कर्ज की रकम चढ़ी है तो उत्तराखंड में ऐसे किसान-परिवारों की संख्या 43.8 प्रतिशत है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की रिपोर्ट से यह भी झलकता है कि वर्ष 2013 से 2019 के बीच कई राज्यों में किसान-परिवारों पर मौजूद कर्जे में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। मिसाल के लिए असम के किसानों पर 6 साल की अवधि में कर्जा 382 प्रतिशत बढ़ा है तो त्रिपुरा के किसानों पर कर्जे की रकम में 378 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मिजोरम में तो किसान-परिवारों पर कर्जे की रकम में 709 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

हरियाणा ऐसा राज्य है जिसकी 81 फीसदी जमीन खेती लायक है, जहां की दो तिहाई आबादी खेती पर निर्भर है, जहां 65 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और यदि वहां की कृषि विकास साल दर साल घटती जाए तो यह न केवल बड़े संकट, बल्कि सामाजिक विघटन की तरफ भी इशारा है। हाल ही में समाप्त हुए कृषि कानून विरोधी आंदोलन का असर हरियाणा के गांवों में गहराई से देखा गया, उसके राजनीतिक कारक भले ही अन्य कई हों, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि देश में कृषि आय के मामले में तीसरे स्थान पर रहने की बावजूद यहां किसान सालभर में औसतन एक चपरासी के वेतन से भी कम आमदनी प्राप्त कर पाता है। एक तो विभिन्न विकास कार्य में जमीन का अधिग्रहण और फिर बढ़ते परिवार के साथ जोत का आकार बहुत कम होना, खेती में लागत बढ़ने, कर्ज के चस्के में फंसा किसान और गैर पारंपरिक फसलों के जरिए जल्दी पैसा कमाने की चाहत ने हरियाणा में खेती के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है।

नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन की हालिया जारी सालाना रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के किसान की मासिक आय औसतन 22,841 रुपए है। यह तब है जब इस आय में परिवार द्वारा खेती के लिए किए गए श्रम-मजदूरी की गणना की नहीं गई है। जाहिर है कि यह कमाई एक सबसे नीचे के पायदान के सरकारी कर्मचारी से भी बहुत कम है। हरियाणा में लगभग 24.8 लाख किसान हैं और 15.28 लाख खेतिहर मजदूर। लगभग 49.32 प्रतिशत किसानों के पास जोत की जमीन एक हैक्टेयर से भी कम है, जबकि एक से दो हैक्टेयर वाले किसान 19.29 फीसदी हैं। 17.79 प्रतिशत किसानों के पास चार से दस हैक्टेयर जमीन का मालिकाना हक है और महज 2.52 फीसदी किसान ही 10 हैक्टेयर से अधिक के मालिक हैं। शायद तभी राज्य में खेती छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। वर्ष 1983 में राज्य में जहां 71 प्रतिशत पुरुष किसान थे, जो आज घटकर 35 प्रतिशत रह गए हैं, जबकि इस अवधि में महिला किसानों की संख्या 90 से कम होकर 61 प्रतिशत रह गई है। यही कारण है कि हरियाणा का किसान हर दिन कर्ज के दल दल में धंसता जा रहा है। राज्य के 45,95,805 धरती पुत्रों पर इस समय 7931 हजार करोड़ कर्ज की देनदारी है। एक बारगी लगता है कि कर्जदार की संख्या किसान से ज्यादा क्यों है? असल में कई किसानों पर दो-तीन किस्म के कर्जे चढ़े हैं, बीज, खाद, बागवानी, पशु या मछली पालन या सिंचाई के लिए। इस दुश्चक्र में फंसे लगभग ढाई लाख किसान हर साल बैंक में डिफाल्टर हो जाते हैं। इसके अलावा आढ़ती या स्थानीय सूद खोर का कर्जा अलग होता है।

● जय सिंह

किसानों को चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था चाहिए

एक बात जान लेना जरूरी है कि किसान को न तो कर्ज चाहिए और न ही बगैर मेहनत के कोई छूट या सब्सिडी। इससे बेहतर है कि उसके उत्पाद को उसके गांव में ही विपणन करने की व्यवस्था और सुरक्षित भंडारण की स्थानीय व्यवस्था की जाए। किसान को सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है कि उसके खाद-बीज-दवा के असली होने की गारंटी हो तथा किसानी के सामानों को नकली बेचने वाले के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो। अधिक फसल उत्पादन की दशा में किसान को बिचौलियों से बचाकर सही दाम दिलवाने के लिए जरूरी है कि सरकारी एजेंसियां खुद गांव-गांव जाकर खरीदारी करें। सब्जी-फल-फूल जैसे उत्पाद की खरीद-बिक्री स्वयं सहायता समूह या सहकारी के माध्यम से करना कोई कठिन काम नहीं है।

विपक्ष होने लगा जागरूक

बजट सेशन में विपक्ष की आवाज का असर देखने को मिला है। बड़े दिनों बाद विपक्ष की खामोशी टूटती नजर आई है। सोशल मीडिया पर भी लोगों के रिएक्शन पर गौर करें तो वे भी विपक्षी नेताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देते नजर आए हैं। सत्तापक्ष की तरफ से विपक्ष को मुद्दा विहीन बताकर खारिज करने की कोशिश भी की गई है। फिर भी भाजपा के प्रभाव में न आकर लोग संसद में उठाए गए मुद्दों को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिखे हैं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बजट पर रिएक्शन के बाद वित्तमंत्री की टिप्पणी 'यूपी टाइप' का ढंग से विरोध हुआ है और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिस तरीके से मोदी और राहुल गांधी में फर्क समझाया, वो भी बेअसर रहा। सिर्फ राहुल गांधी के भाषण की ही कौन कहे, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और आरजेडी सांसद मनोज झा के संसद में दिए भाषण की भी खूब चर्चा और तारीफ हुई है। ये सभी लोग अपनी-अपनी पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल थे।

2021 के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से 2022 के विधानसभा चुनावों की शुरुआत के बीच विपक्षी खेमे में काफी उठापटक देखने को मिली है और कदम-कदम पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच सीधा टकराव महसूस किया गया है, लेकिन संसद के भीतर तो नजारा अलग ही देखने को मिला। क्या ये सोनिया गांधी की पहल का नतीजा हो सकता है? ममता बनर्जी की शरद पवार से मुलाकात और यूपीए को नकार देने के बाद सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस और टीएमसी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बने शरद पवार भी शामिल हुए थे। ये तभी की बात है जब शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के कई सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी भी देखे गए और टीएमसी सांसद भी, क्योंकि निलंबित सांसदों में टीएमसी के नेता भी थे।

सोनिया गांधी की बुलाई मीटिंग से जो खबर निकलकर आई, पता चला चर्चा के प्रमुख मुद्दों में ममता बनर्जी भी शामिल थीं और संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर भी बात हुई। लेकिन जिस तरह गोवा में ममता बनर्जी और राहुल गांधी फिर से आमने-सामने देखे गए और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के इरादे पर उठते सवालों में निशाने पर राहुल गांधी नजर आए, लगा नहीं कि कुछ फर्क पड़ने वाला है। बजट सत्र का नजारा काफी अलग है। ऊपर से विपक्ष वैसे ही बिखरा नजर आ रहा है, जैसे पहले था, लेकिन एजेंडा कॉमन लग रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने मुद्दे अलग-अलग उठाए हैं, लेकिन सभी के भाषण में बेरोजगारी, संविधान, पेगासस पर फोकस देखने को मिला है और ये सब अगले आम चुनाव तक जारी रहा तो लगता नहीं परिस्थितियां 2019 जैसी फिर से हो सकती हैं।

कांग्रेस में टीम भावना जरूरी

कांग्रेस नेतृत्व को भी अब टीम भावना के साथ विपक्ष के सपोर्ट में खड़े रहने की जरूरत है। दमखम बरकरार रहा तो जैसे 10 साल तक यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर विपक्ष के बड़े-बड़े दिग्गज सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार किए रहे, आगे भी कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरने लगे तो अपने आप बाकी नेता पीछे लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन लाइन वहीं से शुरू होगी जहां राहुल गांधी खड़े होंगे, अभी तो नहीं चलने वाला है। अभी के हिसाब से देखें तो आगे भी नहीं चलने वाला। कहने का मतलब जल्दी नहीं चलने वाला है। हालांकि, संसद में राहुल गांधी ने जिस तरह गंभीर होकर मुद्दों पर बात की है, वो यूं ही नहीं लगता। अब विपक्षी दलों के सभी नेताओं को हकीकत समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये एक चुनाव या 5 महीने का संघर्ष नहीं है। 5 साल भी लग सकते हैं और उससे ज्यादा भी लगे रहना पड़ेगा, फिर तो जिसका भी प्रदर्शन बेहतर होगा, सिकंदर भी वही बनेगा।

विपक्ष के एकजुट न होने का सत्तापक्ष हमेशा ही फायदा उठाता रहा है। पहले ऐसा फायदा कांग्रेस उठाया करती थी, अब वही काम भाजपा कर रही है, लोकतंत्र की तमाम खूबसूरत चीजों के बीच ये एक आवश्यक बुराई की तरह ही लगता है। चल क्या रहा है, किरदार बदल जाते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं। विपक्ष में अब साफ-साफ दो धड़े बन चुके हैं। एक तो पहले से ही कांग्रेस और गांधी परिवार है, मुकाबले में पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत के बाद ममता बनर्जी भी खड़ी हो गई हैं। साथ में दो फैक्टर और भी जुड़ गए हैं, जिनके अपने-अपने राजनीतिक गुणा-गणित हैं, शरद पवार और प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, थोड़-थोड़े दिन के अंतराल पर विपक्ष से जुड़े मुद्दों पर बहस को किसी न किसी बहाने आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी ऑडियो के जरिए तो कभी वीडियो लीक कराकर और जब ये सब थमता है तो ट्विटर पर। हाल फिलहाल वो अलग-अलग मीडिया फोरम पर इंटरव्यू देकर चर्चा को बरकरार रखे हुए हैं।

महुआ मोइत्रा की तरफ से अभी जिन 200 सीटों का जिक्र सुनने को मिला है, वो थ्योरी भी प्रशांत किशोर की ही है और उसकी चर्चा ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात में भी हो चुकी है। शरद पवार का स्टैंड भी साफ ही हो चुका है कि वो ममता बनर्जी की तरह कांग्रेस मुक्त विपक्षी एकता के खिलाफ हैं, लेकिन वो गांधी परिवार की तरफ से नेतृत्व की दावेदारी से पीछे हट जाने का इंतजार भी कर रहे हैं। कांग्रेस के भरोसे कब तक सीपीएम का ड्राफ्ट राजनीतिक प्रस्ताव भी अभी चर्चा में शामिल हो गया है। राजनीतिक प्रस्ताव को अप्रैल में होने वाले सीपीएम के सम्मेलन में अंतिम रूप दिया जाना है और फिलहाल ये फीडबैक के लिए पेश किया गया है।

सीपीएम के इस ड्राफ्ट में निशाने पर कांग्रेस ही है। कहा गया है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। कांग्रेस की संगठनात्मक शक्ति और प्रभाव दोनों ही कम हो गए हैं। लिहाजा भाजपा के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों को एकजुट करने में नाकाम रही है। प्रस्ताव मसौदे में कहा गया है कि कांग्रेस को भाजपा के बराबर

मोदी और उनकी सरकार की कोई विश्वसनीयता नहीं

विपक्ष की नजर में मोदी और उनकी सरकार की कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसके उलट जनता की नजरों में मोदी से ज्यादा कोई विश्वसनीय नेता देश में नहीं है। वास्तव में यह संघर्ष मोदी-भाजपा बनाम विपक्ष नहीं है। यह देश के आम लोगों और विपक्ष के बीच का संघर्ष है। मोदी को तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मोदी पर हर हमले का जवाब तो जनता ही दे रही है। जवाब जनता दे रही है, इसका मतलब यह नहीं कि भाजपा हर चुनाव जीत रही है या जीतेगी। राज्यों में चुनावी हार-जीत कोई बड़ी बात नहीं है। उससे मोदी का विजय रथ रुकता नहीं। यह युद्ध के बीच में लड़ी जाने वाली छोटी लड़ाइयां हैं, जिनमें हार-जीत की अहमियत महज तात्कालिक है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को ही देख लीजिए। सारे मोदी विरोधियों की जुबान पर एक ही बात है, मोदी-भाजपा चुनाव हार गए। हारता वह है, जो अपना राज्य और ऐतिहासिक संदर्भ में कहें तो राजपाट हार जाता है। बंगाल में भाजपा का कभी राज था ही नहीं। जिन दो पार्टियों का करीब 30-30 साल तक राज रहा, उनकी हार पर आपको एक शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। तो पिछले लगभग 7 साल में हार-जीत की परिभाषा बदल गई है। इस अवधि में मोदी सरकार ने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में इतने बड़े-बड़े काम किए हैं, जो आम लोगों को तो दिखाई देते हैं, लेकिन एक वर्ग को दिखता ही नहीं। हालत यह है कि यदि मोदी कह दें सूरज पूरब से उगता है तो उनके विरोधी कहेंगे, प्रमाण दो। हम कैसे मान लें? वे मानकर चलते हैं कि मोदी कह रहे हैं तो गलत ही होगा। भला मोदी कोई सही बात या काम कर कैसे सकते हैं?

खतरनाक तो नहीं माना जा सकता, लेकिन कांग्रेस के साथ राजनीतिक गठबंधन भी नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, केरल तो नहीं लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में सीपीएम ने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया था।

अब सवाल ये है कि कांग्रेस के कमजोर होने से भी बाकियों को फर्क क्यों पड़ना चाहिए? ऐसा भी तो नहीं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो क्या विपक्ष भी नहीं बचेगा? जब तक लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी हुई है, ये भी ऊर्जा की तरह ही शाश्वत है, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही क्रिएट किया जा सकता है। बस उसे इधर-उधर शिफ्ट होते देखा जा सकता है। कांग्रेस कमजोर पड़ी और 2014 में सत्ता गवां दी। सत्ता पर कोई और काबिज हो गया, भारतीय जनता पार्टी। अगर कांग्रेस और कमजोर पड़ती है तो विपक्ष का नेतृत्व भी हाथ से फिसल जाएगा कोई और नेतृत्व करेगा।

विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सत्ता की निगरानी के लिए। सत्तापक्ष मजबूत होना चाहिए देश के लिए, सही और जरूरी फैसले लेने के लिए, अति सर्वत्र वजर्येत्, इसलिए बैलेंस बना रहे वही बेहतर होगा। विपक्ष में सबकी बराबर भागीदारी है। किसी को कांग्रेस के भरोसे बैठे रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा भी तो कह ही रही हैं, हम यहां सरकार को लड्डू-पेड़े खिलाने के लिए बैठे हैं।

विपक्षी खेमा भले ही बहुत मजबूत नहीं हो सका हो, लेकिन जागरूक होता नजर आने लगा है। जाहिर है भाजपा भी महसूस कर रही होगी अगर अब भी सतर्क नहीं है तो जितना जल्दी हो सके, हो ही जाना चाहिए। संसद से सड़क तक, यानी चुनाव मैदान में भाजपा के प्रति मायावती का व्यवहार एक जैसा नजर आता है और बिलकुल वैसे ही पार्टी के खिलाफ बाकी राजनीतिक दलों का भी।

अगर उप्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो, ध्यान रहे, जैसे संसद में विपक्ष अलग-अलग खेमे में बंटा नजर आया है, चुनावी मैदान में भी प्रमुख दलों का आपस में गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग तो बन ही चुकी है। ऐसा कदम-कदम पर लग रहा है। जैसे माायावती उप्र में भाजपा के प्रति नरम रुख अपनाए हुए नजर आती हैं, संसद में भी बसपा सांसद मलूक नागर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई काट नहीं है। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में मलूक नागर कहते हैं, देश में पिछले 70 साल से दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय होता रहा है, लेकिन अब जाकर लगता है, ऐसा माहौल बना है... पिछड़ों और दलितों को न्याय मिलने वाला है क्योंकि इसी सदन में आकर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इतने दलित मंत्री बने हैं और इतने पिछड़ों को मंत्री बनाया गया है।

बाकी भाजपा विरोधी दलों को देखें तो अलग ही भाव नजर आता है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के बदले कांग्रेस करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला करती है। जब बुलंदशहर में भी प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार करते-करते आमना-सामना हो जाता है तो फिर से मुलाकात होती है। दुआ सलाम होती है। अखिलेश यादव ट्विटर पर लिखते हैं, 'एक दुआ-सलाम... तहजीब के नाम', तो प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब मिलता है, 'हमारी भी आपको राम-राम।'

राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह बताने लगे हों, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का व्यवहार पहले से ही सवालों के घेरे में रहा है और ये महज हिमंत बिस्वा सरमा के कुत्तों वाले बिस्कुट तक ही सीमित नहीं है। अगर ममता बनर्जी के दिल्ली में कदम रखते ही राहुल गांधी अचानक एक्टिव हो जाते हैं और विपक्षी दलों के साथ मीटिंग करने लगते हैं, तो क्या दिखाने की कोशिश होती है, यही ना कि विपक्ष के नेतृत्व की जिम्मेदारी कांग्रेस की जागीर है और इसे वो शेयर नहीं करने वाली है। अगर कांग्रेस कार्यकारिणी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने जैसे मुद्‌दों का विरोध न करने की सलाह देते हैं और उनकी आवाज दबा दी जाती है, क्या समझा जाए?

गुजरते वक्त के साथ जैसे सिंधिया, जितिन और आरपीएन कांग्रेस का साथ छोड़ दिए, विपक्षी खेमे के नेता भी तो वैसा ही करेंगे। ये सच्चाई कांग्रेस नेतृत्व जितना जल्दी समझ ले, बेहतर होगा। जिस मीटिंग में ये तीनों नेताओं को चुप कराने की कोशिश की गई थी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। बाद में राहुल गांधी ऐसे नेताओं को डरपोक बताने लगे और हाल ही में प्रियंका गांधी की भी ऐसी ही राय रही। प्रियंका के मुताबिक कांग्रेस मुश्किल लड़ाई लड़ रही है और हर किसी के लिए टिके रहना आसान नहीं है। ऐसे में अगर कोई कांग्रेस छोड़कर कहीं और ठिकाना ठीक समझता है तो चलेगा।

● विपिन कंधारी

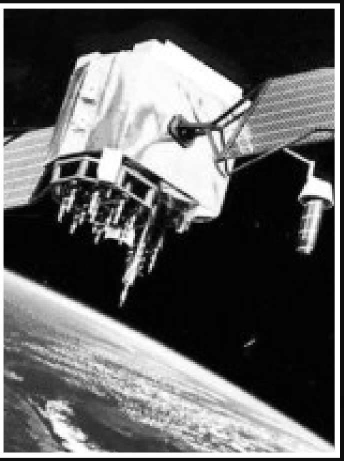

देवास मल्टीमीडिया का उद्देश्य सैटेलाइट के इस्तेमाल से संचार (मोबाइल पर बातचीत) सिस्टम को बेहतर करना था। इससे यह होना था कि आज हर दूसरा उपभोक्ता जिस तरह कमजोर इंटरनेट या मोबाइल सिग्नल की शिकायत करता है, वह शायद सैटेलाइट मोबाइल के होने से नहीं होती। लेकिन विवादों के कारण योजना अधर में लटक गई।

देवास-एंट्रिक्स का जिन्न फिर निकला बाहर

दिसंबर, 2004 में गठित देवास मल्टीमीडिया कंपनी, जो बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप कंपनी थी, से जुड़े देवास-एंट्रिक्स सौदे का मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक जंग का कारण बन गया है।

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह देश और देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा था।

सीतारमण का यह आरोप ऐसे समय में आया है, जब देवास के शेयरधारकों ने 1.29 अरब डॉलर की वसूली के लिए विदेशों में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि सीतारमण के आरोपों के बाद चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने इस आरोप पर चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है। सन् 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस समझौते को यह आरोप लगने के बाद रद्द कर दिया गया था कि यह मिलीभगत से भरी डील है। सन् 2014 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौदे की जांच करने के लिए कहा गया था। अब जनवरी के शुरू में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यूपीए सरकार को इस सौदे पर फटकार लगाने के अलावा देवास मल्टीमीडिया प्रालि की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि कंपनी को बंद करने का आदेश खारिज किया जाए।

महत्वपूर्ण यह है कि देवास मल्टीमीडिया प्रालि कंपनी का सन् 2005 में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) की वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स के साथ सैटेलाइट सौदा हुआ था। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ने देवास मल्टीमीडिया प्रालि की याचिका को ख़ारिज़ करते हुए 17 जनवरी के अपने फैसले में कहा कि देवास मल्टीमीडिया को एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े के मकसद से ही बनाया गया था। इसके बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बाकायदा एक पत्रकारवार्ता करके आरोप लगाया कि इस मास्टर गेम की खिलाड़ी कांग्रेस है। सीतारमण ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि साफ पता चलता है कि कैसे यूपीए सरकार ने इस मामले में गलत हथकंडे अपनाए थे।

इस सारे मामले में बड़ा सवाल यह है कि देवास मल्टीमीडिया के साथ यह महत्वपूर्ण डील बिना पूरी परख किए बिना कैसे और क्यों की गई ? चूंकि इस सौदे में इसरो के उत्पाद के दूसरे देशों के लिए मुहैया कराने वाली सरकार के

कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगाई : सीतारमण

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद यूपीए की पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने देवास मल्टीमीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य से इस्तेमाल होने वाला एस-बैंड स्पेक्ट्रम देने को देश के साथ धोखाधड़ी की और निंदनीय बताया। सीतारमण ने कहा कि सरकार अब करदाताओं के पैसे बचाने के लिए न्यायालयों में लड़ रही है, अन्यथा यह राशि मध्यस्थता फैसले के भुगतान में चली जाती, जो देवास ने सन् 2005 के सौदे को रद्द करने पर जीता है। सीतारमण ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन को इस आधार पर बरकरार रखा कि इसे धोखाधड़ी के इरादे से किया गया था। सीतारमण ने एंट्रिक्स और देवास के बीच 2005 में हुए सौदे पर कहा कि यह देश के लोगों के साथ, देश के साथ धोखाधड़ी थी। एस-बैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और उसे थोड़े से धन के बदले दे दिया गया। सीतारमण ने कहा कि देवास ने ऐसी बातें करने का वादा कर दिया, जो उसके अधिकार में ही नहीं थीं।

मालिकाना हक की कंपनी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन थी, लिहाजा पूरी परख किए बिना इसे करना आश्चर्यजनक है और कई सवाल खड़े करता है। यह मामला इसलिए भी गंभीर था, क्योंकि इसरो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को रिपोर्ट करता है। लिहाजा विवाद सरकार के लिए चिंता पैदा करने वाला रहा। एक और बड़ा सवाल यह भी है कि जब देवास का फर्जीवाड़ा सामने आ ही गया था और 2011 में यूपीए के समय सौदा रद्द कर दिया गया, उसी समय सरकार ने देवास के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलटी) में जाने की जरूरत क्यों नहीं समझी? मामले की जांच तब शुरू हुई, जब सन् 2015 में सीबीआई ने गड़बड़ी का पर्दाफाश किया।

देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बीच साल 2005 में सैटेलाइट सेवा से जुड़ी एक डील हुई थी। बाद में यह सामने आया कि इस सौदे में सैटेलाइट का इस्तेमाल मोबाइल से बातचीत के लिए होना था। हालांकि इसमें गड़बड़ यह हुई कि इसके लिए पहले से सरकार की मंजूरी ही नहीं ली गई थी। देवास मल्टीमीडिया उस समय एक स्टार्टअप था और 2004 में इसे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सचिव प्रबंध निदेशक एमडी चंद्रशेखर ने बनाया था।

जनवरी, 2005 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और देवास के बीच एमओयू पर दस्तखत हुए। समझौते के मुताबिक, एंट्रिक्स को दो सैटेलाइट बनाने, पॉन्च करने और संचालित करने और 90 फीसदी सैटेलाइट ट्रांसपोंडर्स निजी कंपनी को लीज पर देने थे। सौदे में 70 मेगाहर्ट्स एस-बैंड का 1000 करोड़ रुपए की कीमत का स्पेक्ट्रम था। यहां यह बता दें कि यह स्पेक्ट्रम आमतौर पर सुरक्षा बलों और एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी सरकारी दूरसंचार संस्थाओं के उपयोग के लिए था।

हालांकि इस दौरान एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यह सौदा देश के खजाने में दो लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर सकता है। इसके बाद इस सौदे पर सवाल उठने शुरू हो गए। इसके बाद फरवरी, 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने सौदे को रद्द कर दिया और इसका आधार 'सुरक्षा कारण' बताया। उस समय जी माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे। बाद में अगस्त, 2016 में पूर्व इसरो प्रमुख जी माधवन नायर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर गलत तरीके से देवास को 578 करोड़ रुपए का लाभ दिलाने का आरोप लगा। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया। सितंबर, 2017 में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ने विदेशी निवेशकों की अपील पर देवास को 1.3 अरब डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया।

दो साल बाद जून, 2019 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) न्यायाधिकरण ने कहा कि भारत ने देवास के विदेशी शेयरधारक डॉयचे टेलीकॉम एजी की शुरू की गई मध्यस्थता में जर्मनी की द्विपक्षीय निवेश संधि का उल्लंघन किया है। जनवरी, 2020 में तीन मॉरीशस-आधारित संस्थाओं सीसी/देवास (मॉरीशस) लिमिटेड, देवास एम्प्लॉइज मॉरीशस प्रालि और टेलीकॉम देवास मॉरीशस लि, जिन्होंने देवास में 37.5 फीसदी हिस्सेदारी रखी, ने अमेरिका के कोलंबिया जिला न्यायालय में यूएनसीआईटीआरएएल के आदेश की पुष्टि की मांग की।

इसके बाद अक्टूबर, 2020 में वाशिंगटन के अमेरिकी संयुक्त न्यायालय (फेडरल कोर्ट) ने आईसीसी के अवॉर्ड की पुष्टि की, जिसमें इसरो की एंट्रिक्स को देवास को 1.2 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। नवंबर, 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के खिलाफ दलीलें सुनने का निर्देश दिया। बाद में जनवरी, 2021 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एंट्रिक्स को कंपनी अधिनियम के तहत देवास के खिलाफ एक समापन याचिका शुरू करने का निर्देश दिया। एनएलसीटी ने देवास के खिलाफ एंट्रिक्स की याचिका मंजूर कर ली और अनंतिम परिसमापक (प्रोविजनल लिक्विडेटर) नियुक्त किया। उसी साल सितंबर में एनसीएलएटी ने देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखा।

साल के आखिरी दो महीनों में दो अलग-अलग आदेशों में, सौदा रद्द करने के यूपीए सरकार के फैसले के बाद विदेशी निवेशक भारत सरकार के खिलाफ कनाडा कोर्ट में चले गए। यहां यह बताना भी दिलचस्प है कि 2011 में इन निवेशकों की याचिकाओं के आधार पर दस साल बाद 2021 में कनाडा की न्यायालय ने एयर इंडिया (एआई) और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया। हालांकि अब जनवरी में कनाडा की न्यायालय ने अपने उस फैसले पर फिलहाल रोक लगाकर आईएटीए के पास पड़ी एएआई संपत्तियों को फ्रीज करने पर रोक हटा दी। देवास मल्टीमीडिया ने इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) में फैसले के खिलाफ मध्यस्थता कार्रवाई शुरू की थी।

● इन्द्र कुमार

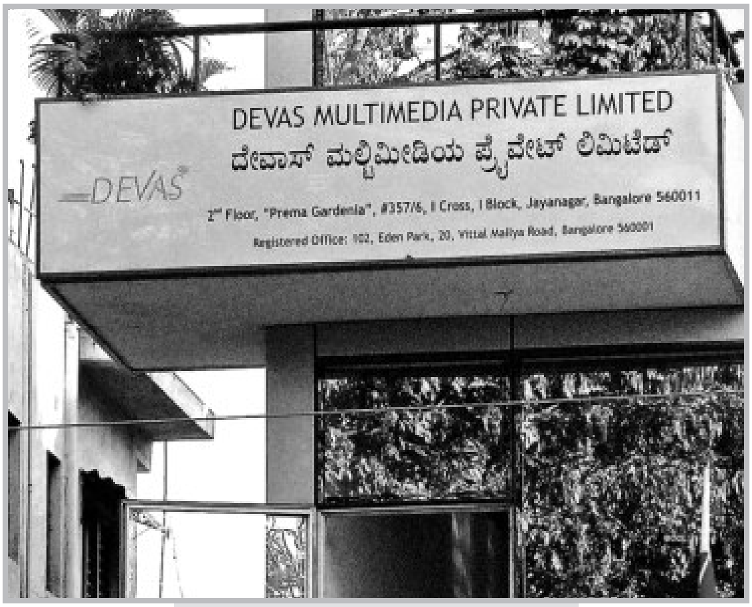

कंपनी में लगा था विदेशी पैसा

साल 2011 में जब इस सौदे में फर्जीवाड़े की बातें सामने आईं, तो इस सौदे को यूपीए की सरकार ने रद्द कर दिया। देवास मल्टीमीडिया में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों का पैसा लगा हुआ था, बेशक यह भारतीय कंपनी थी। सौदा रद्द होते की निवेशकों में हडकंप मच गया, क्योंकि विदेशी निवेशक इससे बड़े संकट में फंस गए। यह हैरानी की बात है कि सन् 2005 में जब यह सौदा किया गया, तबसे लेकर 2011 तक यूपीए सरकार को इसमें फर्जीवाड़े की भनक ही नहीं लगी, या किसी स्तर पर इसे पता होने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया गया। अब देवास के शेयरधारकों ने 1.29 अरब डॉलर की वसूली के लिए विदेशों में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। देवास को इस धनराशि की भरपाई का आदेश अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरणों ने दिया था। देवास को पेरिस में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के लिए फ्रांसीसी न्यायालय ने आदेश दिया है और कंपनी कनाडा में एयर इंडिया के धन को जब्त करने की मांग भी कर रही है।

ओबीसी की काट के लिए ओबीसी

छत्तीसगढ़ का 40 प्रतिशत हिस्सा जंगलों से ढंका है। 47 प्रतिशत आबादी छत्तीसगढ़ में ओबीसी की है। इस वजह से छत्तीसगढ़ के चुनाव में हमेशा ओबीसी का दबदबा रहा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अभी करीब डेढ़ साल बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी से आते हैं इसलिए भाजपा भी कहीं ना कहीं मजबूत ओबीसी चेहरे की तलाश में जुटी है। हालांकि भाजपा में ऐसे कई आदिवासी और ओबीसी चेहरे हैं जो आगामी चुनाव में भाजपा की कमान प्रदेश में संभाल सकते हैं। इनमें कुछ युवा चेहरे भी हैं। छत्तीसगढ़ में 47 प्रतिशत आबादी ओबीसी होने की वजह से चुनाव में उनका दबदबा रहता है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें है, जिसमें से 39 सीटें रिजर्व हैं, 29 एसटी और 10 एससी वर्ग के लिए हैं। 51 सीटें सामान्य हैं इनमें से भी 11 सीटों पर एससी का प्रभाव है। प्रदेश की आधी सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव ओबीसी का है क्योंकि 47 प्रतिशत आबादी प्रदेश में ओबीसी की है। हालांकि 2018 के चुनाव में प्रदेश में 20 विधानसभा सीटों में ओबीसी के विधायकों ने जीत हासिल की थी। सामान्य विधानसभा सीटों में 24 विधायकों ने जीत हासिल की थी।

अब तक प्रदेश में हुए 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं। साल 2003 में 75 प्रतिशत एसटी सीटें भाजपा ने जीती थी। 2008 में 66 प्रतिशत और 2013 में 36 प्रतिशत सीटें ही भाजपा जीत पाई थी। साल 2008 में परिसीमन के बाद ओबीसी वर्ग का दबदबा और बढ़ा। साल 2003 में 19 ओबीसी विधायक सदन में पहुंचे। 2013 में यह संख्या बढ़कर 24 हो गई लेकिन 2018 के चुनाव में ओबीसी के 20 विधायक जीत पाए थे। क्या ओबीसी की काट, ओबीसी ही होना चाहिए? राजनीति के जानकारों ने बताया कि राजनीति में खासकर चुनाव के समय जातिगत आधार का एक महत्व तो है लेकिन ओबीसी की काट ओबीसी ही हो यह जरूरी नहीं है। हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या आदिवासियों की है। विष्णु देव साय भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं वह या उनके स्थान पर किसी तेजतर्रार आदिवासी चेहरे को भाजपा मुख्यमंत्री के लिए आने वाले चुनाव में सामने रख सकती है। लेकिन भाजपा की राजनीति थोड़ी अलग तरह से होती है। अगर हम 2002-03 की बात करें तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस समय रामानुज यादव थे। पिछड़ा वर्ग और आदिवासी की राजनीति उस समय चल रही थी। उसके उलट डॉ. रमन सिंह को भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष बनाया। चुनावी राजनीति अलग होती है और संगठन चलाने की क्षमता अलग होती है। आगामी चुनाव में भाजपा की तरफ से पिछड़ा वर्ग या किसी आदिवासी तेजतर्रार भाजपा नेता को कमान दी जा सकती है।

शशांक शर्मा का कहना है कि भाजपा में युवा नेताओं से लेकर कई ओबीसी और जनजाति समुदाय के बड़े चेहरे हैं। युवा चेहरों में केदार कश्यप, महेश गागड़ा हैं। इसके अलावा रामविचार नेताम, विष्णु देव साय भी हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग में धरमलाल कौशिक, विजय बघेल, ओपी चौधरी, अजय चंद्राकर शामिल हैं। सवाल यह है कि संगठन को लेकर आगामी चुनाव में जनता का विश्वास जीतकर सरकार बनाने की स्थिति पैदा कर सके ऐसा नेतृत्व चाहिए और जो सभी को साथ लेकर भी चल सके, वरना जातिगत चेहरे तो बहुत हैं।

उधर, भाजपा ने पिछले एक सप्ताह में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खिलाफ अलग-अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन किया। इसमें पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रहे नेताओं की दूरी प्रदेश संगठन को खटक रही है। यही कारण है कि आंदोलन में भाग नहीं लेने वाले नेताओं की एक रिपोर्ट केंद्रीय संगठन को भेजने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन ने रायपुर के प्रदर्शन से लेकर बस्तर और सरगुजा के प्रदर्शन की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने भी अपनी बैठक में वरिष्ठ नेताओं और चुनाव हारे उम्मीदवारों की सक्रियता नहीं होने का मुद्दा उठाया था। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो प्रदेश में 15 साल सरकार रहने के दौरान सत्ता और संगठन में भागीदार नेता अचानक गायब हो गए हैं। कुछ चुनिंदा नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो विधानसभा उम्मीदवार रहे नेता भी सक्रिय नहीं हैं। संगठन की बैठक हो या फिर आंदोलन, इन नेताओं के नहीं आने से केंद्रीय संगठन चिंतित है। प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के 15 उम्मीदवारों को जीत मिली थी।

रमन सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार गए। इनमें से दो-तीन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी शांत पड़े हैं। सरगुजा की राजनीति में भाजपा का चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री जिलों के आंदोलन तक में नहीं पहुंच रहे हैं। भाजपा की समर्पण निधि अभियान, माइक्रो डोनेशन कैंपेन में भी ये नेता सक्रिय रूप से नजर नहीं आ रहे हैं।

● अक्स ब्यूरो

शराबबंदी पर सियासी दलों में जुबानी जंग

छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश के 60 फीसदी आदिवासी क्षेत्र का हवाला देकर शराबबंदी के मुद्दे को जनता के पाले में डालने की कोशिश की। इस पर भाजपा ने आक्रामक होकर सवाल किया कि चुनाव के समय जब कांग्रेस नेताओं ने गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी का वादा किया था, तब क्या 60 फीसदी क्षेत्र अनुसूचित नहीं था। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी के लिए राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीन कमेटी का गठन किया है। अब तक राजनीतिक समिति की दो बैठकें हुई हैं। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी राजनीतिक दलों की राय ले रही है, लेकिन कमेटी में भाजपा का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नीयत का राजफाश हो गया है। कांग्रेस सरकार शराबबंदी लागू करने का कोई इरादा नहीं रखती। अवैध शराब से बेहिसाब कमाई हो रही है, जिसका नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मरकाम के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। शुक्ला ने कहा कि भाजपा अफवाह फैलाने की राजनीति कर रही है। शराबबंदी की कमेटी में भाजपा विधायकों के नहीं आने से स्पष्ट समझ में आता है कि वह शराबबंदी के पक्ष में नहीं है।

सियासी संकट से उबारने की कोशिश

गहलोत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई है, उन्हें मंत्री जैसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। गहलोत सरकार ने हाल ही में विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोग में 44 राजनीतिक नियुक्तियां दी हैं। इनमें 11 विधायकों को विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इन विधायकों ने पायलट कैंप की बगावत के समय गहलोत सरकार को सियासी संकट से उबारने में मदद की थी। राज्य सरकार का कहना है कि कानूनी राय लेने के बाद ही विधायकों को नियुक्तियां दी गई है। किसी विधायक को मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं दिया गया है। विधायक के अलावा किसी तरह का लाभ नहीं दिया गया है। भाजपा द्वारा राजनीतिक नियुक्तियों को कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया है।

संवैधानिक व्यवस्था में इन नियुक्तियों को लाभ का पद माना जाता है। ऐसे में इन नियुक्तियों पर अंकुश लगा रहेगा। भाजपा ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बोर्ड, निगम और आयोगों में नियुक्तियां संविधान के खिलाफ हैं। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि ऐसे पदों पर विधायकों की नियुक्तियों पर पूर्व में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ चुके हैं। विधायकों की ऐसी नियुक्तियों में अलग से पद मानकर लाभ की सुविधा नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार संयम लोढा का कहना है कि कानूनी राय लेने के बाद ही विधायकों को नियुक्तियां दी गई है। किसी विधायक को मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं दिया गया है। विधायक के अलावा किसी तरह का लाभ नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सियासी संकट में मदद करने वाले बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक एवं निर्दलीय विधायकों को विभिन्न बोर्ड, आयोग एवं निगमों का अध्यक्ष बनाया है। विधायक महादेव सिंह खंडेला, रफीक खान, दीपचंद खैरिया, मेवाराम जैन, खिलाड़ीलाल बैरवा, हाकम अली खान, लाखन मीणा, जोगिंद्र सिंह अवाना, कृष्णा पूनिया, लक्ष्मण मीणा और रमीला खड़िया को राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया है।

शेखावाटी में बसंत का आगमन राजनीतिक नियुक्तियों की बहार लेकर आया है। मंत्री पद जाने के बाद सीकर में ठंडी पड़ी राजनीति में नियुक्तियों ने गर्माहट ला दी है। वहीं अंचल के चूरू और झुंझुनूं जिले का भी सरकार में कद बढ़ा है। खंडेला विधायक महादेव सिंह को राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। खंडेला यह पद पाने वाले सीकर के दूसरे विधायक है। कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में किसान आयोग के गठन कर पहला अध्यक्ष नारायण सिंह को बनाया था। अब फिर कांग्रेस राज में इस पद पर सीकर के विधायक की तैनाती रही है। वहीं फतेहपुर विधायक हाकम अली खान को राजस्थान वक्फ विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। दांतारामगढ़ क्षेत्र में सक्रिय रहे युवा नेता सीताराम लांबा को राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की गई है।

सीकर जिले में कांग्रेस की जड़े हमेशा से गहरी रही हैं। कांग्रेस सरकार में प्रतिनिधित्व की बात करें तो गत विधानसभा चुनाव में आठों सीटों पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा। खंडेला विधायक महादेव सिंह ने हालांकि चुनाव निर्दलीय जीता, लेकिन सरकार के संकट के समय पूरा साथ निभाया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि महादेव सिंह को इसी का लाभ मिला है। हाकम अली को राजस्थान वक्फ विकास परिषद में अध्यक्ष का दायित्व देकर अल्पसंख्यकों को खुश करने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक नियुक्तियों में शेखावाटी के सीकर जिले का कद बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस के पिछले राज से तुलना की जाए तो प्रतिनिधित्व में कमी महसूस की जा रही है। कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में विधायक राजेंद्र पारीक मंत्री, दीपेंद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष, नारायण सिंह किसान आयोग के अध्यक्ष के साथ परसराम मोरदिया को आवासन मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। इस कार्यकाल में लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को मंत्री के बाद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद डोटासरा के पास महज कांग्रेस अध्यक्ष का ही दायित्व रह गया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक नियुक्तियों में चूरू जिले का विशेष ध्यान रखा है। रेहाना रियाज पर विश्वास जताते हुए उनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया है। रेहाना रियाज पहले महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। खेलों में चूरू का दुनिया में नाम रोशन करने वाली डॉ. कृष्णा पूनिया को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने उन्हें राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किया है। कृष्णा सादुलपुर से विधायक हैं। इसी प्रकार सरदारशहर के अनिल शर्मा को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल का चेयरमैन मनोनीत किया है। शर्मा सरदारशहर विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं। इनके मनोनयन पर जिलेभर में कार्यकर्ताओं में खुशी का आलम बना हुआ है।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटारसी (म.प्र.)

आओ... इटारसी नगर पालिका परिषद को स्वच्छ बनाएं...

अपील

- धरती, पानी, हवा रखो साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ।
- स्वच्छ होगा इटारसी, दूर होंगे रोग।
- कूड़ा-कचरा डस्टबीन में ही डालें।
- अपने आसपास साफ-सफाई रखें।
- मास्क लगाकर ही बाहर निकलें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, इटारसी

मौखिक निर्देश पर फंसती नौकरशाही

एक लोकतांत्रिक देश को ठीक से चलाने के लिए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश के भाग्य विधाताओं ने काफी सोच-विचार करके ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका आदि का गठन किया होगा। इनके चयन और चुनाव की प्रक्रिया तय की गई होगी। गलतियां होने पर उन्हें सुधारने की व्यवस्था भी दी गई होगी। लेकिन आज लोकतंत्र के उक्त तीनों अंगों की जिम्मेदारियां गड्ड-मड्ड होती दिखाई दे रही हैं। वैसे ये गड्ड-मड्ड कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन इसका सबसे सटीक उदाहरण इन दिनों महाराष्ट्र में दिख रहा है।

महाराष्ट्र में तीन दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद से व्यवस्था कम बल्कि दुर्व्यवस्था कुछ ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। इससे न केवल सबक लेने की जरूरत है, बल्कि इसमें सुधार के प्रयास भी किए जाने जरूरी हैं। राज्य में इन दिनों किसी न किसी पूर्व या वर्तमान नौकरशाह के ऐसे बयान आ जाते हैं, जिनके कारण राजनीतिक नेतृत्व गंभीर आरोपों में फंसता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार में गृहमंत्री का पद किसी राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए बनाया गया है। दुर्भाग्य देखिए, इस राज्य का गृहमंत्री ही इन दिनों कई गंभीर आरोपों में अपने पद से इस्तीफा देकर अब जेल की हवा खा रहा है। पुलिस आयुक्त का पद किसी बड़े महानगर की पुलिस को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाया गया होगा। आज मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त पर ही हफ्तावसूली के कई मामले दर्ज हैं। राजनीतिक नेतृत्व ने कुछ दशक पहले गंभीर अपराध खत्म करने का शार्टकट ढूंढ़ते हुए ही 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' जैसी व्यवस्था को जन्म दिया होगा। आज मुंबई के कई पूर्व 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' निर्दोष नागरिकों को मारकर खुद जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं।

किसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे पदों से बहुत जिम्मेदारी, ईमानदारी और साफगोई की उम्मीद की जाती है। आज इस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ही जांच एजेंसियों के सामने सिर झुकाए यह कबूल करते दिखाई दे रहे हैं कि मुझे मौखिक निर्देश देकर ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए कहा जाता था, और पद में कनिष्ठ होने के कारण मैं मना नहीं कर पाता था। वाकई लाज आने लगी है अपने लोकतंत्र पर ऐसे बयान सुनकर। करीब-करीब ठीक एक साल पहले 2021 के फरवरी महीने में हुए एंटीलिया कांड ने महाराष्ट्र में राजनीतिक नेतृत्व एवं नौकरशाही के बीच चल रही गड्ड-मड्ड की पोल खोलकर रख दी है। कौन उम्मीद कर सकता था कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देश के ही शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के निकट एक विस्फोटक लदा वाहन खड़ा कर दिया जाएगा? वह भी स्काटलैंड यार्ड के बाद सबसे सक्षम पुलिस का तमगा लेकर घूमनेवाली मुंबई पुलिस की ही छत्रछाया में! लेकिन जब इस पूरे मामले की पोल खुली तो पता चला कि यह काम तो खुद पुलिस के अधिकारी ही करवा रहे थे। वही अति कनिष्ठ अधिकारी करवा रहे थे, जिन्हें खुद गृहमंत्री मुंबई के अर्केस्ट्रा बारों एवं रेस्टोरेंटों से हर महीने करोड़ों रुपए वसूली के 'मौखिक निर्देश' देते थे। अब पता चल रहा है कि सचिन वाझे नामक इस सहायक पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी को फर्जी एनकाउंटर के एक मामले में 16 साल निलंबित रहने के बाद राज्य में उद्धव सरकार आते ही बहाल कर दिया गया था। सभी नियमों को ताक पर रखकर उसकी बहाली करवाने में खुद तत्कालीन गृहमंत्री और मुख्यमंत्री ने रूचि ली थी।

खुद अनिल देशमुख ने माना है कि वाझे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिलवाने के लिए शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे और अनिल परब जैसे मंत्रियों के फोन आते थे। लेकिन आलाकमान का वरदहस्त पाकर मनबढ़ हुए इस अधिकारी ने जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर खुद विस्फोटक लदी कार खड़ी करने जैसी बड़ी गलती कर दी, तो आलाकमान को अपनी भी गर्दन फंसती दिखाई देने लगी। तब उन्होंने सारा ठीकरा तत्कालीन पुलिस आयुक्त के सिर फोड़ दिया। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, जब किसी राजनेता ने अपनी मुसीबत अपने अधीनस्थ नौकरशाह के सिर डाली हो। लेकिन मामला तब उलटा पड़ गया, जब नौकरशाह भी सवा सेर निकला। उसने चुपचाप सबकुछ स्वीकार कर लेने के बजाय आलाकमान पर ही पलटवार कर दिया। यानी पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने खुद को पद से हटाए जाते ही अपने आलाकमान अनिल देशमुख की सारी करतूतें एक पत्र में लिखकर सार्वजनिक कर दीं। परिणामस्वरूप अनिल देशमुख को न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच में फंसकर जेल भी जाना पड़ा।

● **बिन्दु माथुर**

दूर तक जाती है बात

कहते हैं न कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सो वही हुआ। मामला 100 करोड़ रुपए की वसूली वाले भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं रहा। अनिल देशमुख पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इस आरोप की शुरुआत भी राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार आने के साथ ही शुरू हो गई थी। यानी सरकार बनते ही ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल शुरू हो गया था। इस मामले की आंच तो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती दिखाई दे रही है। क्योंकि सरकार बनने के बाद जब राज्य में उच्च स्तर पर ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल शुरू हुआ तो राज्य खुफिया विभाग की तत्कालीन प्रमुख आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने इस मामले पर निगाह रखने के लिए तत्कालीन अपर मुख्य सचिव (गृह) से कुछ लोगों के फोन रिकार्ड करने की अनुमति मांगी। तब अपर मुख्य सचिव (गृह) की जिम्मेदारी संभाल रहे वरिष्ठ आईएएस सीताराम कुंटे ने रश्मि शुक्ला को यह अनुमति दे भी दी। कुंटे सैद्धांतिक रूप से दृढ़ आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। लेकिन सारे फोन रिकॉर्ड्स के साथ रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्योंकि राज्य में चल रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट में सबसे ऊपरी पायदान के लोग भी शामिल थे। इसमें खुद गृहमंत्री के भी शामिल होने के सबूत मिल रहे थे।

बसपा के संस्थापक कांशीराम ने अपनी विरासत और दलित उद्धार की जो जिम्मेदारी मायावती को सौंपी थी, बहनजी न तो उस विरासत को बचा पाईं और न ही दलित समाज का कोई उद्धार कर पाईं। उप्र में चुनाव सिर पर हैं, मगर बहनजी और उनके हाथी का अतापता नहीं है।

विरासत नहीं बचा पाईं मायावती!

उप्र में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों ने जनता को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा जहां प्रदेशभर में विजय संकल्प यात्रा और जन विकास यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस का जन जागरण अभियान चल रहा है। समाजवादी पार्टी की भी विजय रथ यात्रा प्रदेशभर में जारी है। यहां तक कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तक हैदराबाद छोड़ उप्र में डेरा जमाए हुए हैं और 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उप्र में 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। मगर इन सब के बीच 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकीं बसपा प्रमुख और दलित नेत्री मायावती की चुनावी तैयारी बहुत फीकी-फीकी सी है।

चुनाव सिर पर हैं, मगर बहनजी के पुराने तेवर कहीं दिख नहीं रहे हैं। न कोई दावा न वादा, न यात्रा, न संकल्प, न समारोह। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ओमप्रकाश राजभर, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, ओवैसी सब सड़कों पर हैं, बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे हैं, भाषणबाजी में लगे हैं, मगर बहनजी और उनके हाथी की चाल सुस्त है। हाथी की यह सुस्ती बेवजह नहीं है। दरअसल उप्र में चुनाव से पहले सबसे ज्यादा टूट का सामना बसपा कर रही है। रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पता चलता है कि पिछले 7 सालों में 150 से ज्यादा नेता बसपा का साथ या तो छोड़ चुके हैं, या निकाले जा चुके हैं। इनमें कई वे चेहरे भी थे जो कभी पार्टी की पहचान हुआ करते थे। आज बसपा के पास विधानसभा में मात्र 5 विधायक बचे हैं, जिनमें से एक मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं।

बसपा के संस्थापक कांशीराम ने अपनी विरासत और दलित समाज के उद्धार की जो जिम्मेदारी मायावती को सौंपी थी, बहनजी न तो उस विरासत को बचा पाईं और न दलित समाज का कोई उद्धार कर पाईं। वे, उनकी पार्टी और पार्टी के नेता बीते 3 दशकों में सिर्फ धनउगाही, भ्रष्टाचार और घोटालों में रमे रहे। बहनजी अपने कुछ खास करीबियों की मदद से अपना बटुआ भरती रहीं और अपनी शोहरत बुलंद रखने के लिए अपनी मूर्तियां गड़वाती रहीं। दलित समाज के लिए उन्होंने क्या किया, यह तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाकर ढूंढ़ने से भी मालूम नहीं चलेगा।

आज प्रदेश का दलित समाज नेतृत्वविहीन है। शहरी दलित भाजपा के भरमाने में फंसकर खुद को हिंदू और हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निचली जातियों में फिर वही डर पनपने लगा है कि भाजपा राज मजबूत हुआ तो वे सवर्णों के तलुवे चाटने वाले अछूत और तुच्छ तो कहलाएंगे ही, शोषण और प्रताड़ना का दंश भी झेलेंगे। यह डर उन पिछड़ों और दलितों को अब विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बांट रहा है जो कभी मायावती की एक ललकार पर हाथी छाप झंडे के नीचे जमा हो जाते थे। आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नेता कौन है, उन्हें किसके पीछे चलना है, किसको वोट देना है, कौन उनका उद्धारक होगा।

बसपा संस्थापक कांशीराम ने जीवनपर्यंत दलितों को मजबूत बनाया, साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी वोट शेयर में इजाफा किया। दलित राजनीति के सक्रिय होने का श्रेय बिना किसी संदेह के उन्हीं को जाता है। कांशीराम का मानना था कि अपने हक के लिए दलितों को लड़ना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी।

कांशीराम का दौर दलितों के राजनीतिक रूप से चेतनशील होने का दौर था। बहुत कम समय में उनकी पार्टी बसपा ने उप्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। उत्तर भारत की राजनीति में गैरब्राह्मणवाद की शब्दावली बसपा ही प्रचलन में लाई थी। 1992 में राममंदिर आंदोलन के समय भाजपा जहां हिंदुत्व कार्ड खेल रही थी, कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी बहुत खुरदुरे तरीके से दलितों को समझा रही थी कि उसकी अपनी बिरादरी से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी बड़े पावर ग्रुप का नाममात्र चेहरा न हो बल्कि अपनी ताकत और तेवर दिखाने वाला दलित नेता हो। वर्ष 1995 में कांशीराम इसमें कामयाब हो गए जब उनकी शिष्या मायावती उप्र की मुख्यमंत्री बनीं। मायावती को एक नेता के तौर पर कांशीराम ने ही ग्रूम किया था। वे मायावती के मार्गदर्शक थे। अपनी बीमारी व मौत से कई साल पहले ही उन्होंने मायावती को अपना राजनीतिक प्रतिनिधि चुन लिया था। मगर कांशीराम के तेवरों को सही से आगे न ले जाने के चलते मायावती जिस तेजी से उप्र में उभरी थीं, उसी तेजी से वे उप्र में सिर्फ एक जाति की नेता बनकर रह गईं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

सोशल इंजीनियरिंग का दाव भी बेकाम

कांशीराम का दलित आंदोलन देखते ही देखते मायावती की सोशल इंजीनियरिंग बनकर खत्म हो गया। कांशीराम जहां व्यक्तिगत रूप से बेहद सादा जीवन जीते थे, वहीं मायावती ने धनवैभव के प्रदर्शन को दलित शक्तिप्रदर्शन का प्रतीक बना दिया। मंडल युग में कांशीराम के संघर्ष के चलते पिछड़ा और दलित वर्ग अपने अधिकारों को लेकर पहली बार सचेत हुआ था। संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर के बाद कांशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई थी। बेशक अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन वे कांशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा। कांशीराम भले ही अंबेडकर की तरह महान चिंतक और बुद्धिजीवी न रहे हों, मगर उन्होंने जिस जमात की लड़ाई लड़ी वह संविधान में हक मिलने के बावजूद अशिक्षा, गरीबी, शोषण, प्रताड़ना, बेकारी और बंधुआ मजदूरी का शिकार थी। कांशीराम ने इस जमात के लिए सवर्णों द्वारा तय किए फर्मे तोड़े और उनमें कुछ करने व कुछ पाने का आत्मविश्वास पैदा किया।

वंश वॉर

वैसे बिहार में राजनीतिक मर्यादाओं को ताख पर रखने का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। लालू परिवार के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं। हालांकि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के बयान सरकस्टिक होते हैं, लेकिन इन दिनों लालू के बोल बेहद निजी और बिगड़े नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से एक सीधा सवाल वंशवाद पर पूछा गया था। मगर लालू को ये सवाल इतना चुभ गया कि उन्होंने नीतीश कुमार पर निजी हमला बोल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा 'नीतीश जी को तो भगवान ए गो दिए हैं उ भी राजनीति के काबिल नहीं....' लाजिम सी बात है इस बयान पर बिहार की राजनीति गर्म होना है। इतना ही नहीं लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने बोलते-बोलते कहा कि 'भगवान से प्रार्थना है कि मोदी जी को भी भगवान एक दो बेटा-बेटी दें ताकि परिवारवाद समझ आए।'

दरअसल वजह ये थी कि तेजस्वी की ताजपोशी की चर्चा तेज है। शिवानंद तिवारी जिन्होंने अपनी पहचान समाजवादी नेता के रूप में बना रखी है। उन्होंने अपने मूल विचार से अलग लालू परिवार के वंशवाद का समर्थन कर दिया। जिसे लेकर पहले जदयू की तरफ जवाबी हमला किया गया। बाद में जब लालू यादव से वंशवाद की राजनीति पर सवाल पूछा गया तो निजी होकर वे राजनीतिक मर्यादा ही भूल बैठे। ऐसे बयान को लेकर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपनी उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं वो सजायाफ्ता हैं, कैदी नंबर 351 हैं और उनकी भाषा भी कैद खाने में चली गई है। नीरज कुमार ने कहा, पिछड़ों के बेटों का बाल कटवाते थे और अपने बेटा को डीपीएस में पढ़ाते थे। उन्होंने कहा नीतीश जी के पिता सामाजिक परिवर्तन के वाहक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने परिवारवाद के खिलाफ एक मानक साबित किया है। ये संस्कारी पिता का संस्कारी बेटा जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है। अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। इंजीनियरिंग पढ़ता है। बीआईटी मेसरा से पढ़ता है। उन्होंने कहा कि लालू जी का दुर्भाग्य है कि उनका बेटा 8वीं भी पास नहीं कर सका है। लेकिन लालू जी के बेटे 420 के आरोपी हैं।

बिहार की राजनीति आज चौराहे पर खड़ी दिखाई दे रही है। बिहार के सभी राजनीतिक गठबंधनों में खींचतान मची है। सबसे ज्यादा बवाल अभी एनडीए गठबंधन में है। भाजपा और जदयू में तो बयान के तीर चल ही रहे थे, उधर भाजपा और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी में ठन गई है। भाजपा नहीं चाहती है कि मुकेश सहनी की पार्टी उप्र में चुनाव लड़े, लेकिन मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं हैं। भाजपा तमाम तरीकों से मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश कर चुकी है। तब भाजपा ने गठबंधन के तहत बोचहा सीट वापस लेने की भी धमकी दी, जब इस पर भी मुकेश सहनी नहीं माने तो फिर भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि उन्हें जहां जाना है वहां जाएं।

भाजपा जिस तरीके से बयान दे रही है उससे तो यही लगता है कि उसे सरकार से मतलब नहीं है। बहुत कम संख्या में बहुमत से चल रही सरकार में भला कहीं ऐसा कहा जा सकता है। मुकेश सहनी को भाजपा के कोटे की सीट मिली हुई है। वर्तमान में उनके तीन विधायक हैं। भाजपा ये मानकर चल रही होगी कि उनके विधायक उनके साथ नही जाएंगे। तभी इस तरह के बयान भाजपा के तरफ से आ रहे हैं। मुकेश सहनी मंत्री जरूर हैं, लेकिन जिस एमएलसी सीट से वो विधायक हैं उसका कार्यकाल इसी साल जून में खत्म हो जाएगा।

उधर राजद ने दावा किया था कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगा। राजद प्रवक्ता मृत्युन्जय तिवारी का कहना है कि खेला तो शुरू हो चुका है अब देखिए क्या होता है। जिस तरह से भाजपा मुकेश सहनी का अपमान कर रहे हैं उससे बहुत कुछ साफ है। गत दिनों भाजपा ने पटना में कोर कमेटी की बैठक पटना में बुलाई थी। जिसमें बिहार के वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चर्चा की गई और उसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी गई। इन सबके बीच जदयू उप्र में भाजपा से गठबंधन नहीं होने पर भी चुनाव लड़ने पर आमादा है। भाजपा ने यह साफ भी कर दिया है कि कम सीट होने के बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे में जदयू को उप्र में भाजपा की मदद करनी चाहिए। अब इस सियासी घालमेल में बिहार की राजनीति किस रास्ते जाएगी ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन उप्र चुनाव तक बिहार की राजनीति भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगी।

● **विनोद बक्सरी**

नर्मदापुरम को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहभागी बनें...

अपील

- सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ-सफाई।
- गंदगी को दूर भगाओ, नगर पालिका को स्वच्छ बनाओ।
- शौचालय का प्रयोग करें, शहर को खुशियों से भरें।
- समय पर टैक्स भरें, विकास में योगदान करें।

श्री नीरज सिंह
कलेक्टर एवं प्रशासक

श्री शैलेंद्र बड़ोनिया
तहसीलदार एवं प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी

बड़े खतरे का संकेत

यूक्रेन में तनाव बढ़ रहा है। रूस ने उसकी सीमा पर करीब एक लाख अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित सैनिक तैनात कर दिए हैं और अमेरिका लगातार रूस को यूक्रेन पर किसी भी तरह की कार्रवाई के खिलाफ चेता रहा है। अमेरिका अपने मित्र देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। अब अमेरिका ने अपने कई जंगी जहाज और हथियार यूक्रेन भेजे हैं। रक्षा जानकार यूक्रेन और रूस के बीच गंभीर रूप से उभर रहे इस तनाव को दुनिया की शांति के लिए बड़े खतरे का संकेत मान रहे हैं। वैसे रूस ने बार-बार कहा है कि वह यूक्रेन पर हमले का इरादा नहीं रखता, लेकिन अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि फरवरी में रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। नाटो ने हाल में कहा था कि उसने पूर्वी यूरोप के इलाके में युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को तैनात कर अपने दस्तों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल में कहा था कि अमेरिका यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। हालांकि जो गंभीर बात उन्होंने कही वह यह है कि अगर रूस सीमा के पास तैनात किए गए अपने अनुमानित एक लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला करता है, तो यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण होगा। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ऐसा करता है, तो इससे दुनिया बदल जाएगी। अमेरिकी सेनाएं यूक्रेन नहीं जाएंगी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तनाव सन् 2014 में ही शुरू हो गया था, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला करके उसके क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा जमा लिया था। रूसी सेना का तब यूक्रेन की सेना ने साहस से मुकाबला किया था, लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। इस हमले के बाद क्रीमिया में रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच जारी जंग में अब तक करीब 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। दोनों के बीच तनाव बना हुआ है जो अब काफी गंभीर रुख अख्तियार कर गया है।

अमेरिका यूक्रेन की खुले तौर पर मदद कर रहा है। दोनों देशों के बीच इस तनाव के चलते नाटो और पश्चिमी देश सक्रिय हैं। यूक्रेन को युद्ध की किसी भी स्थिति में मजबूत करने की मंशा से खुद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ब्रिटेन, स्वीडन और तुर्की आदि ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करनी शुरू कर दी है। हालांकि चुप रूस भी नहीं बैठा है और उसने हाल के दिनों में यूक्रेन की सीमा पर विमानभेदी (एंटी एयरक्राफ्ट) मिसाइल, टैंक, तोप, सशस्त्र वाहन (आर्म्ड व्हीकल) के अलावा करीब एक लाख सैनिकों की फौज खड़ी कर दी है। चिंता की बात यह है कि रूस और अमेरिका के बीच इस मसले को हल करने और तनाव खत्म करने के लिए प्रयास नाकाम साबित हुए हैं।

रूस यूक्रेन पर यूरोपीय संघ से अपने रिश्तों को खत्म करने पर जोर दे रहा है। सन् 2014 के बाद से यूक्रेन अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, क्योंकि उसे भय है कि इससे नाटो की उसकी सीमा तक पहुंच हो जाएगी। रूस को लगता है कि यूक्रेन के कारण ही अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देश, जो रूस को पसंद नहीं करते, रूस की सीमा तक पहुंच बना रहे हैं। हालांकि जनवरी के आखिर में पेंटागन के एक प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया कि रूस को यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने की कोशिशों का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने का समर्थन करता है।

अमेरिकी सेना के अधिकारी हाल के सैलून में लगातार यूक्रेन के दौरे करते रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन-रूस की सीमा पर भी स्पॉट किए गए हैं। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच इस तनाव के कारण रक्षा जानकार यूरेशिया क्षेत्र में बड़े सैनिक टकराव की आशंका जाता रहे हैं। जाहिर है दोनों के बीच युद्ध हुआ तो यह सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच तक सीमित नहीं रहेगा और किसी बड़े युद्ध में भी बदल सकता है। अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा कि यूक्रेन और रूस सुलह का कोई रास्ता अपनाएंगे। दुनियाभर की नजर इस पर लगी है कि अगर युद्ध हुआ, तो आखिर होगा क्या? अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने अमेरिका और यूरोप में मौजूद अपने करीब 8,500 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। अगर जरूरत पड़ी, तो इन्हें नाटो की पूर्वी यूरोपीय सीमा पर तैनात किया जाएगा। इस तरफ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया आते हैं। ये वो देश हैं, जो सन् 1989 के बाद नाटो में शामिल हुए।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

अपील

- कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, अति आवश्यक हो तभी घर से निकलें अन्यथा घर पर ही रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करें।
- स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 अन्तर्गत सूखा कचरा नीले डस्टबीन में एवं गीला कचरा हरे डस्टबीन में डालें।
- समय पर नगरपालिका के सम्पत्तिकर, दुकान किराया, जलकर एवं अन्य करों का भुगतान करें।
- अपने पालतू पशुओं को सड़क पर आवारा न छोड़ें जिससे जानमाल की हानि न हो।
- पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए पॉलिथीन का उपयोग न करें।

श्री राकेश मिश्रा
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
न.पा. सिवनी मालवा

प्रगाढ़ हो रही इजरायल-भारत मैत्री

इन दिनों हम इजरायल और भारत के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इजरायल के राजनयिकों के लिए भारत सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, क्योंकि भारत में इजरायल के कई मित्र हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच बहुत प्रेम, आदर और गहरी दोस्ती है। 29 जनवरी, 1992 को औपचारिक रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से इजरायल और भारत ने मिलकर जो हासिल किया है, वह अभूतपूर्व है। हमारी दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच का संबंध हजारों वर्ष पुराना है। भारत का यहूदी समुदाय इन संबंधों की आधारशिलाओं में से एक है। **यहूदी पीढ़ियों** से भारत में शांति के साथ रह रहे हैं। उन्हें कभी भी उत्पीड़न या विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। सबको अपनाने वाला भारतीय समाज उन्हें फलने-फूलने और अपना अभिन्न अंग बनने की इजाजत देता है। इसे ही हम अतुल्य भारत के रूप में जानते हैं।

बीते 30 वर्षों के दौरान भारत के साथ इजरायल के द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में प्रगाढ़ हुए हैं। स्वास्थ्य, कृषि, जल, व्यापार, विज्ञान एवं तकनीक, अनुसंधान एवं विकास, रक्षा, कला-संस्कृति, पर्यटन एवं अंतरिक्ष इनमें प्रमुख हैं। भारत हमारा अब केवल घनिष्ठ मित्र ही नहीं है, बल्कि एक सामरिक साझेदार भी है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ अनेक उच्च स्तरीय दौरों से यह स्पष्ट भी हो जाता है। आने वाले वर्षों में और अधिक उच्च स्तरीय दौरों की योजना है।

हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत हमारे प्रमुख साझेदारों में से एक है। आज हमारे द्विपक्षीय संबंध जिन क्षेत्रों में केंद्रित हैं, वे हिंद प्रशांत में समग्र रूप से इजरायल के निरंतर हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक महामारी कोविड पर काबू पाना, आतंकवाद से लड़ना, व्यापार का विस्तार और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले खतरों से निपटना दोनों देशों की आज प्राथमिकता है। महामारी की शुरुआत के बाद से इजरायल ने कई संयुक्त योजनाओं पर भारत के साथ मिलकर काम किया है। इस दौरान हमने चिकित्सा उपकरणों का भी आदान-प्रदान किया। साथ ही निशुल्क महिला स्वास्थ्य क्लीनिक की व्यवस्था की है। दोनों देश वैक्सीन प्रमाणपत्रों की आपसी मान्यता पर भी सहमत हुए हैं। इससे दोनों देशों की आपसी समझबूझ और मजबूत हुई है। इसकी बदौलत हम स्वास्थ्य सेवा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत बनाना जारी रख सकते हैं। हमने रक्षा समेत सहयोग के अन्य क्षेत्रों में भी निरंतर प्रगति की है।

भारतीय सैन्य अधिकारियों ने इजरायल की कई उच्च स्तरीय यात्राएं करने के साथ इजरायली वायु सेना द्वारा आयोजित ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास में भागीदारी की। मेक इन इंडिया अभियान के शुरू होने से पहले से ही इजरायल मेक इन इंडिया, मेक विद इंडिया (भारत में बनाओ, भारत के साथ बनाओ) के पक्ष में रहा है। वास्तव में दोनों देश समझ चुके हैं कि लंबे समय तक दोस्ती बनाए रखने के लिए साझेदारी की जड़ों को निरंतर पोषित करना होगा। इसे अकादमिक सहयोग के स्तर पर भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें एक-दूसरे को समृद्ध करते हुए अपने साझा ज्ञान के क्षितिज का विस्तार करना चाहिए।

इजरायल में 10 प्रतिशत विदेशी छात्र भारतीय हैं। इसमें और बढ़ोतरी कैसे हो, इस पर बात चल रही है। और अधिक युवा छात्रों तक पहुंचने के लिए हम अगले पांच वर्षों में नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में मोबाइल कक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली बस को प्रायोजित करेंगे। इजरायल एक स्टार्टअप राष्ट्र है। हमारे पास प्रौद्योगिकी में भारत से साझा करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने दोनों देशों की स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों के बीच व्यावसायिक उपक्रमों में पर्याप्त वृद्धि भी देखी है। हरित ऊर्जा भी एक और ऐसा क्षेत्र है, जहां हमें सहयोग को मजबूत बनाने पर गर्व है। हाल में इजरायल-भारत नीत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। दोनों देश मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक युद्ध में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कृषि और जल भारत के साथ हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ड्रिप सिंचाई तकनीक भारत में कृषि विकास में अहम भूमिका निभा रही है।

● कुमार विनोद

भारत में इजरायल नीत कई परियोजनाएं

भारत-इजरायल कृषि परियोजना के तहत इसे विकसित किया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी कृषि परियोजना है, जिसमें इजरायल की सरकार शामिल है। जल के क्षेत्र में भारत में इजरायल नीत कई परियोजनाएं चल रही हैं। बुंदेलखंड, उप्र की प्रमुख जल परियोजना सबसे हाल की है। कई इजरायली कंपनियां पहले से ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से भारत में जल प्रबंधन में परिवर्तन ला रही हैं। जल के क्षेत्र में अपने सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने पहली बार जल संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञ के रूप में एक विशेष दूत को नियुक्त किया है, जो भारत में सरकारी अधिकारियों और उद्योगों के साथ मिलकर काम करेगा। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना जारी रखें और द्विपक्षीय सहयोग के असीमित दायरे का पूरा उपयोग करते रहें। हमारे युवा, ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्थाएं हमें द्विपक्षीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधन प्रदान कर रहे हैं। हमारे संबंधों की नींव काफी मजबूत है। इस पर हम अपने रिश्ते की ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं।

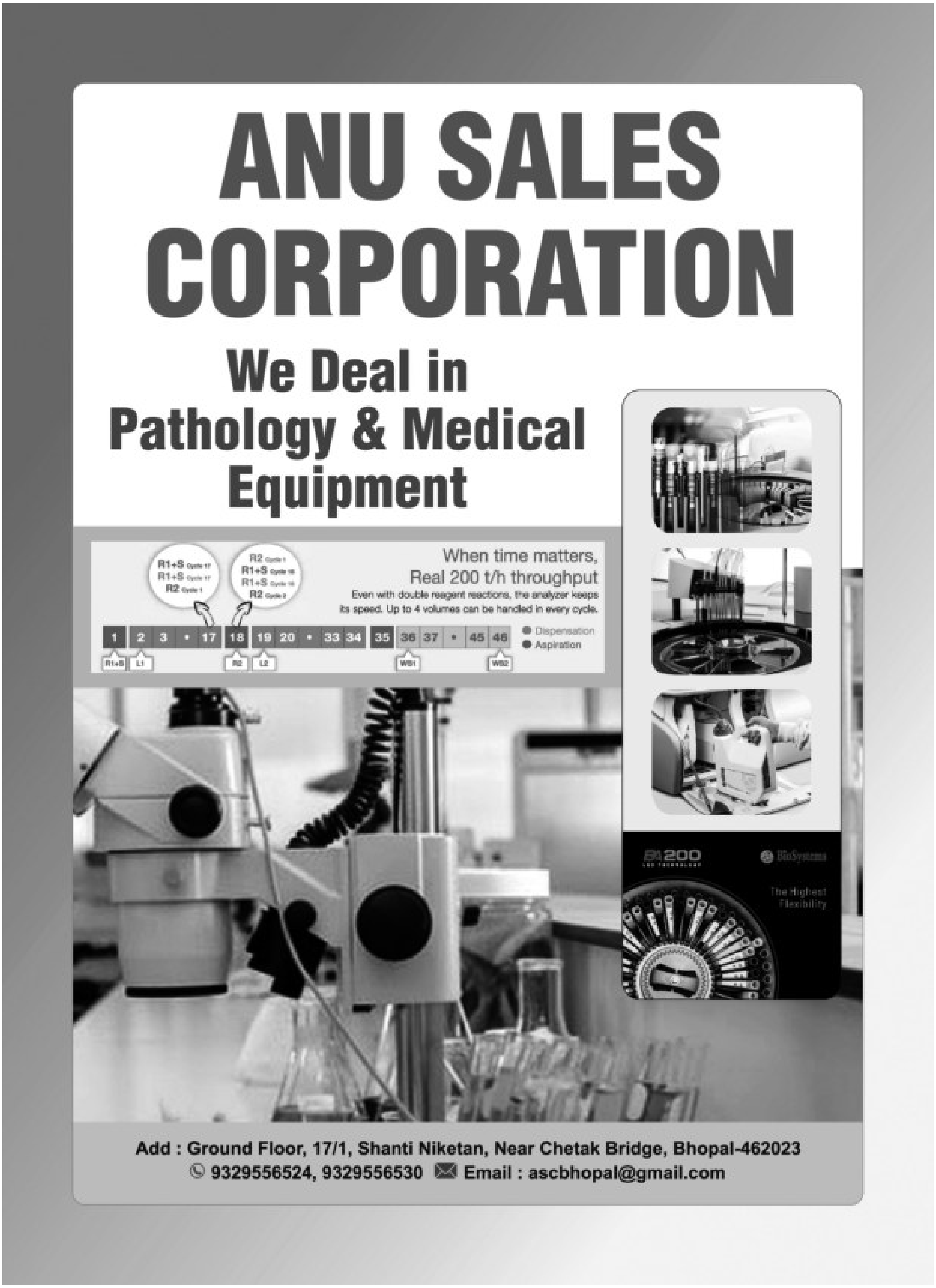
ANU SALES CORPORATION
We Deal in
Pathology & Medical
Equipment
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।

कोरोना और निमोनिया की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराई गई लता दीदी ने 29 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद 6 फरवरी की सुबह 8 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि हर बार की तरह लता दीदी इस बार भी मौत को मात देकर घर लौट आएंगी। लेकिन किसी को क्या पता कि नामुराद कोरोना उनको हमसे हमेशा के लिए छीन लेगा।

न भूतो, न भविष्यति!

नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही, पहचान है, गर याद रहे...फिल्म किनारा के इस गाने को अपनी आवाज देने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी देह छोड़ी है। उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हर किसी के कानों में ऐसी ही गूंजती रहेगी। उसके मन को सुकून देती रहेगी। देखा जाए तो एक इंसानी शरीर को जितनी सांसें मिलती हैं, उतनी ही लता दीदी को मिली थीं। लेकिन अपनी सांस का हर कतरा-कतरा कैसे सुर, संगीत, संसार, समाज और परिवार के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये लता मंगेशकर से सीखा जाना चाहिए। महज 13 साल की उम्र में सिर से पिता का साया हटने के बाद उन्होंने जिस तरह से खुद को दरकिनार करके परिवार को पाला, 80 साल तक जिस तरह से सुर साधना की और जिस ईमानदारी के साथ अपने पेशे में बनी रहीं, इसकी बानगी समाज में विरले ही देखने को मिलती है।

पिछले दो साल के दौरान कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में जमकर तांडव मचाया है। दूसरी लहर के दौरान तो हमारे आसपास इतने लोगों की जानें गईं कि इंसानियत भी सहम कर रहने लगी। क्या आम, क्या खास, बड़ी से बड़ी हस्तियां इसकी चपेट में आई, लेकिन किसे पता था कि तीसरी लहर हमसे हमारा अमूल्य रत्न छीन ले जाएगी। बताया जा रहा है कि लता जी की कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें कोरोना के साथ निमोनिया भी हो गया था। वो 29 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ती रहीं। पूरे देश में दुआओं का दौर जारी रहा, लेकिन जिस दिन सुर की देवी सरस्वती की आराधना में हम लगे हुए थे, उसी दिन काल हमें धोखा देकर हमसे हमेशा के लिए हमारी स्वर कोकिला को छीन ले गया।

मप्र के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को पैदा हुई लता मंगेशकर के पिता पं. दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया के जाने पहचाने नाम थे। वो मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे। लताजी ने अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा ली थी। लेकिन 13 साल की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया हट गया। पं. दीनानाथ मंगेशर का निधन हो गया। परिवार में मां के अलावा चार भाई-बहनों आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर की जिम्मेदारी उम्र में सबसे बड़ी लताजी पर आ गई। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उसमें उन्होंने परिवार के जीवकोपार्जन के लिए काम करना शुरू कर दिया। चूंकि संगीत और रंगमंच विरासत में मिला था, इसलिए उसमें काम करना उनके लिए सहज था। इसलिए उन्होंने अभिनय और गायन शुरू कर दिया। साल 1942 में रिलीज हुई मराठी फिल्म पहली मंगला गौड़ के लिए उन्होंने अपना पहला गाना गाया था। इसी फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। हालांकि, अभिनय में उनका मन नहीं रमा तो गायन पर फोकस कर लिया।

● **अक्स ब्यूरो**

80 साल की सुर साधना, शायद ही टूटे रिकॉर्ड

92 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने वाली लता मंगेशकर ने 8 दशक तक सुर साधना की है। इन 80 वर्षों के दौरान उन्होंने करीब 20 भारतीय भाषाओं में 50 हजार से अधिक गाने गाए हैं। यह किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। इसके लिए साल 1974 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था, तब उन्होंने 25 हजार से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर लिए थे। इतना ही नहीं लता जी ने करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज दी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की इतिहास में एक दौर ऐसा भी था, जब लता मंगेशकर के गानों के बिना फिल्में बनती ही नहीं थी। उनकी आवाज फिल्म की सफलता की गारंटी हुआ करती थी। जैसे आज के दौर में कंटेंट किंग है, उसी तरह उस दौर में लताजी क्वीन हुआ करती थीं। हालांकि, बाद में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से गाना कम कर दिया था। साल 2001 में उनकी संगीत साधना को देखते हुए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी थीं। उनके नाम कई नेशनल फिल्म अवॉर्ड और फिल्म फेयर अवॉर्ड भी दर्ज हैं। अब लता दीदी नहीं रहीं, लेकिन उनकी आवाज में ये शब्द हमेशा गूंजते रहेंगे...

तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे
हां तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे
जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे
संग-संग तुम भी गुनगुनाओगे

शादी नहीं की, क्योंकि भाई-बहनों की चिंता थी

सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनका परिवार था। अपने परिवार के पालन-पोषण में वो इतनी व्यस्त रहीं कि उनको शादी का कभी ख्याल ही नहीं आया। कई बार रिश्ते आए, लेकिन जिम्मेदारियों ने उनसे जुड़ने नहीं दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, पिताजी के जाने के बाद घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। यदि मैं शादी कर लेती तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरे के घर जाना पड़ता। इसलिए जब भी शादी का रिश्ता आया, मैंने मना कर दिया।

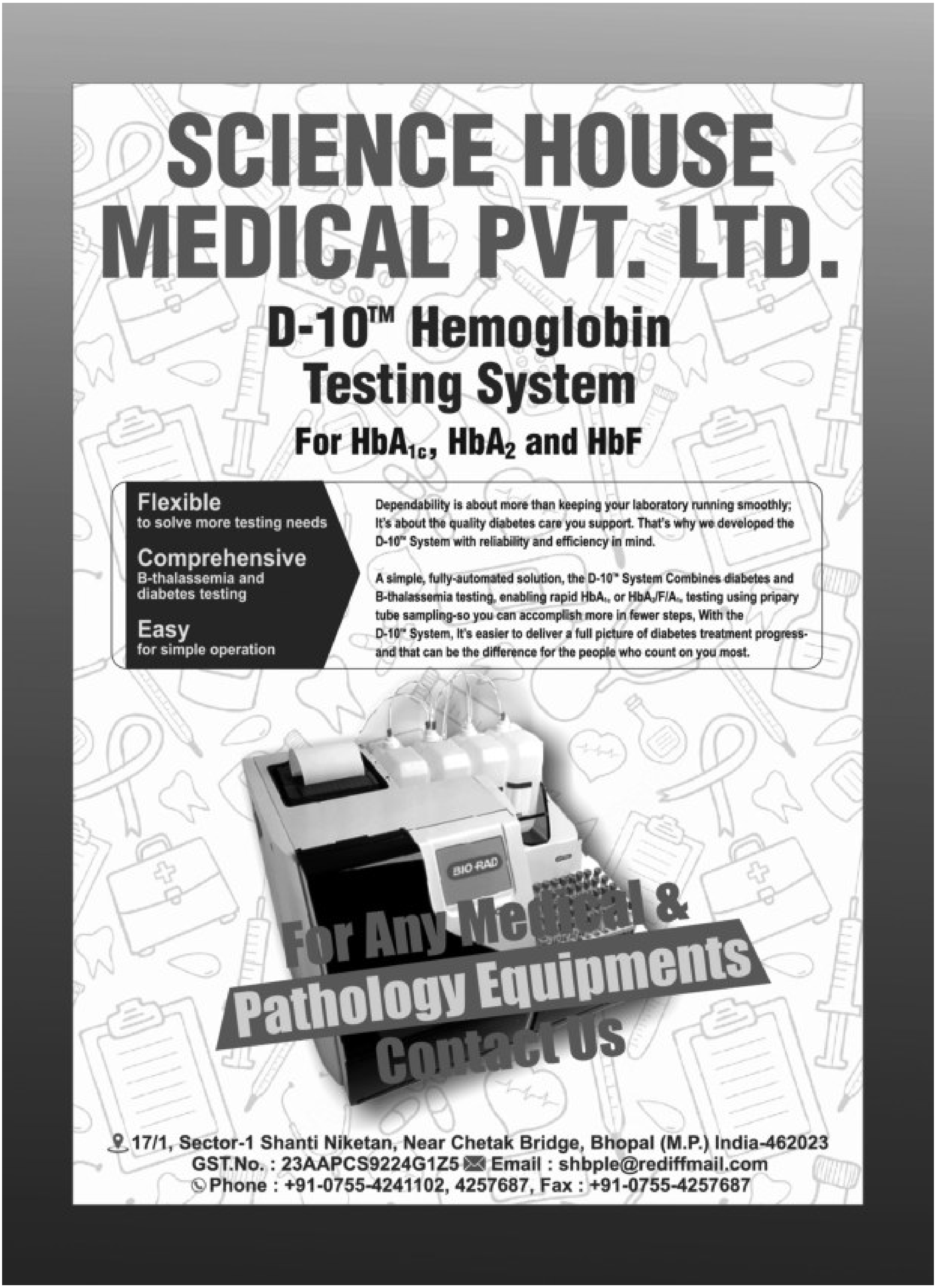

SCIENCE HOUSE
MEDICAL PVT. LTD.
D-10™ Hemoglobin
Testing System
For HbA1c, HbA2 and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA1c or HbA2/F/A1c testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.
BIO-RAD
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

खिलाड़ियों पर धनवर्षा

आईपीएल में 10 टीमें, मार्च-अप्रैल में होगी शुरुआत

आईपीएल ऑक्शन के बाद खिलाड़ियों, फैंस एवं टीमों को टूर्नामेंट के शुरू होने का इंतजार है। अभी आईपीएल 2022 के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। संभवतः मई के आखिर तक चलने वाले इस सीजन के दौरान 10 टीमों के बीच कुल 74 मैच खेले जाएंगे। अधिकांश टीम मालिकों ने इच्छा व्यक्त की है कि टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाए। बीसीसीआई भी आईपीएल 2022 को भारत में कराने के लिए उत्सुक है, लेकिन कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड प्लान-बी पर भी काम कर रही है। प्लान-बी के मुताबिक बीसीसीआई आईपीएल को साउथ अफ्रीका या यूएई में भी आयोजित कर सकती है।

आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन संपन्न हो गए हैं और सभी 10 टीमों ने अपने स्क्वॉड तैयार कर लिए हैं। सभी टीमें ज्यादा से ज्यादा 25 और कम से कम 18 खिलाड़ी लेने के लिए बाध्य थीं। इसको ध्यान में रखते हुए चार टीमों ने 25-25 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल किया है।

इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण के लिए दो दिनों तक बेंगलुरु में लगी खिलाड़ियों की बोली संपन्न हो गई। इस नीलामी में 600 खिलाड़ियों के नाम सामने आए जिसमें से 204 पर सभी फ्रेंचाइजीज ने मिलकर दांव लगाया। लखनऊ सुपर जाइंट्स ने सबसे कम 21 खिलाड़ी और जीरो पर्स के साथ ऑक्शन का समापन किया। आपको बता दें कि सभी टीमों को कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 25 खिलाड़ियों को खरीदना था। इसका ध्यान रखते हुए सभी टीमों ने आईपीएल 2022 के लिए अपना स्क्वॉड तैयार किया। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स ने सर्वाधिक 25-25 खिलाड़ियों के पूरे दल को तैयार किया।

पूरी ऑक्शन प्रक्रिया में कुल 5 अरब, 51 करोड़ और 70 लाख रुपए खर्च हुए। इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने 21 खिलाड़ियों के लिए पूरे 90 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। खास बात यह है कि लखनऊ फ्रेंचाइजी ने बाकी टीमों के मुकाबले कम खिलाड़ी खरीदे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को कप्तान बनाया है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने नीलामी से पहले राहुल के अलावा मार्कस स्टोइनिस और रवि बश्नोई को भी साइन किया था।

ईशान किशन आईपीएल 2022 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर रहे। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके साथ ही ईशान किशन आईपीएल की नीलामी में दूसरे सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। युवराज सिंह ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी हैं। युवराज को दिल्ली डेयरडेविल्स ने साल 2016 की नीलामी में 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल 2022 की नीलामी में दीपक चाहर दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। चेन्नई सुपरकिंग्स ने दीपक चाहर को 14 करोड़ रुपए में खरीदा।

आईपीएल ऑक्शन में कुछ बड़े खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना का भी नाम इन खिलाड़ियों में रहा। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले रैना को खरीदने में उनकी पिछली टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। गौरतलब है कि रैना आईपीएल के इतिहास में चौथे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। रैना ने 205 आईपीएल मुकाबलों में 5,528 रन बनाए हैं। उनसे आगे केवल विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा हैं। रैना के अलावा इयोन मॉर्गन, एरॉन फिंच, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स भी नीलामी में अनसोल्ड रहे।

ऑक्शन के पहले दिन एक अप्रिय घटना हुई, जब ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स लो ब्लड प्रेशर की वजह से स्टेज से नीचे गिर गए। जिस समय यह घटना घटी, उस समय वानिंदु हसारंगा की बोली लग रही थी। एडमीड्स को मेडिकल इमरजेंसी के तहत उपचार के लिए ले जाया गया और ऑक्शन को भी कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा था। जब दोबारा ऑक्शन शुरू हुआ तो चारु शर्मा ने ऑक्शनर की भूमिका निभाई। टीवी प्रेजेंटर एवं मशाल स्पोर्ट्स के सह संस्थापक चारू शर्मा बेहद शॉर्ट नोटिस पर ऑक्शन के लिए तैयार हुए थे। चारू शर्मा ने जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया और उन्होंने एडमीड्स की कमी नहीं खलने दी।

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले क्रिकेटर होंगे। राहुल को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने 17 करोड़ रुपए में साइन किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं। इन तीनों खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने 16-16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज ईशान किशन (15.25 करोड़) इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं।

● **आशीष नेमा**

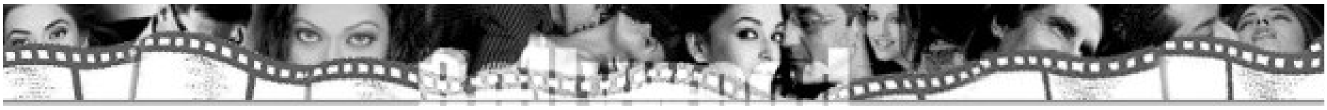

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों बॉक्स ऑफिस पर बिकने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल हैं। दोनों की पिछली कुछ फिल्में बैक-टू-बैक हिट रही हैं। दोनों सितारों में जो चीज कॉमन है- वह उनका एक्शन एंटरटेनर होना भी है। हालांकि अक्षय कुमार अब तरह-तरह की भूमिकाएं करते हैं। हाल ही में आई ब्लॉकबस्टर सूर्यवंशी में उनका कॉमिक एक्शन अवतार दिखा था। यहां बॉलीवुड के दो बड़े सितारों की चर्चा के लिए विषय मौजूं हैं। दरअसल, दोनों को लेकर बड़े मियां छोटे मियां के सीक्वल बनने की चर्चाएं हैं और इसे बल मिला है एक टीजर और सितारों की कुछ सोशल पोस्ट्स से।

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ आ रहे हैं तो बॉक्स ऑफिस पर इसके मायने बड़े हैं!

सोशल मीडिया पर करीना कपूर खान ने वासु भगनानी को टैग करते हुए एक वीडियो साझा किया। जो वीडियो साझा किया वह वासु के प्रोडक्शन में साल 1998 में आई ब्लॉकबस्टर मसाला एंटरटेनर बड़े मियां छोटे मियां का है। जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जोड़ी डबल रोल में नजर आई थी। इसी वीडियो को टाइगर श्रॉफ ने भी साझा किया जो एक तरह से चर्चाओं को पुष्ट करने वाला माना जा सकता है। इन्हीं सोशल पोस्ट्स की वजह से बड़े मियां छोटे मियां के रीमेक या सीक्वल बनने की बातें हो रही हैं। और हाल ही में एक टीजर भी रिलीज हुआ है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ मारधाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। यह पहले भी सामने आ चुका है कि सीक्वल में अक्षय और टाइगर की जोड़ी नजर आएगी। करीना कपूर ने जिस तरह से वीडियो साझा किया- माना जा सकता है कि प्रोजेक्ट में वह भी एक अहम हिस्सा होंगी। वैसे सीक्वल पर पहले भी चर्चाएं सुनने को मिली हैं। इसके मुताबिक वासु की फिल्म में अक्षय और टाइगर को कास्ट किया जाना है। यह फिल्म अगले साल फ्लोर पर जाएगी। अली अब्बास जफर के फिल्म बनाने की चर्चा है। सूत्र तो यहां तक कह रहे कि फिल्म बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी एक्शन एंटरटेनर होगी। अक्षय-टाइगर की कास्टिंग को इसका सबूत भी माना जा सकता है। अक्षय पिछले साल वासु की स्पाई थ्रिलर बेलबॉटम में दिखे थे।

रीमेक का अंदाज अलग होगा... चर्चों और कास्टिंग के आधार पर देखें तो बड़े मियां छोटे मियां के रीमेक या सीक्वल में कई सारे बदलाव नजर आ सकते हैं। बड़े मियां छोटे मियां में कॉमेडी पर ज्यादा जोर था। हालांकि फिल्म में एक्शन और रोमांस का भी मसाला भरपूर था। अक्षय-टाइगर की कास्टिंग और सूत्रों के दावों से तो यही संकेत मिल रहे कि सीक्वल का मिजाज पुराना नहीं रहने वाला है।

बेकार गई तापसी पन्नू की मेहनत, लूप के लपेटे में फंसी रह गई फिल्म

बॉलीवुड में रीमेक फिल्में बनाने का चलन बहुत पुराना है। हॉलीवुड और साउथ सिनेमा की कई सफल फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाया जा चुका है। इनकी सफलता की दर को देखते हुए आने वाले समय में कई रीमेक फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। इन सबके बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म लूप लपेटा स्ट्रीम हो रही है, जो जर्मनी की क्लासिक कल्ट फिल्म लोला रेन्नट का हिंदी रीमेक है। इसकी कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। यही वजह है कि इसके हिंदी रीमेक के दौरान पटकथा लेखन की जिम्मेदारी एक भारी भरकम लेखन टीम को दी गई। जर्मन फिल्म की कहानी को भारतीय परिवेश में ढ़ालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सफल होते नहीं दिख रहे हैं। तापसी पन्नू ने इस फिल्म में खूब मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत बेकार चली गई। फिल्म के नाम के साथ ही पूरी फिल्म लूप के लपेटे में फंसी रह गई।

आलिया की अदाकारी का अलहदा अंदाज दिल जीत लेता है!

एक वक्त था, जब आलिया भट्ट को दिग्गज फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी के रूप में जाना जाता था। उनको स्टार किड्स की श्रेणी में रखकर लोग उनपर नेपोटिज्म का आरोप लगाते थे। यहां तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन उनको मजाक बनाया जाता था। उनके निक नेम आलू के बहाने उनके सामान्य ज्ञान की खिल्ली तक उड़ाई जाती थी। लेकिन आलिया ने कभी किसी पर पलटवार नहीं किया। उन्होंने हर बार अपनी मेहनत और दमदार अदाकारी के जरिए अपने आलोचकों को जवाब दिया है। इसी कड़ी में संजय लीला भंसाली की बहुप्रतिक्षित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसमें आलिया ने अपने कैरियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है। इसमें जिस तरह से उनका नाजो-अंदाज दिखा है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आलिया आला दर्जे की अभिनेत्री बन चुकी हैं। फिल्म में उनका जेस्चर काफी अपीलिंग है।

नेतागिरी का पंचनामा

शहर से बाहर, पक्की सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के सामने, एक अधपक्का बिल्डिंग के बाहर एक बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई थी। जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था- नेता बनने का हुनर सीखें!

मोदी जी भी अपने भाषणों में अक्सर कहा करते है- पकौड़ा तलना सीखें। पंचर बनाना सीखें। अचार बनाना सीखें, फटीचर बनना सीखें। मतलब कि कुछ भी बनना-बनाना सीखें! पंचर बनाना-पकौड़ा तलना वैसा ही एक हुनर है जैसे झूठ बोल और जूमले गढ़कर सत्ता हथिया लेना! हुनर के बिना आदमी का जीवन हुंडार सा हो जाता है!

सड़क किनारे के उस मकान के बाहर खड़ा मैं कुछ देर के लिए हुंडार की तरह ही सोचता रहा था। नेता बनने की बात है तो उसका फीस-फास भी बड़ा ही होगा। मैं इसी सोच में पड़ा था कि तभी मेरी नजर पुन: उसी होर्डिंग पर जा टिकी!

प्रवेश शुल्क-पांच हजार इक्कावन रुपए उस पर लिखा हुआ था।

मैं अंदर जाने की सोच ही रहा था कि बढ़ते कदम रुक से गए। फिर भी दरवाजे तक चला ही गया। दरवाजा खुला था। उस पर एक पर्दा झूल रहा था। उस पर ऊं लिखा हुआ था। दरवाजे के बगल में एक खिड़की थी। उसके दोनों पल्ले खुले हुए थे। मैंने अपनी गर्दन थोड़ी लंबी की- ऊंट की माफिक! फिर अंदर झांका। प्लास्टिक की आठ-दस कुर्सियां एक कतार से लगी हुई थीं। सभी के रंग लाल थे। एक दम बकरे की कलेजी जैसा। केवड़े की गंध से कमरा महक रहा था। क्रमबद्ध तरीके से चार लोग बैठे हुए थे। तभी कमरे में गेरूआ वस्त्र धारण किए एक अधेड़ ने प्रवेश किया। उम्र और चूल दाढ़ी से किसी बड़े आश्रम के फेंकू लग रहे थे। उठकर सभी ने उनका स्वागत किया। सीधे वो अपनी आसन पर विराजमान हुए तो बाकी भी बैठ गए थे।

पता चला। गेरूआ धारी का नाम स्वामी कालीदास है। बरसों जेल काटकर आया है। तब से नेता बनने का हुनर सीखें नाम का आश्रम खोल रखा है उसने।

आसन ग्रहण करते ही कालीदास ने क्लास शुरू की। पहले से पूछा- क्या नाम है?

कमल दास!

काम क्या करते हो?

ब्लॉक का बीडीओ हूं।

अच्छा माल बनाया होगा? और क्या करते हो?

लेखक भी हूं। कहानी कविताएं लिखता हूं!

यह सब कहां बिकता है? सरस सलिल में लिखते हो?

उसमें कभी लिखा नहीं है!

उसमें जल्द लिखना शुरू कर दो। उसी में लिखकर आज देश में कितने बड़े-बड़े लेखक-संपादक बन गए हैं। तुम भी लिखना शुरू कर दो। तुम्हारा नेता बनने का रास्ता वहीं से खुलेगा।

तुम क्या करते हो नौजवान? स्वामी ने दूसरे से पूछा था

कॉलेज स्टूडेंट हूं!

कॉलेज चुनाव कभी जीता है?

अभी तक तो नहीं स्वामी जी!

मारपीट के दोष पर कभी कॉलेज में दंडित हुए हो?

नहीं स्वामी जी!

गांजा चरस कोकिन पीते हो?

हां यह सब पीता हूं ...!

इन नशों में शामिल अब तक कितनी लड़कियों का बलात्कार किया है तुमने?

चार का!

और पिटे कितनी बार?

तीन बार...चौथी में भाग गया था। लड़के ने बताया

यहीं तुम मार खा गया! तुमको भागना नहीं चाहिए था, बल्कि पलटकर पीटना शुरू कर देना चाहिए था। डरने वाले को दुनिया डराती है, डरपोक मानती है लेकिन डराने वाले- मर्डर करने वाले को दुनिया सलाम करती है। देखो आज अहिंसावादी या तो आश्रमों में आसन लगाए बैठे हैं या फिर वजूद के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं!

उसी क्षण! उसी पल में! लगा कमरे में तूफान घुस आया हो-

स्वामी जी... स्वामी जी! कहता एक लंबा-चौड़ा गबरू सा जवान कमरे में आ घुसा था। खून से सने उसके दोनों हाथ! बदन पर लगे खून के दाग-धब्बे देख डर के मारे सभी उठ खड़े हो गए। पर स्वामी कालीदास मंद-मंद मुस्कुराते बैठे रहे!

शांत हो जाओ वत्स! शांत हो जाओ! स्वामी कालीदास ने आगंतुक से कहा था- तुम्हारा यह रूप बता रहा है कि जरूर कोई तगड़ा विरोधी रहा होगा। जिसे तू ठिकाने लगा कर आया है।

आप तो सबकुछ जानते हैं स्वामी जी! बरसों से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, न रहा बांस न बजेगी अब बांसुरी! अब आगे क्या करना है वो मुझे बताएं!

अपने समर्थकों-चाहने वालों को यहीं बुला लो। कुछ मालाएं भी मंगवा लो..!

ऐसा ही हुआ। दस मिनट में ही तीस चालीस की संख्या में आदमी पहुंच गए आश्रम में।

जाओ, जुलूस के शक्ल में जाकर थाने में सरेंडर कर दो। तुम्हारे भाग्य रेखा में, लोकसभा जाने का रास्ता वहीं से खुलेगा... गृहमंत्री का योग है.!

आंगतुक के गले में पहली माला डालते स्वामी कालीदास ने कहा था।

देश का भावी नेता-जबरलाल! जिंदाबाद..! जिंदाबाद!

● **श्यामल बिहारी महतो**

HEIDELBERGCEMENT
149 वर्षों का
अतुलनीय अनुभव
HEIDELBERGCEMENT
SINCE 1873
QUALITY ASSURANCE MARK
mycem cement
माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा ''सर्वोत्तम निर्माण के लिए'' उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।
क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..
माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए
सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका
For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री
उद्यम क्रांति योजना

मध्यप्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोज़गार के लिए बैंको के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण और ब्याज अनुदान सहायता

किन
परियोजनाओं के लिए

- रुपये 1 लाख से 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए।
- रुपये 1 लाख से 25 लाख तक सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय के लिए।

किसे
मिलेगी सहायता

- प्रदेश के 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के युवा।
- शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम 12वीं पास।
- परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो।

कितनी
मिलेगी सहायता

- वितरित किए जाने वाले ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरीयम अवधि सहित)।
- ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरीयम अवधि सहित)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश

msmedeptmp @minmpmsme

D-19507/21